



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 305]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 23, 2016/आश्विन 1, 1938

No. 305]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 23, 2016/ ASVINA 1, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2016

अंतिम जांच परिणाम

विषय: टर्की और रूस के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "सोडा ऐश" के आयातों से संबंधित पाटन-रोधी जांच की मध्यावधि समीक्षा (एमटीआर)।

सं.15/17/2015-डीजीएडी.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम भी कहा गया है) और सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि :

1. जबकि निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने टर्की और रूस (जिसे एतदपश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "सोडा ऐश" (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु, अथवा विचाराधीन उत्पाद अथवा डाइसोडियम कार्बोनेट कहा गया है) के आयातों से संबंधित निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए दिनांक 9 फरवरी, 2013 की अधिसूचना सं. 14/3/2011-डीजीएडी के द्वारा अपने अंतिम जांच परिणाम को अधिसूचित किया था। निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 18 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना सं. 08/2013/2012-सी.शु. (एडीडी) के द्वारा लगाया गया था।

2. जबकि, अखिल भारतीय ग्लास विनिर्माता संघ (ए आई जी एम एफ), संबद्ध वस्तुओं के आयातकों/प्रयोक्ताओं का एक प्रतिनिधि निकाय, जिसे एतदपश्चात आवेदक कहा गया है, ने इस नियमावली के नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क के अनुसार संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों की मध्यावधि समीक्षा शुरू करने के लिए अनुरोध करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने दावा किया है कि मूल जांच की अवधि के दौरान जो परिस्थितियां मौजूद थीं वह काफी हद तक बदल गई हैं जिसके फलस्वरूप एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां मौजूदा पाटनरोधी शुल्क अब आवश्यक नहीं रह गया है।

3. जबकि आवेदक ने यह कहा है कि संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है तथा घरेलू विक्री कीमतों में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है, तथा प्रमुख कच्चे माल की कीमतों में भी वृद्धि हुई है, लेकिन इन कीमतों में वृद्धि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की कीमतों में हुई वृद्धि के अनुपात में नहीं हुई है। आगे आवेदक ने यह कहा है कि आयात की कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि जिसके फलस्वरूप आयातों के पहुंच मूल्य में वृद्धि हुई है, के साथ-साथ क्षति मार्जिन में कमी आई है और इसके फलस्वरूप शुल्कों के वर्तमान स्तर की समीक्षा करने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है।

4. और जबकि इस अधिनियम की धारा 9 क के साथ पठित इस नियमावली का नियम 23 में यह अपेक्षा है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी जहां भी आवश्यक हो किसी हितबद्ध पक्षकार, जो ऐसी समीक्षा की आवश्यकता की पुष्टि करते हुए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करते हों, तथा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने के समय से उचित समयावधि समाप्त हो गई हो, द्वारा अपने स्वयं की पहल पर अथवा उनके अनुरोध पर कोई पाटनरोधी शुल्क को निरंतर लगाने की आवश्यकता की समीक्षा करेंगे और इस प्रकार की समीक्षा किए जाने पर निर्दिष्ट प्राधिकारी केन्द्र सरकार को इसे वापस लेने की सिफारिश करेंगे जहां वह इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि घरेलू उद्योग को लगातार क्षति होने या फिर से होने की संभावना उस स्थिति में नहीं है जब उक्त पाटनरोधी शुल्क को हटाया जाएगा अथवा उसमें परिवर्तन किया जाएगा और इसलिए अब इसकी आवश्यकता नहीं है।

5. आवेदक द्वारा ऐसी समीक्षा की आवश्यकता की पुष्टि करते हुए तथा बदली हुई परिस्थितियों को दर्शाते हुए, लागू उपाय की समीक्षा को जरूरी बताते हुए दी गई सूचना के संबंध में, प्राधिकारी ने दिनांक 1 अक्टूबर, 2015 की अधिसूचना सं. 15/17/2015-डी जी ए डी की अधिसूचना के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1 खंड 1 में प्रकाशित दिनांक 9 फरवरी, 2013 की अधिसूचना सं. 14/3/2011-डी जी ए डी के द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणाम की मौजूदा मध्यावधि समीक्षा (एमटीआर) की जांच तथा केन्द्र सरकार द्वारा पाटनरोधी शुल्कों को लगातार लगाए रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए दिनांक 18 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना सं. 08/2013-सी.शु. (एडीडी) के द्वारा लगाए गए निश्चयात्मक शुल्क की जांच शुरू की है।

6. पूर्व में दिनांक 21 जुलाई, 2015 की अधिसूचना सं. 15/28/2014-डीजीएडी के द्वारा, प्राधिकारी ने उसी जांच की अवधि के लिए एक अन्य एमटीआर जांच शुरू की थी जिसमें चीन जन.गण., ईयू, कीनिया, पाकिस्तान, ईरान, यूक्रेन और यूएसए में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में उसी घरेलू उद्योग को शामिल किया गया था।

ख. प्रक्रिया

7. जांच के संबंध नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन में किया गया है :

i. प्राधिकारी ने उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में संबद्ध देशों से दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों तथा घरेलू उत्पादकों को दिनांक 1 अक्टूबर, 2015 के जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना की प्रतियां भेजी। ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करें तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने दृष्टिकोण से अवगत कराएं।

ii. निर्यातकों को भेजे गए पत्र एवं प्रश्नावलियों की प्रतियां इस अनुरोध के साथ ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की एक सूची सहित संबद्ध देशों के दूतावासों को भी भेजी गई थी कि वे निर्धारित समय के भीतर संबद्ध देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को उत्तर देने की सलाह दें।

iii. आवेदक की ओर से दायर किए गए आवेदन के अगोपनीय पाठ की प्रति पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार संबद्ध देशों के दूतावासों, ज्ञात निर्यातकों और घरेलू उत्पादकों को उपलब्ध कराई गई थी।

iv. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को एमटीआर शुरू करने से संबंधित सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अग्रेषित की और उन्हें नियमावली के नियम 6(2) और 6(4) के अनुसार इस पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 40 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने दृष्टिकोण से अवगत कराने के लिए अवसर दिया।

सोडा सानयी ए.एस. टर्की टर्कीयेसीसे वीई कैम फाबरीकलारी ए.एस. आईएस कूलेलेरी, कूले-3343304, लेवेंट इस्तनाबुल टर्की
ईटीआई सोडा, साइनर ग्रुप, पसलीमनी कैड नं. 4, उस्कूदर 34674, इस्तनाबुल टर्कीए
सास सोडा ऐश सेल्स एंड सर्विसेज

- | |
|--|
| एम तोलमाचेवस्कीए पीईआर, 10 कार्यालय, 7,8119017
मास्को, रूस
जेएससी वास्कीरियन कैमिस्ट्री
8,बी पालूयारोस्लैवसीयेपेरूलोक, मास्को, 105 120, रूस |
|--|
- v. संबद्ध जांच के शुरू किए जाने के प्रत्युत्तर में, टर्की के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर दायर कर जवाब दिया है और निम्नलिखित अनुरोध किया है :
1. सोडा सनाई ए.एस.
 2. ईटीआई सोडा
- vi. भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली भेजी गई थी ।

गुजरात गार्जियन लिमिटेड, गांव- कौंध, वालिया रोड, प्लांट स्टेट हाइवे नं.13, अंकलेश्वर, बहराइच-393001
फ्लोट ग्लास इंडिया लिमिटेड., टी-7, एमआईडीसी, इंडस्ट्रियल एरिया, तलोजा, महाराष्ट्र
हिंदुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंड.लि., रिशरा, वेस्ट बंगाल
प्रोटेक्टर एंड गेम्बल हाइजेनिक एंड हेल्थ केयर, मंडीदीप प्लांट एल एंड सी-एमएफजी, प्लांट नं.182, मंडीदीप, मध्य प्रदेश
एडवॉंज इंडस्ट्रीज प्रा.लि., धनाली, गांव-धनाली, एट-कादी, जिला-मेहसाना, गुजरात
यू.पी. ग्लास मैन्युफैक्चरर, सिंडीकेट, 14-मोनापुरम, नजदीक-गणेश नगर, फिरोजाबाद- 283203, उ.प्र.
फेना (प्रा.) लि., ए-237, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-20
पोलाची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आरपी कॉम्पलैक्स, दूसरा तल, 14, बालागोपालापुरम स्ट्रीट, पोलाची-642001
पावर शॉप लिमिटेड, 62-बी, नार्थ बोग रोड, टी. नगर, चेन्नई – 600017
एलेम्बिक ग्लास इंडस्ट्रीज लि0, एलेम्बिक रोड, बडौदा (वदोदरा) गुजरात
दीपक नाइट्राइट लि0, 4/12, कैमिकल कॉम्पलैक्स, जीआईडीसी, नानफेशारी, बडौदा (वदोदरा) गुजरात
हिंदुस्तान यूनीलिव लि0, पार्टी एट्रेस दक्षिणा बिल्डिंग, 8वां तल, प्लांट नं.2, सैक्टर-11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई
अल्ब्राइट मोरारजी एंड पंडित लि0, अंबरनाथा, जिला-थाणे, महाराष्ट्र
साइलेंड-गोबेन ग्लास इंडिया, मुख्यालय तथा संयंत्र: ए-1, एसआईपीसीओटी इंडस्ट्रियल पार्क, श्रीपेरम्बदूर - 602105, कांचीपुरम जिला- तमिलनाडु
असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड., 5वां तल, टावर-बी, ग्लोबल बिजनेस पार्क, महरोली-गुडगांव रोड, गुडगांव-122002(भारत)
श्री यूनियन आर्गेनिक्स प्रा0 लि0, बीएस-3, एपेजय. 130, बॉम्बे समाचार मार्ग, मुंबई-23
वसुंधरा रेसयान लि0, सी-104, एमआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, माहेड, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र
सहायनाथ डिटरजेंट्स प्रा0 लि0, पी-15, कालाकर स्ट्रीट, कोलकाता -700007
एडवांस होम एंड पर्सनल केयर लि0, एडवांस सरफेक्टेंट्स इंडिया लि0, 511/2/1, गांव राजोरकी, नई दिल्ली-38
एस कुमार डिटरजेंट प्रा0 लि0, प्लांट नं0.34, सेक्टर-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पीतमपुर-454775 जिला-धर, म0 प्र0.
हिंद सिलीकेट्स प्रा0 लि0, 3ए, अकलैंड प्लेस, 5वां तल, कोलकाता-17
पी एंड जे क्रीटैकचैम (प्रा0) लि0, 318, स्वप्नलोक, 92/93, एस डी रोड, सिकंदराबाद-500003, आ.प्र., भारत
जे.जे.पटेल इंडस्ट्रीज, गोंडल रोड, बी/एच, राजकमल पेट्रोल पंप, वावदी, राजकोट-360004
मॉर्डन ग्लास इंडस्ट्रीज, कोल सिडिंग रोड, एस.एन.रोड, फिरोजाबाद- -283203
संदीप आर्गेनिक प्रा.लि., 104, नैन कृपा, 118/122, काजी सैय्यद स्ट्रीट, मस्जिद बंडर (वेस्ट), वडागी, मुंबई -400003
एलेबिक ग्लास इंडस्ट्रीज लि0, एलेबिक रोड, बडौदा (वदोदरा) गुजरात

रोहित सरफेकटेंस (प्रा0) लि0., 117/एच-2/202, पंडूनगर, कानपुर-05
बीडीजे ग्लास इंडस्ट्रीज प्रा0 लि0, 1, केवाईडी स्ट्रीट, प्लेस कोर्ट, पहली मंजिल, सूइट-14-ए, कोलकाता- 700016
जगतीत इंडस्ट्रीज लि0, प्लॉट नं. 78, सेक्टर-78, इंडस्ट्रियल एरिया, गुडगांव-122001
हल्दयान ग्लास गुजरात लि0, 9 गायत्री कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स, मित्तल इंडस्ट्रियल इस्टेट नं0 5 के पीछे, अंधेरी कुर्ला रोड, मोरल नाका, अंधेरी (ईस्ट), मुंबई- 400059
हिपोलिन लिमिटेड, मधुबन, चौथा तल, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद- -380006
मॉडर्न ग्लास इंडस्ट्रीज, कोल साइडिंग रोड, एस एन रोड, फिरोजाबाद-283203
डिटरजेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, (दिल्ली क्षेत्र) 148, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल कॉम्पलैक्स-1, नई दिल्ली-110020
मौली एक्सपोर्ट्स, प्लॉट नं.97-98, सेक्टर – 25, पार्ट-II, इंडस्ट्रियल एरिया, हुडा, पानीपत – 132 104, हरियाणा
मै0 चैम्पैक्स इंडस्ट्रियल, 393/III/6 बाजेर, कीकानेरियान, कटरा, अहलुवालिया, अमृतसर, पंजाब
टाटा कैमिकल्स लि0., लीला बिजनेस पार्क, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुंबई -59
मै0 तूतीकोरिन अल्कली कैमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लि0, 534, अन्ना सलाई, टेनापेट, चेन्नई -18
एजीआई ग्लास पैक, ग्लास फैक्टरी रोड, मोती नगर, पो.बा.1930, संत नगर, हैदराबाद – 500 018
पावर शॉप्स लि0., ए-8, 1 मेन रोड, अम्बाला इंडस्ट्रियल इस्टेट, चेन्नई- 600 058
हिंदुस्तान (प्रा0) लि9, 62/बी, ब्राउनफील्ड रो, पहला तल, कोलकाता- 700 027
एम्पायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड., एम्पायर हाउस, 414, सेनापति बापर, लोअर पारेल, मुंबई – 13

vii. उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में, निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने आयातक की प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है और निम्नलिखित अनुरोध किया है :

- क. गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड
 ख. गुजरात बोरोसिल लिमिटेड
 ग. एचएनजी फ्लोट ग्लास लिमिटेड
 घ. एचएसआईएल लिमिटेड, पैकेंजिंग प्रोडक्ट्स डिविजन
 ड. ला ओपाला आरजी लिमिटेड,
 च. पिरामल ग्लास लिमिटेड

viii. भारत में संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात घरेलू उत्पादकों को भी आवश्यक सूचना और उत्तर के लिए प्रश्नावली भेजी गई थी।

मै0 डीसीडब्ल्यू लि0
मै0 जीएचसीएल लि0
मै0 निरमा लि0
मै0 सौराष्ट्र कैमिकल्स लि0
टाटा कैमिकल्स लि0

ix. निम्नलिखित संघों को भी जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना भेजी गई थी :

डिटरजेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
इंडियन कैमिकल मार्चेन्ट्स एंड मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
बल्स ड्रग मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (भारत)
इंडियन ग्लास मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन

दि डायर्स एंड कैमिकल मर्चेन्ट्स एसोसिएशन
ऑल इंडिया ग्लास मैनुफैक्चरर्स फेडरेशन
अल्कली मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
इंडियन शॉप एंड टोइलेटरीज मेकर्स एसोसिएशन

- x. उत्तर देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों/प्रयोक्ताओं, घरेलू उत्पादकों और उनके प्रतिनिधियों के अलावा, निम्नलिखित पक्षकारों ने भी इस जांच के दौरान निम्नलिखित ने अनुरोध किए :
- i. डिटरजेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
 - ii. डिटरजेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (दिल्ली क्षेत्र)
 - iii. बंगाल शॉप्स एंड डिटरजेंट मैनुफैक्चरर्स वेलफेयर एसोसिएशन
 - iv. इंडियन होम एंड पर्सनल केयर इंडस्ट्री एसोसिएशन,
 - v. हिंदुस्तान यूनीलीवर लि०
 - vi. संदीप आर्गेनिक लि०
 - vii. आरएसपीएल लि०
 - viii. अशोका एनेमल एंड ग्लास वर्क्स प्रा० लि०
 - ix. इंडियन काउंसिल ऑफ स्माल इंडस्ट्रीज
 - x. ऑल इंडिया ग्लास मैनुफैक्चरर्स फेडरेशन
 - xi. सेनित गोविन ग्लास इंडिया लि०
 - xii. मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ रसियन फेडरेशन
 - xiii. टर्की जन.गण. का दूतावास
 - xi. निर्यातकों, उत्पादकों और अन्य हितवद्ध पक्षकारों जिन्होंने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है और न ही इस जांच से संगत सूचना भेजी है, को असहयोगी हितवद्ध पक्षकारों के रूप में माना गया है।
 - xii. जांच की अवधि सहित पिछले तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के व्यौरे की व्यवस्था करने हेतु वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से अनुरोध किया गया था। इसलिए प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा की गणना तथा अपेक्षित विश्लेषण के लिए डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों को स्वीकार किया है।
 - xiii. सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांत (जी ए ए पी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं का निर्माण करने तथा उसे बेचने की लागत और उत्पादन की आदर्शतम लागत की गणना इस तथ्य की जांच करने के लिए इस प्रकार से की गई है कि क्या पाटनरोधी शुल्क पाटन मार्जिन से कम है और यह घरेलू उद्योग को क्षति से बचाने के लिए पर्याप्त होगा। एनआईपी का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अंतर्गत निर्धारित सिद्धांतों के संबंध में किया गया है।
 - xiv. जांच 1 अप्रैल, 2014 से शुरू करते हुए 31 मार्च, 2015 की अवधि (पीओआई) तक की गई थी, हालांकि क्षति की जांच 2011-12, 2012-13, 2013-14 और जांच की अवधि के लिए की गई थी। प्राधिकारी ने संभावना का विश्लेषण करने के लिए जांच की अवधि के पश्चात (1 अप्रैल, 2015 से 30 सितंबर, 2015) के लिए हितवद्ध पक्षकारों से संगत सूचना/आंकड़े भी उपलब्ध कराने के लिए कहा।
 - xv. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने 01 मार्च, 2016 को संपन्न सार्वजनिक सुनवाई में हितवद्ध पक्षकारों को अपने दृष्टिकोण मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए भी अवसर दिया। उन पक्षकारों, जिन्होंने दोनों मौखिक सुनवाई में अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए, से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से अभिव्यक्त दृष्टिकोणों को लिखित रूप में प्रस्तुत करें और तत्पश्चात अलग से अनुरोध करें।
 - xvi. जांच की अवधि के दौरान हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध पर प्राधिकारी द्वारा जहां भी संगत पाया गया, इस जांच परिणाम में विचार किया गया है। जिस सीमा तक सत्यापन को आवश्यक माना गया, उसे घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं आंकड़ों के संबंध में किया गया था।

- xvii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक माना गया, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना पर गोपनीय के रूप में विचार किया गया है तथा इसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रस्तुत करें।
- xviii. जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने सूचना देने से इंकार किया है अथवा वर्तमान जांच की अवधि के दौरान अन्य प्रकार से आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की है अथवा इस जांच में पर्याप्त रूप से बाधा पहुंचाई है, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अंतिम जांच परिणाम को दर्ज किया है।
- xix. *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना और इस नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उस पर किए गए विचार का द्योतक है।
- xx. इस जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा जांच की अवधि के दौरान 1 अमरीकी डॉलर = 61.69 रूपए की प्रचलित औसत विनिमय दर को माना गया है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

8. मूल जांच तथा वर्तमान समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) "सोडा ऐश" है। मूल जांच में उत्पाद की परिभाषा नीचे दिए गए अनुसार थी :-

- i. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद डाइसोडियम कार्बोनेट है जिसे कैमिकल फार्मूला एनए2 सीओ3 वाले सोडा ऐश के रूप में भी जाना जाता है। सोडा ऐश का उत्पादन दो रूपों में अर्थात् लाइट सोडा ऐश और डेंश सोडा ऐश में किया जाता है। दोनों प्रकारों में अंतर बहुत अधिक घनत्व के कारण है। इसका उत्पादन सिंथेटिक रूट और प्राकृतिक रूट जिसे विलय प्रक्रिया भी कहा जाता है, के माध्यम से किया जाता है। वर्तमान जांच में सोडा ऐश के सभी प्रकार और रूप शामिल हैं।
- ii. सोडा ऐश डिटरजेंट्स, साबुन, सफाई करने वाले पदार्थों, सोडियम आधारित कैमिकल्स, फ्लोट ग्लास, कंटेनर और स्पेशियलिटी ग्लासेज, सिलिकेट्स और अन्य औद्योगिक कैमिकल्स के निर्माण में एक प्रमुख तत्व है। इसका व्यापक रूप से उपयोग टैक्सटाइल्स, पेपर, मैटलर्जिकल इंडस्ट्रीज और डिसेलिनेशन प्लांट्स में भी किया जाता है। सोडा ऐश का वर्गीकरण उप-शीर्ष संख्या 2836.20 के अंतर्गत सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 28 के अंतर्गत किया गया है। हालांकि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।"

9. किसी भी आयातक, उपभोक्ता, निर्यातक, घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में कोई टिप्पणी अथवा अनुरोध नहीं किया है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि उनका विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में कोई मुद्दा नहीं है। उपर्युक्त को देखते हुए वर्तमान समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही है जो मूल जांच में था।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

याचिकाकर्ता तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

10. आवेदक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग का आधार और क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- i. संबंधित घरेलू उत्पादक जो घरेलू उद्योग के रूप में अपने आप को होने का दावा करते हैं, स्वयं संबंध देशों से संबद्ध वस्तुओं के बड़े आयातक हैं। कुछ घरेलू उत्पादकों का पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों ने भी भारत में संबद्ध वस्तुओं का बहुत अधिक मात्रा में निर्यात किया है। घरेलू उत्पादकों ने स्पष्ट रूप से माना है कि दक्षिणी और पूर्वी भारत के ग्राहकों को आपूर्ति करने के लिए वे प्रमुख रूप से आयात पर निर्भर कर रहे हैं। इस कारण से ऐसे घरेलू उत्पादक पाटनरोधी नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग बनने के लिए पात्र नहीं हैं।
- ii. सबसे बड़े भारतीय घरेलू उत्पादक "टाटा कैमिकल्स लिमिटेड" ने कीनिया से अपनी सहायक कंपनी से तथा ई यू और चीन से असंबंधित उत्पादकों से इस सामग्री का आयात किया।
- iii. निरमा ने अन्य देशों में पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों का अधिग्रहण किया है और यह उन कंपनियों से संबद्ध वस्तुओं का आयात कर रहा है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या आयात की निम्न कीमत की क्षतिपूर्ति निरमा द्वारा प्राप्त कीमत से की गई है।
- iv. जीएचसीएल भी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों से आयात कर रही है। जीएचसीएल का 87 प्रतिशत से अधिक क्षमता उपयोग इस जांच की अवधि के दौरान हुआ है जो इन उद्योगों के लिए सबसे अधिक है। जीएचसीएल 850000 मी.ट. की क्षमता के साथ एक बड़ा उत्पादक है और इसकी संबद्ध देशों सहित विभिन्न देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात करना मजबूरी है। वे संबद्ध वस्तुओं का आयात करते समय पाटनरोधी शुल्क का भुगतान कर रहे हैं तथा उसके बावजूद उन्हें लाभ हो रहा है।

- v. सौराष्ट्र कैमिकल्स लिमिटेड (एससीएल) पहले से ही निरमा के साथ मिला हुआ है और यह कानूनी प्रतिष्ठान/कंपनी के रूप में नहीं है।
- vi. तूतीकोरिन अल्कली कैमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड सबसे छोटा है और उत्पादन के मामले में घरेलू उत्पादकों में सबसे कमजोर सदस्य है। यह कच्चे माल सीओ₂ की उपलब्धता न होने के कारण बार-बार अपने उत्पादन को रोकता है।
- vii. केवल डीसीडब्ल्यू एक छोटी कंपनी है जिसकी क्षमता प्रतिवर्ष लगभग 300000 मी.ट. है। यह इस क्षमता का उपयोग उच्चतर दर पर कर रहा है और यह लाभ अर्जित कर रहा है। ऐसी कंपनी किसी प्रकार के लगातार संरक्षण की हकदार नहीं है।
- viii. न तो तथाकथित घरेलू उद्योग और न ही प्राधिकारी ने यह स्पष्ट किया है कि कौन से घरेलू उत्पादक मौखिक सुनवाई किए जाने के पूर्व पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के संबंध में घरेलू उद्योग हो सकते हैं।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

11. घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू उद्योग के आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

- i. जीएचसीएल और टाटा कैमिकल्स को छोड़कर किसी भी कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान संबंध वस्तुओं का स्वयं आयात किया है।
- ii. जीएचसीएल द्वारा आयात उस स्थिति में निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से बाजार में अपनी उपस्थिति बनाए रखने तक थी जब बड़ी हुई क्षमताएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
- iii. जी एच सी एल रोमानिया में एक संबंधित कंपनी थी, जिसे अब बंद कर दिया गया है। निरमा का यूएसए में एक संबंधित उत्पादक है जिसने जांच की अवधि के दौरान भारत में सोडा ऐश का निर्यात किया है। हालांकि निर्यात कंपनी द्वारा सीधे किया गया है।
- iv. डी सी डब्ल्यू का भारत से बाहर कोई संबंधित उत्पादक-निर्यातक नहीं है।
- v. टाटा कैमिकल्स का कीनिया, अमरीका और यूरोप में एक संबंधित उत्पादक है। कीनिया की कंपनी टाटा कैमिकल्स की एक सहायक कंपनी है जिसने भारत में वस्तुओं का निर्यात किया है। ये निर्यात टाटा कैमिकल्स द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर किए गए हैं। यदि इसे उचित माना जाए तो टीसीएल को अपात्र घरेलू उद्योग के रूप में माना जा सकता है।
- vi. घरेलू उद्योग द्वारा आयातों के अनेक कारण हैं। सर्वप्रथम अवतरित कीमत उस कीमत से बहुत कम है जिस पर घरेलू उत्पादक इन क्षेत्रों में दे सकते हैं। दूसरे, क्षमताओं का निकट भविष्य में विस्तार के लिए मांग का पूर्व सृजन आवश्यक है जो इन उपभोक्ताओं को आयातित उत्पाद की आपूर्ति करते हुए किया जा रहा है। तीसरे, इन आयातों पर बहुत मामूली लाभ अर्जित किया गया है। चौथा, शुल्कों की सिफारिश भाड़े को शामिल किए बिना की गई थी, जिसे उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए शामिल किया जाना चाहिए था।
- vii. पाटनरोधी शुल्क बिना किसी भेदभाव के आधार पर होता है और यदि घरेलू उत्पादकों ने विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है, तब उन्होंने लागू पाटनरोधी शुल्क का भुगतान किया है।
- viii. जहां तक सुनवाई का प्रभावी न होने का संबंध है, यह आवेदक आयातक संघ के लिए आवश्यक था कि वह घरेलू उद्योग की पहचान करे और तत्पश्चात किसी प्रकार की क्षति और उसमें किसी प्रकार की संभावना न होने को सिद्ध करे।
- ix. निरमा की क्षमता जिसे दर्शाया गया है, एससीएल की क्षमता को शामिल करने के बाद है। एस सी एल क्षति की अवधि के प्रारंभ में एक अलग प्रतिष्ठान था और बाद में इसका विलय निरमा में हो गया। निरमा की सूचना में एससीएल की सूचना शामिल है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

12. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) को नीचे दिए गए अनुसार पढ़ा जाए:

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं

अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

13. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में प्रावधान है कि घरेलू उत्पादक जो निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हैं, अथवा जो स्वयं कथित रूप से पाटित वस्तुओं के आयातक हैं, को कुछ परिस्थितियों में घरेलू उद्योग का निर्धारण करते समय बाहर रखा जा सकता है। प्राधिकारी का यह सुविचारित मत है कि नियम 2 (ख) में शब्द 'किया जा सकता है' के उपयोग का यह मतलब है कि प्रश्नगत उत्पादकों के दो प्रकार अर्थात् संबंधित उत्पादक और वे उत्पादक जो पाटित उत्पाद का आयात कर रहे हैं, घरेलू उद्योग का हिस्सा बनने से स्वतः बाहर नहीं हो सकते हैं। इसके विपरीत यह एक सतत प्रथा रही है कि ऐसे उत्पादकों को बाहर करने के संबंध में निर्णय उचित और न्यायपरक आधारों पर मामला दर मामला आधार पर तथा इसमें शामिल सभी कानूनी और आर्थिक पहलुओं पर विचार करने के बाद किया जाना चाहिए।

14. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल जांच में भी घरेलू उद्योगों को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में शामिल किया गया था और वे संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों/आयातकों से संबंधित थे। मूल जांच अंतिम जांच परिणाम में, प्राधिकारी ने नीचे दिए गए अनुसार, नोट किया था :-

" 49. प्राधिकारी का विचार है कि घरेलू उत्पादक जो पाटित वस्तुओं का मामूली मात्रा में आयात करते हैं और जिनके संबंधित निर्यातक पाटित वस्तुओं का निर्यात करते हैं अथवा जिनके संबंधित आयातक पाटित वस्तुओं का आयात करते हैं, उस स्थिति में पाटन प्रथाओं से अनुचित रूप से लाभ नहीं प्राप्त करते हैं, यदि ये आयात उनके बिक्री अथवा बाजार के आकार का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं होते हों। वास्तव में ऐसे घरेलू उत्पादकों को बाजार में अन्य आपूर्तिकर्ताओं से प्रतिस्पर्धा के कारण कोई लाभ नहीं होता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि इसके बारे में निर्णय लेते समय कि क्या किसी घरेलू उत्पादकों को बाहर रखा जाना चाहिए, अन्य देशों के जांच प्राधिकारियों द्वारा किया गया एक अन्य अंतर यह है : क्या घरेलू उत्पादक केवल कुछ पाटित आयातों के साथ अपना घरेलू उत्पादन को पूरा कर रहे हैं अथवा क्या यह प्राथमिक रूप से अपेक्षाकृत सीमित उत्पादन के साथ एक अयातक हैं ? प्राधिकारी का यह विचार है कि बाद के मामले में इस प्रकार की कंपनी को घरेलू उद्योग के क्षेत्र से बाहर किया जाना चाहिए। एक अन्य कारण जिस पर विचार किया जा सकता है, वह यह है कि क्या प्रश्नगत घरेलू उत्पादक आयातों के देश में उत्पादन करते हैं या नहीं।

50. उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि निर्धारण के लिए एकमात्र संगत विषय यह है कि क्या जीएचसीएल, निरमा, एससीएल और टाटा कैमिकल्स को पात्र घरेलू उद्योग के रूप में माना जाना चाहिए या नहीं। वर्तमान मामले में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि कोई भी घरेलू उत्पादक किसी आयातक से संबंधित हैं। हितबद्ध पक्षकारों का तर्क यह है कि एससीएल, निरमा और जीएचसीएल को संबद्ध देशों में विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों के साथ उनके संबंध को देखते हुए अथवा निरमा के मामले में निरमा द्वारा किए गए आयातों के कारण अतिरिक्त रूप से अपात्र घरेलू उद्योग के रूप में माना जाना चाहिए या नहीं।

51. प्राधिकारी ने वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर उपर्युक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए आवेदक कंपनियों की पात्रता के मुद्दे की जांच की है। जहां तक आवेदक कंपनियों के संबंध और पात्रता के मुद्दे का संबंध है, वर्तमान मामले के तथ्य नीचे दिए गए हैं :-

- i. यह आवेदन अल्कली मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ए एम ए आई) द्वारा दायर किया गया है। ए एम ए आई कॉस्टिक सोडा (क्लोरीन सहित) और सोडा ऐश के उत्पादकों का एक संघ है।
- ii. डी सी डब्ल्यू, जी एच सी एल, निरमा और सौकेम ने घरेलू उद्योग को क्षति से संगत सूचना उपलब्ध कराई है और वर्तमान जांच के प्रयोजन से "घरेलू उद्योग" के रूप में विचार किए जाने के लिए अनुरोध किया है। इन कंपनियों को "भाग लेने वाली कंपनियां" के रूप में माना जा रहा है। इस याचिका को टाटा कैमिकल्स को छोड़कर जांच की अवधि के दौरान सोडा ऐश के सभी भारतीय उत्पादकों का समर्थन प्राप्त है। टाटा कैमिकल्स ने न तो पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का समर्थन किया है और न ही इसका विरोध किया है। हालांकि यह नोट किया गया है कि मगदी सोडा कंपनी, कीनियां, (इसका नाम टाटा कैमिकल्स मगदी लिमिटेड के रूप में उल्लेख किया गया है) टाटा कैमिकल्स की एक 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है और यह कंपनी निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर दायर कर वर्तमान जांच में भाग ले रही है।
- iii. जांच शुरू किए जाने के बाद और पहली मौखिक सुनवाई आयोजित किए जाने के बाद तूतीकोरिन अल्कली कैमिकल्स (टी ए सी) ने इस आवेदन का समर्थन करते हुए तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी को पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए अनुरोध करते हुए दिनांक 23 मई, 2011 के अपने पत्र के द्वारा अपना लिखित अनुरोध दायर किया है। यह नोट किया जाता है कि टी ए सी ने जांच की शुरुआत से संबंधित अधिसूचना का उत्तर देकर कार्यवाही में भाग नहीं लिया है। यह भी नोट किया जाता है कि वे जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर रहे थे। इस कारण से प्राधिकारी से इस विलंबित चरण में टीएसी के अनुरोधों पर विचार नहीं किया है।

- iv. कोई भी याचिकाकर्ता कंपनी भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातकों से संबंधित नहीं है।
- v. डीसीडब्ल्यू लिमिटेड का भारत के बाहर कोई संबंधित उत्पादक-निर्यातक नहीं है। कंपनी ने विचाराधीन उत्पाद का न तो आयात किया है और न ही कंपनी किसी निर्यातक अथवा आयातक से संबंधित है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि डी सी डब्ल्यू एक पात्र घरेलू उत्पादक है जो 'घरेलू उद्योग' का हिस्सा है। याचिकाकर्ता ने इस तर्क को जोरदार तरीके से रखा है कि उस स्थिति में जब प्राधिकारी यह मानते हैं कि जीएचसीएल, निरमा और एससीएल पात्र घरेलू उद्योग नहीं हैं, केवल डीसीडब्ल्यू घरेलू उद्योग का हिस्सा होगा, क्योंकि उस स्थिति में कंपनी का उत्पादन "घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन" का 100 प्रतिशत होगा।
- vi. एस सी एल और निरमा निर्विवाद रूप से संबंधित कंपनी है।
- vii. निरमा ने यूएसए में अपने संबंधित आपूर्तिकर्ता से सोडा ऐश का आयात किया है। निरमा को छोड़कर किसी भी याचिकाकर्ता कंपनी ने समग्र क्षति की अवधि के दौरान किसी भी संबद्ध देशों से इस सामग्री का स्वयं आयात नहीं किया है।
- viii. जीएचसीएल की एक संबंधित कंपनी रोमानिया में है जिसका नाम एससी जी एच सी एल उपसम है। जी एच सी एल का संबंधित निर्यातक ने वर्तमान क्षति की अवधि के दौरान भारत में सोडा ऐश का निर्यात किया है। जीएचसीएल ने भी भारत में उत्पादन और निर्यात के संबंध में रोमानिया में अपनी संबंधित कंपनी का ब्यौरा उपलब्ध कराया है। क्षति की अवधि के दौरान संबंधित निर्यातक द्वारा किए गए निर्यात के ब्यौरे दर्शाते हैं कि : (क) इन निर्यातों को प्रत्यक्ष रूप से रोमानिया की कंपनी द्वारा जांच की अवधि के दौरान असंबंधित भारतीय ग्राहकों को किया गया है और (ख) कंपनी द्वारा किए गए निर्यात की मात्रा में जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक गिरावट आई है। नीचे दी गई तालिका में यह दर्शाया गया है कि रोमानिया से निर्यात, जी एच सी एल उपसम द्वारा किए गए निर्यात की मात्रा कितनी है और अन्य संगत ब्यौरे क्या हैं।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
क	(क) एस सी जी एच सी एल उपसम द्वारा निर्यात	मी.ट.	17,356	51,353	6,489	4,101
ख	संबंधित पक्षकारों को निर्यात	मी.ट.	11,082	-	-	-
ग	असंबंधित भारतीय पक्षकारों को निर्यात	मी.ट.	6,274	51,353	6,489	4,101
घ	(ख) रोमानिया से कुल आयात	मी.ट.	46,594	67,121	7,652	47,148

2	निम्नलिखित की तुलना में एस सी जी एच सी एल उपसम द्वारा किया गया निर्यात	मी.ट.	17,356	51,353	6,489	4,101
क	भारतीय उत्पादन		0.85%	2.54%	0.32%	0.20%
ख	भारतीय खपत		0.80%	2.33%	0.29%	0.17%
ग	जीएचसीएल का उत्पादन		3.31%	8.68%	1.05%	0.61%
घ	निम्नलिखित की तुलना में जीएचसीएल द्वारा किया गया आयात					
क	जीएचसीएल का उत्पादन		2.11%	0.00%	0.00%	0.00%
ख	भारतीय उत्पादन		0.54%	0.00%	0.00%	0.00%
ग	भारतीय खपत		0.51%	0.00%	0.00%	0.00%

3	रोमानिया से सकल आयात	मी.ट.	46,594	67,121	7,652	47,148
क	• जी एच सी एल उपसम द्वारा निर्यात	मी.ट.	17,356	51,353	6,489	4,101
ख	• अन्य निर्यातकों द्वारा निर्यात	मी.ट.	29,238	15,768	1,163	43,047
ग	रोमानिया से कुल निर्यात में जीएचसीएल उपसम का हिस्सा		37.25%	76.51%	84.80%	8.70%

52. प्राधिकारी यह मानते हैं कि :

- i. जीएचसीएल उपसम रोमानिया से सोडा ऐश का बहुत बड़ा निर्यातक नहीं है। रोमानिया से अन्य निर्यातक रोमानिया से अधिक मात्रा में निर्यात करते हैं।
- ii. जी एच सी एल उपसम द्वारा किए गए निर्यात में पूर्ण रूप से तथा रोमानिया से आयात के संबंध में भी बहुत अधिक गिरावट आई है।
- iii. जी एच सी एल उपसम द्वारा किए गए निर्यात बहुत मामूली हैं जब उसकी तुलना भारत में सोडा ऐश के कुल आयातों, जी एच सी एल द्वारा सोडा ऐश के उत्पादन और भारत में सोडा ऐश की खपत से की जाए।
- iv. ये आयात जी एच सी एल, भारत द्वारा नहीं किए गए थे। इन आयातों को सीधे असंबंधित उपभोक्ताओं द्वारा किया गया था।
- v. जी एच सी एल उपसम द्वारा किए गए निर्यात की मात्रा उतनी अधिक नहीं है कि यह घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाती हो अथवा उससे क्षति हो सकती हो।
- vi. जी एच सी एल का ध्यान लगातार उत्पादन पर है। कंपनी व्यापारी नहीं बनी है और न ही कंपनी को पाटन से कोई अनुचित लाभ हुआ है। वास्तव में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अर्थ यह होगा कि जी एच सी एल उपसम द्वारा किए गए निर्यातों पर भी पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है। क्षति का निर्धारण जी एच सी एल को घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र के भीतर शामिल करने से परिवर्तित नहीं हो जाएगा।
- vii. विरोध करने वाले हितबद्ध पक्षकारों में से किसी ने जी एच सी एल को घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र से बाहर करने के लिए अपने संबंध के तथ्य को छोड़कर कोई औचित्य नहीं दिया है।

53. एस सी एल और निरमा का यू एस ए में संबंधित उत्पादक है जिसका नाम सर्लस वैली मिनरल्स है। क्षति की अवधि के दौरान संबंधित निर्यातक द्वारा किए गए निर्यातों का विवरण दर्शाता है कि (क) इन निर्यातों को जांच की अवधि के दौरान ही किया गया है, (ख) ये निर्यात निरमा को किए गए हैं, (ग) निरमा ने इस सामग्री का उपयोग स्वयं की खपत के लिए किया है। नीचे दी गई तालिका यूएस से निर्यात की मात्रा, सर्लस वैली मिनरल्स द्वारा किया गया निर्यात (निरमा और एस सी एल का यूएसए में संबंधित उत्पादक) और अन्य संगत व्यौरे को दर्शाता है।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	(क) सर्लस वैली मिनरल्स द्वारा निर्यात	मी.ट.	-	-	-	2,700
	निरमा को निर्यात	मी.ट.	-	-	-	2,700
	असंबंधित भारतीय पक्षकारों को निर्यात	मी.ट.	-	-	-	-
	(ख) यू एस ए से कुल आयात	मी.ट.	123	629	830	32,679
	प्रत्यक्ष	मी.ट.	123	629	830	17,852
	ट्रांसशिपमेंट	मी.ट.	-	-	-	14,827
2	निम्नलिखित की तुलना में सर्लस वैली मिनरल्स द्वारा किया गया निर्यात					
	भारतीय उत्पादन		0.00%	0.00%	0.00%	0.13%
	भारतीय खपत		0.00%	0.00%	0.00%	0.11%
	निरमा का उत्पादन		0.00%	0.00%	0.00%	0.58%
	निम्नलिखित की तुलना में निरमा द्वारा किया गया आयात					
	निरमा का उत्पादन		0.00%	0.00%	0.00%	0.58%
	भारतीय उत्पादन		0.00%	0.00%	0.00%	0.13%
	भारतीय खपत		0.00%	0.00%	0.00%	0.11%

3	भारत में यू एस ए से निर्यात	मी.ट.	123	629	830	32,679
	निरमा/सौकेम के अंगीभूत पक्षकारों द्वारा निर्यात	मी.ट.	-	-	-	2,700
	यू एस ए से अन्य पक्षकारों द्वारा निर्यात	मी.ट.	123	629	830	29,979
	यू एस ए से कुल निर्यात में निरमा के अंगीभूत उत्पादक द्वारा निर्यात का हिस्सा		0.00%	0.00%	0.00%	8.26%

54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि-

- सर्लस वैली मिनरल्स (यू एस ए में निरमा और एस सी एल की संबंधित कंपनी) जांच की अवधि के दौरान यू एस ए से सोडा ऐश का बहुत बड़ा निर्यातक नहीं है। यू एस ए से अन्य निर्यातक (असंबंधित) का यू एस ए से निर्यात में बहुत बड़ा हिस्सा है।
- सर्लस वैली मिनरल्स द्वारा निर्यात भारत में सोडा ऐश के कुल आयात, निरमा और सौकेम द्वारा सोडा ऐश का उत्पादन और भारत में सोडा ऐश की खपत की तुलना में बहुत ममूली है।
- सर्लस वैली मिनरल्स द्वारा निर्यात की मात्रा उतनी अधिक नहीं है कि इसने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई हो अथवा पहुंचा सके।
- निरमा द्वारा यू एस ए में संबंधित कंपनी से आयातों का उपयोग घरेलू बाजार में व्यापार के लिए नहीं किया गया है। उसका उपयोग निरमा द्वारा कैप्टिव खपत के लिए किया गया है और उसकी मात्रा निरमा के कुल उत्पादन की तुलना में बहुत कम है।
- निरमा का ध्यान (अथवा सौकेम) उत्पादन पर लगा रहता है। उचित तरीके से यह कहा जा सकता है कि कंपनी आयातित सामानों के व्यापार की ओर नहीं मुड़ी है और न ही कंपनी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसे पाटन से अनुचित रूप से लाभ हुआ है। वास्तव में पाटनरोधी शुल्क लगाने का अर्थ यह होगा कि सर्लस वैली मिनरल्स द्वारा किए गए निर्यात पर भी पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है। क्षति का निर्धारण घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र के भीतर सर्लस वैली मिनरल्स को शामिल करने से परिवर्तित नहीं होगा।
- विरोध कर रहे हितबद्ध पक्षकारों में से किसी ने अपने संबंध की बात को छोड़कर घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र से सर्लस वैली मिनरल्स को बाहर करने के लिए कोई औचित्य नहीं दिया है।

55. टाटा कैमिकल्स (संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों में से एक) का एक संबंधित उत्पादक रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार कीनिया में है और प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान कीनिया से बहुत अधिक आयात हुआ है। वर्तमान जांच में कीनियां संबद्ध देशों में से एक देश के रूप में शामिल है। जांच की अवधि के दौरान कीनियां में संबंधित निर्यातक द्वारा किए गए निर्यात का विवरण दर्शाता है कि (क) कीनिया की कंपनी टाटा कैमिकल की एक सहायक कंपनी है (ख) रिकॉर्ड कीनिया में सोडा ऐश के किसी अन्य उत्पादक को नहीं दर्शाते हैं। (ग) ये निर्यात पूरी जांच की अवधि के दौरान किए गए हैं (घ) याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने किन्हीं संगत कारणों से इस बात का खंडन नहीं किया है कि टाटा कैमिकल्स को घरेलू उद्योग के रूप में माने जाने के लिए नियम 2(ख) के अंतर्गत अपात्र घरेलू उत्पादक माना जाना चाहिए। नीचे दी गई तालिका कीनिया से निर्यात, मगदी सोडा ऐश (जिसका पुनः नाम टाटा कैमिकल्स मगदी लिमिटेड के रूप में रखा गया है) द्वारा किए गए निर्यात की मात्रा और अन्य संगत विवरण दर्शाते हैं :

क्र.सं.		इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	(क) मगदी सोडा द्वारा निर्यात	मी.ट.	85,797	1,15,520	1,17,572	1,06,585
	संबंधित पक्षकारों को निर्यात	मी.ट.	-	-	-	2,005
	असंबंधित भारतीय पक्षकारों को निर्यात	मी.ट.	85,797	1,15,520	1,17,572	1,04,580
	(ख) कीनिया से कुल आयात	मी.ट.	85,797	1,15,520	1,17,572	1,06,585

2	निम्नलिखित की तुलना में मगदी सोडा (कीनिया) द्वारा किया गया निर्यात	मी.ट.	85,797	1,15,520	1,17,572	1,06,585
	भारतीय उत्पादन		4.19%	5.72%	5.79%	5.13%
	भारतीय खपत		3.97%	5.24%	5.33%	4.32%
	टीसीएल का उत्पादन		11.33%	16.57%	16.91%	15.32%

56. उपर्युक्त से प्राधिकारी नोट करते हैं कि :

- मगदी सोडा, कीनिया (जिसका पुनः नाम टाटा कैमिकल्स मगदी लिमिटेड रखा गया है) कीनिया से सोडा ऐश का एकमात्र निर्यातक है।
- मगदी सोडा, (कीनिया) द्वारा किए गए निर्यात बहुत मामूली हैं जब उसकी तुलना भारत में सोडा ऐश के कुल आयातों, टाटा कैमिकल्स द्वारा सोडा ऐश के उत्पादन और भारत में सोडा ऐश की खपत से की जाए।
- मगदी सोडा, (कीनिया) द्वारा किए गए निर्यात की मात्रा उतने अधिक नहीं है कि ये घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाते हों अथवा उससे क्षति हो सकती हो।
- टाटा कैमिकल्स का ध्यान लगातार उत्पादन पर है। कंपनी व्यापारी नहीं बनी है हालांकि कंपनी को संबंधित कंपनी द्वारा पाटन से अनुचित लाभ से जांच की अवधि के दौरान कीनिया से संबंधित कंपनी द्वारा निर्यातों की मात्रा को देखते हुए इंकार नहीं किया जा सकता है।
- जबकि याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया है कि टाटा कैमिकल्स को अपात्र घरेलू उद्योग के रूप में माना जाना चाहिए, विरोध करने वाले किसी भी हितबद्ध पक्षकारों ने टाटा कैमिकल्स को घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र में शामिल किए जाने की मांग नहीं की है।

57. इस प्रकार से यह देखा गया है कि -

- यू एस ए से 85 प्रतिशत निर्यात और रोमानिया से 93 प्रतिशत निर्यात उन उत्पादकों द्वारा किया जाता है जो भारतीय उत्पादकों से संबंधित नहीं हैं। हालांकि मगदी से 100 प्रतिशत निर्यात उस उत्पादक द्वारा किया जाता है जो भारतीय उत्पादकों में से एक उत्पादक से संबंधित हैं।
- टाटा कैमिकल्स के संबंध में, मगदी सोडा द्वारा किया गया निर्यात बहुत अधिक है। मगदी सोडा कीनिया में सोडा ऐश का एकमात्र उत्पादक है, निर्यात की मात्रा में कमी नहीं आई है। मगदी सोडा की घरेलू मांग बहुत कम है और कंपनी का ध्यान निर्यात पर है (कंपनी द्वारा निर्यात इसकी कुल बिक्री का लगभग 90 प्रतिशत है)। प्राधिकारी यह मानते हैं कि यद्यपि, टाटा कैमिकल्स एक घरेलू उत्पादक है फिर भी कंपनी को वर्तमान जांच के प्रयोजन से "घरेलू उद्योग" के रूप में माने जाने के लिए अपात्र होने पर विचार किया जाना चाहिए।
- जी एच सी एल के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबंधित निर्यातक द्वारा किए गए निर्यात में जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक गिरावट आई है, रोमानिया से असंबंधित उत्पादकों द्वारा 93 प्रतिशत निर्यात रोमानिया में किया जाता है, जी एच सी एल का ध्यान विनिर्माण से व्यापार की ओर नहीं गया है और न ही ऐसा कहा जा सकता है कि संबंधित निर्यातक अथवा जी एच सी एल को इससे कोई लाभ हुआ है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि जी एच सी एल वर्तमान जांचों के प्रयोजन से "घरेलू उद्योग" के रूप में माने जाने के लिए पात्र है।
- निरमा और सौकेम के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबंधित निर्यातक द्वारा किया गया निर्यात केवल जांच की अवधि में था। यू एस ए से निर्यात का 85 प्रतिशत यू एस ए में असंबंधित उत्पादकों द्वारा किया गया है। निरमा का ध्यान विनिर्माण से व्यापार की ओर नहीं गया है जैसाकि संगत आंकड़े दर्शाते हैं। यू एस ए में संबंधित उत्पादक द्वारा किए गए निर्यात के बारे में यह नहीं कह जा सकता है कि इससे भारत में घरेलू उत्पादक नामतः निरमा अथवा सौकेम को अनुचित लाभ हुआ है बल्कि, इस सामग्री की मामूली मात्रा का आयात आंतरिक खपत के लिए किया गया है। उपर्युक्त स्थित को देखते हुए प्राधिकारी निरमा और सौकेम को वर्तमान जांच के प्रयोजन से "घरेलू उद्योग" के रूप में माने जाने के लिए पात्र समझते हैं।

58. इस प्रकार से प्राधिकारी का यह मत है कि जी एच सी एल, निरमा, सौकेम और डी सी डब्ल्यू लिमिटेड को पटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग के रूप में मानना उपयुक्त है। तदनुसार, प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के साथ पठित नियम 2 (ख) की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए "घरेलू उद्योग" के रूप में संबंधित आवेदकों, जी एच सी एल, निरमा, सौकेम और डी सी डब्ल्यू लि. को मानते हैं।

15. वर्तमान एम टी आर जांच में घरेलू उद्योग के किसी भी उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। हालांकि घरेलू उद्योग के कुछ उद्योगों ने जांच की उसी अवधि के लिए चीन जन.गण., ई यू, कीनिया, पाकिस्तान, ईरान, यूक्रेन और यू एस ए से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई वर्तमान एम टी आर जांच तथा अन्य एम टी आर जांच में उक्त देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। उक्त एमटीआर जांच में घरेलू उद्योग की स्थिति नीचे दी गई है।

16. चीन जन.गण., ई यू, कीनिया, पाकिस्तान, ईरान, यूक्रेन और यू एस ए के संबंध में प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई एमटीआर जांच में, डी सी डब्ल्यू ने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और न ही यह संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातक अथवा निर्यातक से संबंधित है। निरमा ने भी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। यू एस ए में केवल उनके 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। जी एच सी एल लि. ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का मामूली मात्रा में आयात किया है। केवल टाटा कैमिकल्स ने जांच की अवधि में कीनिया में अपनी सहायक कंपनी से संबद्ध वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में आयात नहीं किया है बल्कि न तो मूल जांच में और न ही वर्तमान समीक्षा में वह घरेलू उद्योग का हिस्सा हैं। वर्तमान जांच में शामिल विभिन्न घरेलू उत्पादकों, जो घरेलू उद्योग होने का दावा करते हैं, द्वारा जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का किए गए आयातों का व्यौरा नीचे दिया गया है :-

जी एच सी एल

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	पोस्ट-पीओआई
1	जीएचसीएल द्वारा आयात	मी.ट.	-	-	3,021	12,689	14,760
क	संबद्ध देश (चीन आदि)	मी.ट.	-	-	3,021	12,689	14,760
ख	संबद्ध देश (टर्की तथा रूस)	मी.ट.	-	-	-	-	-
2	कुल आयात	मी.ट.	4,44,475	6,92,228	5,67,587	7,23,978	3,67,818
क	संबद्ध देश (चीन आदि)	मी.ट.	3,29,828	5,53,416	4,89,270	6,73,706	3,47,389
ख	संबद्ध देश (टर्की तथा रूस)	मी.ट.	1,10,695	1,19,014	62,103	49,071	19,305
3	भारतीय उत्पादन	मी.ट.	23,55,710	23,61,482	23,35,596	24,17,331	12,36,435
4	आबद्ध रहित भारतीय खपत	मी.ट.	24,30,534	27,77,552	27,35,605	29,42,744	14,86,940
5	जीएचसीएल का उत्पादन	मी.ट.	6,76,007	6,85,101	6,76,523	7,04,835	3,49,820
6	निम्नलिखित की तुलना में जीएचसीएल द्वारा किय गया आयात						
क	जीएचसीएल उत्पादन	%	-	-	0.45	1.80	4.22
ख	भारतीय उत्पादन	%	-	-	0.13	0.52	1.19
ग	भारतीय खपत	%	-	-	0.11	0.43	0.99
घ	कुल आयात	%	-	-	0.53	1.75	4.01
i	संबद्ध देश (चीन आदि)	%	-	-	0.62	1.88	4.25
ii	संबद्ध देश (टर्की तथा रूस)	%	-	-	-	-	-

17. निरमा लिमिटेड के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि उक्त कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष तौर पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। हालांकि यूएसए में उनकी 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं की कुछ मात्रा का निर्यात किया है परंतु निरमा की सहायक कंपनी एकमात्र उत्पादक अथवा यू एस ए से निर्यातक नहीं है और इस कारण से यदि इसने जांच की अवधि के दौरान उतनी मात्रा में निर्यात नहीं किया होता, जितना इसने भारत में निर्यात किया है, तब एक अन्य यू एस ए निर्यातक द्वारा इस अंतर को पूरा कर दिया गया होता। जैसा कि निरमा द्वारा दिया गया है, संबंधित यू एस ए प्रतिष्ठान द्वारा संबद्ध वस्तुओं को को किए गए निर्यात का व्यौरा नीचे दिया गया है :-

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	पोस्ट पीओआई
1क	सीअरलैस वैली मिनरल्स द्वारा निर्यात	मी.ट.				48,228	59,523
	क)संबद्ध	मी.ट.	-	-	-	-	-
	ख) असंबद्ध	मी.ट.	-	-	-	48,228	59,523
2	निरमा लि0 द्वारा सभी संबद्ध देशों से आयात	मी.ट.	-	-	-	-	-
3	सीअरलैस वैली मिनरल्स द्वारा कुल निर्यात	मी.ट.	-	-	-	48,228	59,523
4	कुल आयात	मी.ट.	4,44,475	6,92,228	5,67,587	7,23,978	3,67,818
क	संबद्ध देश (चीन आदि)	मी.ट.	3,29,828	5,53,416	4,89,270	6,73,706	3,47,389
ख	संबद्ध देश (टर्की तथा रूस)	मी.ट.	1,10,695	1,19,014	62,103	49,071	19,305
5	भारतीय उत्पादक	मी.ट.	23,55,710	23,61,482	23,35,596	24,17,331	12,36,435
6	भारतीय खपत	मी.ट.	24,30,534	27,77,552	27,35,605	29,42,744	14,86,940
7	निरमा लि0 का उत्पादन	मी.ट.	8,21,064	8,43,699	8,43,444	8,58,359	4,56,112
8	सीअरलैस वैली मिनरल्स इंक द्वारा संबंधित को निर्यात						
क	निरमा उत्पादन	%	-	-	-	5.62	13.05
ख	भारतीय उत्पादक	%	-	-	-	2.00	4.81
ग	भारतीय खपत	%	-	-	-	1.64	4.00
घ	कुल आयात	%	-	-	-	6.66	16.18
ii	संबद्ध देश (चीन आदि)	%	-	-	-	7.16	17.13
ii	संबद्ध देश (टर्की तथा रूस)	%	-	-	-	-	-

18. टाटा कैमिकल लि. के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कंपनी ने स्वयं संबद्ध देशों में अपने संबंधित पक्षकार से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। इसके अलावा, टाटा कैमिकल्स लि. के हितबद्ध पक्षकार ने भारत में काफी मात्रा में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए टाटा कैमिकल्स का मामला न तो जी एच सी एल और न ही निरमा से तुलनीय है और इसलिए प्राधिकारी टाटा कैमिकल्स लि. को एक पात्र घरेलू उद्योग के रूप में नहीं मानते हैं। घरेलू उद्योग द्वारा अनुसार उनके आयातों का विवरण निम्नानुसार है:-

टाटा कैमिकल्स लिमिटेड

क्र.सं.	विवरण	मी.ट.	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	टाटा कैमिकल्स मगदी लि0 द्वारा निर्यात	मी.ट.	-	-	-	1,32,725
	क)संबद्ध	मी.ट.	-	-	-	16,407
	ख)असंबद्ध	मी.ट.				1,16,318
2	संबद्ध देशों से कीनिया को निवल आयात (चीन आदि)	मी.ट.	-	-	-	43,253
3	कुल आयात/टाटा द्वारा निर्यात	मी.ट.	-	-	-	1,75,978
4	संबद्ध देश (टर्की और रूस)	मी.ट.	-	-	-	-
5	कुल आयात	मी.ट.	4,44,475	6,92,228	5,67,587	7,23,978

a	संबद्ध देश (चीन आदि)	मी.ट.	3,29,828	5,53,416	4,89,270	6,73,706
b	संबद्ध देश (टर्की और रूस)	मी.ट.	1,10,695	1,19,014	62,103	49,071
6	भारतीय उत्पादन	मी.ट.	23,55,710	23,61,482	23,35,596	24,17,331
7	भारतीय खपत	मी.ट.	24,30,534	27,77,552	27,35,605	29,42,744
8	टाटा कैमिकल्स का उत्पादन	मी.ट.	6,90,181	6,93,396	7,23,819	7,23,892
9	टीसीएल द्वारा संबंधित को किए गए आयात					
a	टीसीएल उत्पादन	%	-	-	-	24.31
b	भारतीय उत्पादन	%	-	-	-	7.28
c	भारतीय खपत	%	-	-	-	5.98
d	कुल आयात	%	-	-	-	24.31
i	संबद्ध देश (चीन आदि)	%	-	-	-	26.12
ii	संबद्ध देश (टर्की और रूस)	%	-	-	-	-

19. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों का आशय किसी घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग की परिधि से केवल इस कारण से वंचित नहीं करना है कि उन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। नियमावली के अंतर्गत घरेलू उद्योग का दर्जा प्राप्त करने का दावा करने वाले किसी घरेलू उत्पादक द्वारा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात को नियम का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। प्राधिकारी द्वारा यह आकलन किया जाना महत्वपूर्ण है कि ऐसे घरेलू उत्पादकों का उद्देश्य, ऐसे आयातों की मात्रा, उस स्थिति का क्या मतलब है जिसके अंतर्गत ऐसे आयात किए गए हैं और ऐसे उद्योगों के वित्तीय मानदंडों पर ऐसे आयातों का क्या प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान जांच में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार, जीएचसीएल और निरमा, जिन्होंने डी सी डब्ल्यू के साथ घरेलू उद्योग के रूप में माने जाने का दावा किया है, ने न तो जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में आयात किया है और न ही संबद्ध देशों में उनके संबंधित निर्यातकों ने उनके माध्यम से भारत में संबद्ध वस्तुओं को बेचा है। उनके व्यापार का केन्द्र उत्पादन से व्यापार की ओर भी नहीं मुड़ा है। जी एच सी एल और निरमा दोनों ने जांच की अवधि के दौरान उत्पादन की अपनी 80 प्रतिशत क्षमता से अधिक का उपयोग किया है। इस कारण से उनके द्वारा संबद्ध वस्तुओं का किया गया आयात और उनके संबंधित पक्षकार द्वारा किए गए निर्यात को निर्यात की व्याख्या स्वयं को व्यापार में शामिल करने के प्रयास के रूप में नहीं किया जा सकता है। यदि उन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की कुछ मात्रा का आयात किया भी है तब यह आयात की कीमत की प्रतिस्पर्धा करने अथवा ग्राहक को बनाए रखने के लिए किया गया है जो अन्य प्रकार से अपेक्षाकृत सस्ते आयात की ओर गया होता। इसके अलावा, उनके द्वारा किया गया ऐसा आयात वास्तव में पाटनरोधी शुल्कों के भुगतान पर है और इसलिए ऐसा नहीं देखा जा सकता है कि इससे उन्हें अनुचित वित्तीय लाभ मिला है।

20. वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग के संघटकों की उत्पादन स्थिति नीचे दी गई है :-

विवरण	यू ओ एम	2011- 12	2012- 13	2013-14	पीओआई
घरेलू उद्योग का उत्पादन	मी.ट.	15,78,674	16,11,377	16,02,002	16,45,154
अन्य उत्पादकों का उत्पादन	मी.ट.	7,77,036	7,50,106	7,33,594	7,72,177
कुल भारतीय उत्पादन	मी.ट.	23,55,710	23,61,482	23,35,596	24,17,331
घरेलू उद्योग का हिस्सा	%	67.01	68.24	68.59	68.06
अन्य उत्पादकों का हिस्सा	%	32.99	31.76	31.41	31.94

21. उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के साथ पठित नियम 2(ख) की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए "घरेलू उद्योग" के रूप में जी एच सी एल, निरमा लिमिटेड और जी सी डब्ल्यू लिमिटेड को मानते हैं।

ड. गोपनीयता

22. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता के मुद्दे के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

- घरेलू उत्पादकों को गोपनीयता देने के लिए कोई उचित आधार नहीं है। बिक्री का मूल्य, प्रारंभिक और अंतिम भंडार से संबंधित सूचना आवेदकों के अलग-अलग तुलन-पत्रों में आसानी से उपलब्ध नहीं है, परंतु उसे उनके उत्तर में नहीं दिया गया है।

- ii. घरेलू उत्पादकों के अगोपनीय पाठ में विसंगतियां हैं। इस कारण से घरेलू उत्पादकों द्वारा दी गई सूचना को अस्वीकार किए जाने की आवश्यकता है।
23. घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-
- जहां तक गोपनीयता संबंधी आंकड़ों का प्रश्न है, आंकड़ों में लिपिकीय/गणना अथवा संचयन संबंधी त्रुटियां थीं जिन्हें ठीक कर लिया गया है और सुनवाई के पूर्व सभी पक्षकारों को सूचना दे दी गई है।
 - घरेलू उद्योग ने आंकड़ों में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं किया। इसने एक अतिरिक्त पत्र भेजा और दो अनुरोध पत्रों में निहित गोपनीय सूचना के संबंध में कोई अंतर नहीं था।
 - घरेलू उद्योग के संघटकों द्वारा किए गए आयातों की मात्रा अथवा संबंधित पक्षकारों द्वारा किए गए निर्यात की मात्रा को सार्वजनिक रूप से प्रकट करने का कोई आधार नहीं है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

24. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है :-
- (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उप नियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।
 - (2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।
 - (3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।
25. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक माना गया, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना पर गोपनीय के रूप में विचार किया गया है तथा इसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रस्तुत करें। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोई भी सूचना जो सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है, को गोपनीय नहीं माना जा सकता है।

च. विविध अनुरोध :

आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

26. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं :-
- घरेलू उद्योग ने एमटीआर के उत्तर में दिए गए आंकड़ों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया और उन्होंने शुद्धता का आवश्यक प्रमाण पत्र भी दायर नहीं किया।
 - भाड़े को शामिल करने के दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है और वास्तव में यह रैस जुडीकेटा का सिद्धांत इस मसले पर लागू नहीं होता है क्योंकि घरेलू उद्योग एक बार फिर उसी प्राधिकारी के समक्ष इस मुद्दे बल दे रहा है जो उसने मूल जांच में किया और जिसे प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था।
 - मौखिक सुनवाई के दौरान, घरेलू उद्योग ने प्रतिवादी द्वारा किए गए अनुरोध का खंडन नहीं किया और "नॉन ट्रेवर्स के सिद्धांत" को देखते हुए, यह माना गया है कि घरेलू उत्पादकों ने ऐसे अनुरोध को मान लिया है।
 - दो मध्यावधिक समीक्षाओं को मिला दिया जाना चाहिए क्योंकि विचाराधीन उत्पाद घरेलू उत्पादकों की संरचना और जांच की अवधि एक ही है।

- v. घरेलू उद्योग को वर्तमान जांच में यथा परिभाषित घरेलू उद्योग के रूप में अनुमान लगाया जाना है। यह केवल और केवल स्वयं घरेलू उत्पादक हैं न कि आवेदक, जो इस संबंध में और सूचना दे सकते हैं। घरेलू उद्योग की पहचान करने तथा आरोप लगाने के लिए आवेदक के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 23(1क) के अंतर्गत कोई आवश्यकता नहीं है।
- vi. चूंकि रिट याचिका और अपील घरेलू उत्पादकों द्वारा दायर किए गए भाड़े को शामिल किए जाने के मुद्दे उच्च न्यायालय और सेस्टेट में लंबित हैं अतः प्राधिकारी को क्षति रहित कीमत के निर्धारण के संबंध में अपनी स्थापित प्रथा को नहीं बदलना चाहिए और क्षति रहित कीमत का निर्धारण करते समय अंतरदेशीय भाड़े को शामिल नहीं करना जारी रखना चाहिए। भाड़े को शामिल करना/शामिल नहीं करने के इस मुद्दे के बारे में निर्णय तब लिया जा सकता है जब यह मामला उच्च न्यायालय अथवा सेस्टेट द्वारा अंतिम रूप से निपटा दिया जाए।
- vii. चूंकि घरेलू उद्योग क्षमता होने के बावजूद आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है, अतः घरेलू बाजार में मांग-आपूर्ति के बीच अंतर है।
- viii. भारत में काफी संख्या में लोगों को रोजगार देते हुए छोटे, लघु और मध्यम डिटरजेंट उत्पादकों की संख्या हजारों में है। सोडा ऐश, डिटरजेंट के लिए प्रमुख कच्चे माल पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क से उन्हें बहुत अधिक दिक्कत हो सकती है। मांग और आपूर्ति में अंतर के कारण घरेलू उद्योग द्वारा अपेक्षित मात्रा में आपूर्ति न करने से इन उद्योगों को पाटनरोधी शुल्क लगने वाले आयातित माल पर निर्भर करने के लिए बाध्य होना पड़ता है और उसके द्वारा उनके उत्पाद लागत की दृष्टि से अप्रभावी हो जाते हैं।
- ix. कीमत के निर्धारण के संबंध में सोडा ऐश के घरेलू उत्पादकों के बीच एक आपसी समझौता होता है जिससे डाउन स्ट्रीम उद्योगों की लागत पर कार्टेलाइजेशन होता है।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

27. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं :-

- i. इस याचिका में त्रुटि है क्योंकि इसमें "घरेलू उद्योग" को सिद्ध किए बिना क्षति के न होने का दावा किया गया है।
- ii. यह याचिका इस बात को सिद्ध नहीं करती है कि क्यों पाटनरोधी शुल्क को वापस लिए जाने की आवश्यकता है। मध्यावधि समीक्षा का उद्देश्य इस बात का विश्लेषण करना है कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति शुल्क को समय से पूर्व हटा लेने की स्थिति में जारी रहने की संभावना अथवा फिर से होने की संभावना है।
- iii. प्राधिकारी से यह अनुरोध है कि वह प्राधिकारी द्वारा सामान्य तौर पर लागू किए जा रहे क्षति मार्जिन के लिए तथा मूल जांच के समय यथा लागू की गई पद्धति तथा वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उसकी उचितता और उपयुक्तता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार करे। एनआईपी प्रथा और कानून के संबंध में, अनुबंध-3 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों का पालन पूर्व में किया जा रहा था और प्राधिकारी द्वारा इस कानून को लागू किए जाने के पूर्व भी पालन किया जा रहा था।
- iv. इस तथ्य को देखते हुए कि स्थायी विवरण में कंपनीवार व्यौरे शामिल हैं, स्थायी तालिका और क्षति विवरण में उत्पादन में अंतर के संबंध में, यह एक लिपिकीय त्रुटि थी जो खेदजनक है परंतु ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इससे हितबद्ध पक्षकारों के प्रति गंभीर भेदभाव हुआ है कि शुल्कों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
- v. दायर की गई सूचना के साथ सटीकता प्रमाणपत्र दायर करने की कोई निर्धारित अपेक्षा नहीं है। घरेलू उद्योग को लिपिकीय मानवीय त्रुटियों के आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता है और इसे एक औचित्यपूर्ण संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है।
- vi. हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग भाड़े के कारण दक्षिण में आपूर्ति करने के लिए इच्छुक नहीं है, यह अनुरोध किया जाता है कि सर्वप्रथम घरेलू उद्योग ने किसी उपभोक्ता को कोई ऐसा मार्ग नहीं दिया है जिसके लिए उसे खेद व्यक्त करना है और दूसरे यह कि यह दर्शाता है कि भाड़े को क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए मान्यता दी जा सकती है।
- vii. नॉन ट्रेवर्स के सिद्धांत पर निर्भरता निराधार है क्योंकि जब अनुरोध किए जाते हैं और अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में प्रत्युत्तर अनुरोध किए जाते हैं तब सुनवाई का कोई मतलब नहीं रह जाता है।
- viii. घरेलू उद्योग को दो मध्यावधि समीक्षाओं के संचयन पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि इससे जांच की प्रक्रिया आरंभ करना अवैध हो जाएगा और एक नई मध्यावधि समीक्षा जांच शुरू करना आवश्यक होगा।

- ix. भारत में वैश्विक बाजार जिसके पास सोडा ऐश अतिरिक्त मात्रा में है की तुलना में सोडा ऐश का उत्पादन बहुत कम होता है। आर एस पी एल लि० एक प्रमुख डिटरजेंट निर्माता घरेलू बाजार में बिक्री तथा कैप्टिव खपत के लिए 5 लाख मी.ट. उत्पादन क्षमता वाला एक सोडा ऐश संयंत्र भारत में स्थापित कर रहा है। उनके प्रवेश के साथ भारत सोडा ऐश के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्कों को वापस लिया जाता है और कीमतों में गिरावट आई है, तब आर एस पी एल को क्षति होगी। इस कारण से वर्तमान पाटनरोधी शुल्क जारी रखा जाना चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

28. पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है :-

(1) अधिनियम की धारा 9 क के उपबंध के अंतर्गत लगाया गया कोई पाटनरोधी शुल्क क्षति पहुंचाने वाले पाटन को समाप्त करने के लिए उस अवधि तक और उस सीमा तक लागू रहेगा।

(1क) निर्दिष्ट प्राधिकारी जहां अपेक्षित हो, अपनी खुद की पहल पर या ऐसे किसी हितबद्ध पक्षकार के अनुरोध पर जो ऐसी समीक्षा की जरूरत की पुष्टि करते हुए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करता है और निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद उचित समयावधि बीत जाती है, किसी पाटनरोधी शुल्क को निरंतर लागू रखने की जरूरत की समीक्षा करेंगे और ऐसी समीक्षा के उपरांत निर्दिष्ट प्राधिकारी उस स्थिति में उसकी समाप्ति हेतु केन्द्र सरकार को सिफारिश करेंगे जहां वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त या परिवर्तित कर दिया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है और इसलिए अब इसकी जरूरत नहीं है।

(1 ख) उप नियम (1) या (1क) में किसी बात के होते हुए भी अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसके लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त अवधि से पूर्व अपनी खुद की पहल पर या घरेलू उद्योग की ओर से किए गए विधिवत पुष्टिकृत अनुरोध के आधार पर उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उचित अवधि के भीतर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत शुरू की गई कोई समीक्षा ऐसी समीक्षा की शुरुआत की तारीख से 12 माह से अनधिक अवधि के भीतर संपन्न की जाएगी।

(3) नियम 6,7,8,9,10, 11, 16, 17, 18, 19 तथा 20 के उपबंध समीक्षा के मामले में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

29. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.2 में यह प्रावधान है कि प्राधिकारी जहां भी आवश्यक हो किसी हितबद्ध पक्षकार, जो ऐसी समीक्षा की आवश्यकता की पुष्टि करते हुए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करते हों, तथा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने के समय से उचित समयावधि समाप्त हो गई हो, द्वारा अपने स्वयं के पहल पर अथवा उनके अनुरोध पर कोई पाटनरोधी शुल्क को लगातार लगाने की आवश्यकता की समीक्षा करेगा। हितबद्ध पक्षकार के पास प्राधिकारियों से इस बात की जांच करने का अनुरोध करने का अधिकार होगा कि क्या पाटन के प्रभाव से बचने के लिए शुल्क को लगातार लगाना आवश्यक है, क्या यदि शुल्क को हटा दिया जाए अथवा उसमें परिवर्तन किया जाए, अथवा दोनों हो, तब क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना होगी। यदि इस पैरा के अंतर्गत समीक्षा के फलस्वरूप प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क अब आवश्यक नहीं है, तब इसे तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा।

30. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि मध्यावधि समीक्षा का कार्यक्षेत्र निर्णायक समीक्षा के कार्यक्षेत्र से अधिक है। आवेदक ने यह तर्क दिया है कि एक मध्यावधि समीक्षा में डी जी ए डी को इस तथ्य पर विचार करना और निर्धारण करना अपेक्षित है कि क्या 5 वर्ष पूरे होने के बाद पाटनरोधी शुल्क को वापस लेने के लिए पर्याप्त औचित्य है जबकि निर्णायक समीक्षा में डी जी ए डी से इस बात का निर्धारण करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क को 5 वर्ष की समाप्ति के बाद और आगे बढ़ाना अपेक्षित है या नहीं। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि मध्यावधि समीक्षा में केवल वर्तमान कार्य निष्पादन इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है कि क्या इस चरण में पाटनरोधी शुल्क वापस लिया जा सकता है और क्या यह कि प्राधिकारी को जब पाटनरोधी शुल्क वापस लिया जाए तब उत्पन्न होने वाली संभावित स्थिति पर विचार करना अपेक्षित है।

31. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच की है और यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली में प्राधिकारी के लिए यह बाध्यता है कि वह जहां भी आवश्यक हो किसी हितबद्ध पक्षकार, जो ऐसी समीक्षा की आवश्यकता की पुष्टि करते हुए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करते हों, तथा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने के समय से उचित समयावधि समाप्त हो गई हो, द्वारा अपने स्वयं के पहल पर अथवा उनके अनुरोध पर कोई पाटनरोधी शुल्क को लगातार लगाने की आवश्यकता की समीक्षा करेगा और इस प्रकार की समीक्षा किए जाने पर निर्दिष्ट प्राधिकारी केन्द्र सरकार को इसे वापस लेने की सिफारिश करेंगे जहां वह इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति होने या फिर से होने की संभावना उस स्थिति में नहीं है जब उक्त पाटनरोधी शुल्क को हटाया जाएगा अथवा उसमें परिवर्तन किया जाएगा और इसलिए इसकी अब आवश्यकता नहीं है।

32. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने एमटीआर के उत्तर में दिए गए आंकड़ों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया और उन्होंने शुद्धता का आवश्यक प्रमाण पत्र भी दायर नहीं किया, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के संगत आंकड़ों/सूचना को सत्यापित किया गया है।

33. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि एन आई पी में भाड़े को शामिल करने के दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है और इसे प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए, यह नोट किया जाता है कि एन आई पी का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-3 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ही किया गया है।

34. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि दो मध्यावधि समीक्षाओं अर्थात् वर्तमान समीक्षा और प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई टर्की और रूस के विरुद्ध समीक्षा को मिला दिया जाना चाहिए क्योंकि विचाराधीन उत्पाद, घरेलू उत्पादकों की संरचना और जांच की अवधि एक ही है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि दो मध्यावधि समीक्षाएं दो अलग-अलग अंतिम जांच परिणाम और शुल्क अधिसूचनाओं के संबंध में हैं जिसमें अलग-अलग देशों के दो समूह हैं। इस कारण से इन दोनों जांचों को शामिल करना उपयुक्त नहीं होगा।

35. हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि घरेलू बाजार में मांग और आपूर्ति में अंतर है क्योंकि घरेलू उद्योग क्षमताएं होने के बावजूद आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है और जिसके कारण डाउन स्ट्रीम उद्योगों विशेषकर छोटे, लघु और मध्यम डिटरजेंट उत्पादकों को नुकसान हो रहा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी कानून में घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में समग्र मांग को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है। चूंकि पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयात प्रतिबंधित नहीं होता है और इसका उद्देश्य पाटन के कारण एक अनुचित स्थिति में सुधार लाना मात्र है, प्रयोक्ता क्षेत्र हमेशा अपनी अतिरिक्त मांग को आयात कर सकते हैं और उसे पूरा कर सकते हैं।

36. हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि कीमत के निर्धारण के संबंध में सोडा ऐश के घरेलू उत्पादकों के बीच एक आपसी समझौता होता है जिससे डाउन स्ट्रीम उद्योगों की लागत पर कार्टेलाइजेशन होता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आरोप अपुष्ट है।

छ. पाटन मार्जिन का निर्धारण

बाजार अर्थव्यवस्था दावे, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन

आवेदकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

37. बाजार अर्थव्यवस्था दावे, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन के संबंध में आवेदकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध नीचे दिए गए हैं :-

- i. जब सोडा ऐश का उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों से किया जाता है तब उत्पादन की लागत बहुत कम होती है। यदि ऐसा प्रकटन सही है, तब उन देशों में सामान्य मूल्य अपेक्षाकृत बहुत कम होता।
- ii. चूंकि घरेलू उत्पादकों द्वारा इसके संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतरदेशी दुलाई, पत्तन संबंधी खर्च और बैंक प्रभारों के लिए कीमत ली है, निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह घरेलू उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर पूर्ण रूप से विश्वास करने के बजाए साक्ष्य मंगाए और ऐसी सूचना प्राप्त करे।
- iii. असहयोगी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की गणना सहयोगी निर्यातकों की निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के आधार पर की जानी चाहिए।
- iv. रूस से आयातों के विरुद्ध भारत द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के समय से भारत में सोडा ऐश का रूस से निर्यात में बहुत अधिक कमी आई है।
- v. सोडा ऐश की कीमतों में विश्वव्यापी वृद्धि कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि का परिणाम है। इस कारण से भारतीय सोडा ऐश क्षेत्र पर रूस की कीमतों का प्रभाव निकट भविष्य में पड़ने की संभावना नहीं है।
- vi. ईटीआई और सोडा सोनायी का सोडा ऐश की निर्यात कीमत में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। ईटीआई सोडा ऐश द्वारा निर्यात से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

38. बाजार अर्थव्यवस्था, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध नीचे दिए गए हैं :-

- i. निर्यात कीमत डी जी सी आई एंड एस की लेनदेनवार आंकड़ों के आधार पर रही है। निर्यात कीमतों का समायोजन समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतरदेशीय दुलाई, पत्तन संबंधी खर्च, बैंक प्रभार और वैट के अंतर के लिए किया गया है।

- ii. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत, दोनों का निर्धारण कारखानागत स्तर पर किया गया है। घरेलू उद्योग ने उस उत्पाद की सभी भौतिक विशेषताओं पर विचार किया है जिसके लिए सूचना उपलब्ध है। इस प्रकार से घरेलू उद्योग द्वारा की गई तुलना एक उचित तुलना है।
- iii. पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम है बल्कि पर्याप्त भी है।
- iv. उन देशों में अपेक्षाकृत कम उत्पादन लागत, जहां उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों से होता है, के संबंध में आई एच एस कैमिकल जर्नल उन देशों में प्रचलित कीमत को प्रकाशित करता है जिसके फलस्वरूप इन देशों में बहुत अधिक लाभ अर्जित किए जाने का अनुमान लगाया जाता है।
- v. घरेलू उद्योग में उस देश में प्रचलित कीमत उपलब्ध कराई है जिस पर विचार किया जाना आवश्यक है।
- vi. घरेलू उद्योग ने विभिन्न समायोजनों के लिए लिए गए साक्ष्य के संबंध में परंपरागत दृष्टिकोण का पालन किया है।
- vii. प्राधिकारी को असहयोगी निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के उद्देश्य से अधिकतम सामान्य मूल्य और न्यूनतम निर्यात कीमत लेनदेन पर विचार करना चाहिए।

ज. सामान्य मूल्य का निर्धारण

39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर टर्की के केवल दो उत्पादकों/निर्यातकों नामतः सोडा सनायी ए.एस. और इटीआई सोडा द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उसे प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और उस पर सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के उद्देश्य से विचार किया गया है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रूस से किसी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

सोडा सनायी ए.एस., टर्की

40. सोडा सनायी ए.एस., टर्की ने *** पी के आर का सकल बीजक मूल्य के लिए *** टी.एल. संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बिक्री की सूचना दी है। छूट, अंतरदेशीय भाड़ा, वेयरहाउस प्रभार, ऋण की लागत और माल भंडार के वहन संबंधी लागत के संबंध में समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी ने सोडा सनायी ए एस टर्की के संबंध में कारखानागत स्तर पर दावा किए गए तथा यथा निर्धारित सामान्य मूल्य के समायोजन को मान लिया है। सोडा सनायी ए एस, टर्की के लिए इस प्रकार से निर्धारित प्रस्तावित सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

ई टी आई सोडा, टर्की

41. ई टी आई सोडा, टर्की ने *** पी के आर का सकल बीजक मूल्य के लिए *** टी.एल. संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बिक्री की सूचना दी है। अंतरदेशीय भाड़ा, और ऋण की लागत के संबंध में समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी ने ई टी आई सोडा, टर्की के संबंध में कारखानागत स्तर पर दावा किए गए तथा यथा निर्धारित सामान्य मूल्य के समायोजन को मान लिया है। ई टी आई सोडा, टर्की के लिए इस प्रकार से निर्धारित प्रस्तावित सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

टर्की के असहयोगी निर्यातक

42. प्राधिकारी नोट करते हैं कि टर्की के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है और न ही सहयोग किया है। इसलिए प्राधिकारी ने टर्की के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने हेतु टर्की से सहयोगी निर्यातक के उच्चतम सामान्य मूल्य को अपनाया है। टर्की के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए इस प्रकार से निर्धारित प्रस्तावित सामान्य मूल्य के व्यौरे का उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

रूस के संबंध में सामान्य मूल्य

43. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रूस के किसी उत्पादक/निर्यातक ने सहयोग नहीं किया है तथा निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इस कारण से प्राधिकारी ने रूस के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने हेतु इस नियमावली के नियम 6 (8) के संबंध में सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर विचार किया है। रूस के लिए इस प्रकार से निर्धारित प्रस्तावित सामान्य मूल्य के व्यौरे का उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

झ. निर्यात कीमत**टर्की****सोडा सनायी ए.एस. टर्की**

44. निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर में, जांच अवधि के दौरान, आई सी आई सोडा सनायी ए.एस. टर्की ने *** पी के आर का सकल बीजक मूल्य के लिए *** मी.ट. संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बिक्री की सूचना दी है। कंपनी ने अंतरदेशीय भाड़ा, क्लीयरिंग और रखरखाव संबंधी प्रभार, ऋण की लागत, निवल विदेशी विनिमय लाभ/हानि, शुल्क वापसी के संबंध में समायोजन का दावा किया है। हालांकि प्राधिकारी नोट करते हैं कि निवल विदेशी विनिमय से संबंधित लाभ/हानि के कारण दावा किए गए समायोजन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसका निर्यात की बिक्री से सीधा संबंध नहीं है। शुल्क वापसी के संबंध में दावा किए गए समायोजन के संबंध में, उसे समर्थन में दस्तावेजों के साथ इसकी पुष्टि किए बिना नहीं माना जा सकता है। अतः अंतरदेशीय भाड़ा, क्लीयरिंग और रखरखाव संबंधी प्रभार तथा ऋण की लागत के कारण कीमत में समायोजन करने के बाद, कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है। सोडा सनायी ए.एस. के लिए इस प्रकार से निर्धारित प्रस्तावित निवल निर्यात कीमत के ब्यौरे का उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

ईटीआई सोडा टर्की

45. निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर में, जांच अवधि के दौरान, ईटीआई सोडा टर्की ने *** अम.डॉ. का सकल बीजक मूल्य के लिए *** मी.ट. संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बिक्री की सूचना दी है। कंपनी ने अंतरदेशीय भाड़ा, समुद्री दुलाई, समुद्री बीमा और बैंक प्रभार, के संबंध में समायोजन का दावा किया है। जैसा कि कंपनी द्वारा दावा किया गया है, कीमत के समायोजन के बाद, कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है। ईटीआई सोडा, टर्की के लिए इस प्रकार से निर्धारित प्रस्तावित निवल निर्यात कीमत के ब्यौरे का उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

टर्की के अन्य सभी निर्यातक

46. प्राधिकारी नोट करते हैं कि टर्की के किसी अन्य निर्यातक ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। इस कारण से प्राधिकारी ने उचित समायोजन करने के बाद निवल निर्यात कीमत के रूप में अन्य सभी निर्यातकों के लिए सहयोगी निर्यातकों का भारत में निवल निर्यात कीमत की न्यूनतम सांकेतिक राशि को माना है। टर्की के लिए इस प्रकार से निर्धारित प्रस्तावित निवल निर्यात कीमत के ब्यौरे का उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

रूस के सभी निर्यातक

47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रूस के संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक/उत्पादक ने प्राधिकारी को सहयोग नहीं किया है तथा निर्धारित रूप में तथा तरीके से उत्तर नहीं दिया है। रूस के उत्पादकों/निर्यातकों से निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर न प्राप्त होने की वजह से, प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(8) के संबंध में सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। रूस के सभी निर्यातकों के लिए कारखानागत स्तर पर इस प्रकार से निर्धारित प्रस्तावित निर्यात कीमत का उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

ट. पाटन मार्जिन

48. उपर्युक्त सामान्य मूल्य और यथानिर्धारित निर्यात कीमत की तुलना करने पर जांच की अवधि के दौरान तथा जांच की अवधि के बाद संबद्ध देशों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन नीचे दिया गया है:-

जांच अवधि

देश	निर्यातक/ उत्पादक	सामान्य मूल्य अम.डॉ./मीट.	निवल निर्यात कीमत अम.डॉ./मीट.	पाटन मार्जिन अम.डॉ./मीट.	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन % रेंज
टर्की	सोडा सनायी ए.एस	***	***	***	***	20-30
	ई टी आई सोडा	***	***	***	***	0-10
	असहयोगी	***	***	***	***	25-35
रूस	सभी	***	***	***	***	25-35

जांच पश्चात की अवधि

देश	निर्यातक/ उत्पादक	सामान्य मूल्य अम.डॉ./मीट.	निवल निर्यात कीमत अम.डॉ./मीट.	पाटन मार्जिन अम.डॉ./मीट.	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन % रेंज
टर्की	सोडा सनायी ए.एस	***	***	(***)	(***)	नकारात्मक
	ई टी आई सोडा	***	***	(***)	(***)	नकारात्मक
	असहयोगी	***	***	***	***	10-20
रूस	सभी	***	***	***	***	30-35

ठ. क्षति निर्धारण के लिए पद्धति तथा क्षति एवं कारणात्मक संबंध की जांच

आवेदक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

49. इस संबंध में आवेदक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- आयात केवल इस कारण से हो रहा है कि घरेलू उपभोक्ता प्रयोक्ताओं को मजबूर कर रहे हैं। घरेलू उत्पादक जो डाउन स्ट्रीम उत्पादन में संबद्ध वस्तुओं का उपयोग करते हैं, भी आयातित उत्पादों का ही उपयोग करते हैं। अतः पाटनरोधी शुल्क को उस तिथि से वापस लिए जाने की सिफारिश की जा सकती है, जिस तिथि के इस प्रकार के मध्यावधि समीक्षा को शुरू किया गया है।
- घरेलू उत्पादकों ने इस तथ्य का कभी भी खंडन नहीं किया कि क्षमता उपयोग उस मात्रा से अधिक सीमा तक प्राप्त किया जा सकता है जितना इसने प्राप्त किया है। इसका खंडन नहीं किया गया है कि पूर्व के एस सी एल के साथ निरमा ने बी आई एफ आर के समक्ष यह दावा किया है कि एस सी एल का संयंत्र स्कैप की स्थिति में था
- घरेलू उत्पादकों द्वारा इस बात का भी खंडन नहीं किया गया कि जिस कीमत पर वस्तुओं का आयात किया गया, जिन्हें पुनः बेचा गया था, वह आयात के पत्तन पर दर्शाए गए अवतरित मूल्य की तुलना में बहुत अधिक था, जिसके फलस्वरूप एनआईपी और एन एस आर के साथ ऐसे अवतरित मूल्य की तुलना के प्रयोजन से परिवर्तित अवतरित मूल्य तय किया गया है।
- घरेलू उत्पादकों द्वारा अर्जित 20 प्रतिशत-25 प्रतिशत आर ओ सी ई अनुबंध-III के सिद्धांतों को लागू किए बिना वित्तीय रिकॉर्ड से किया गया है, जिसमें कच्चे माल की उपलब्धता न होने के कारण संयंत्र को बंद किए जाने के दौरान हुए अति असाधारण खर्चों को निकाले जाने की अपेक्षा है।
- कीमत में कटौती के लिए घरेलू उत्पादकों का एन एस आर भाड़े को जोड़ने के बाद तय किया गया है। यह उस स्थिति में भी किया गया है, जब निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा अपनाई जा रही रीति के अनुसार निवल बिक्री प्राप्ति घरेलू उत्पादकों के कारखानागत द्वार पर तय की जाती है।
- गुजरात हैवी कैमिकल्स लि0 (जी एच सी एल) लाभ कमाने वाली कंपनी है और यह कि संबंधित उत्पादक और निर्यातक इस जांच में भाग नहीं ले रहे हैं क्योंकि कोई पाटन नहीं हुआ है। घरेलू उत्पादकों ने इस बात से इंकार नहीं किया कि टाटा कैमिकल्स लि0 (टी सी एल) भी लाभ कमाने वाली एक कंपनी है और यह आयातित संबद्ध वस्तुओं की पुनः बिक्री के माध्यम से भारी लाभ अर्जित कर रहा है।
- घरेलू उत्पादकों के गैर कार्यात्मक संयंत्रों को शामिल करने के बाद भी कीमत में कोई ह्रास अथवा उसका न्यूनीकरण नहीं हुआ है। अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि घरेलू उद्योग को कोई हानि नहीं हो रही है।
- घरेलू उद्योग को मात्रा, कीमत के संबंध में कोई क्षति नहीं हो रही है और यह कि ये संयंत्र अपनी सर्वोत्तम क्षमता उपयोग पर कार्य कर रहे हैं। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- एन आई पी, एन एस आर और अवतरित कीमत का अनुमान यह दर्शाता है कि जांच की अवधि में नकारात्मक क्षति मार्जिन हुआ है। जांच की अवधि के बाद भी नकारात्मक क्षति मार्जिन दृष्टिगत है। घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो

रही है, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने की भी कोई संभावना नहीं है।

- x. यह निर्विवादित तथ्य है कि अवतरित मूल्य में अमरीकी डॉलर में निर्यात कीमत में वृद्धि के कारण बहुत अधिक वृद्धि हुई है। घरेलू उत्पादक आयात की गई सामग्री पर निर्भर नहीं है और इस कारण से उन पर अमरीकी डॉलर की तुलना में भारतीय रूपए में हास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार का परिवर्तन स्थायी प्रकृति का होता है और यह अभी से 3 वर्षों से अधिक तक जारी रह सकता है। अतः घरेलू उत्पादकों को क्षति के फिर से होने की दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं है।
- xi. उत्पादन आधार वर्ष में 2391519 मी.ट. से बढ़कर जांच की अवधि में 2405410 मी.ट. हो गया। घरेलू उत्पादकों ने सार्वजनिक सुनवाई के दौरान यह स्वीकार किया है कि उनको कोई क्षति नहीं हो रही है।
- xii. घरेलू उद्योग के कुल निर्यात में बहुत अधिक गिरावट आई है अर्थात् यह वर्ष 2011-12 में 200354 मी.ट. से घटकर वर्ष 2014-15 में 26642 मी.ट. हो गया है, जो घरेलू उत्पादकों दिए गए विवरण को स्पष्ट रूप से असत्य ठहराता है कि घरेलू उत्पादक को माल भंडार को बेचने के लिए अपने निर्यात को जारी रखना है।
- xiii. इस उत्पाद की घरेलू बिक्री 2011-12 में 2006729 मी.ट. से बढ़कर 2014-15 में 2218766 मी.ट. हो गया। हालांकि, कुल बिक्री में आबद्ध खपत एवं निर्यात में तेजी से निर्यात के कारण 2011-12 में 2419438 मी.ट. से मामूली घटकर 2403783 मी.ट. हो गया।
- xiv. सबसे बड़े भारतीय घरेलू उत्पादक "टाटा कैमिकल्स लि०" ने कीनिया में अपनी सहायक कंपनी तथा ई यू और चीन में असंबद्ध उत्पादकों से सामग्री का आयात किया। घरेलू उत्पादक ने दावा किया कि कीनिया से आयातित उत्पाद अपेक्षाकृत निम्न श्रेणी का था और इसकी भारत में घरेलू उत्पादकों की तुलना में कम कीमत है। जिस कीमत पर घरेलू उत्पादकों ने आयात के पश्चात प्रयोक्ताओं को संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की उसकी तुलना निवल बिक्री प्राप्ति और एन आई पी से की जानी चाहिए।
- xv. घरेलू उत्पादकों ने जांच की अवधि और क्षति अवधि के दौरान आदर्शतम क्षमता उपयोग प्राप्त किया। उनके द्वारा दर्शाई गई क्षमता केवल नेम प्लेट क्षमता है, संयंत्र धिसे-पिटे हैं और वे उससे अधिक क्षमता उपयोग प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं, जिस पर वे कार्य कर रहे हैं।
- xvi. अनेक वर्षों तक शुल्क लगाए जाने के बाद भी सोडा ऐश उद्योग ने इस क्षमता को ऐसे स्तरों तक नहीं बढ़ाया जिससे समग्र भारतीय मांग को पूरा किया जा सके। पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य क्षतिकारक पाटन के व्यापार परिवर्तन प्रभावों को समाप्त करना है और न कि घरेलू उद्योग के लिए एकाधिकारवादी स्थिति पैदा करना है।
- xvii. घरेलू उत्पादकों की क्षमता मूल जांच, जो समीक्षा के अधीन है, से नहीं बड़ी है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की क्षमता बढ़ाने के लिए इन संयंत्रों में किए गए निवेश के बारे में दावे की पुष्टि बिना किसी साक्ष्य के नहीं हो सकी है।
- xviii. विस्तार योजनाओं के बारे में, द्विअर्थक रूप में घरेलू उत्पादक प्रयोक्ताओं के खर्च पर भारी लाभ अर्जित करने के लिए संरक्षण मांग रहे हैं। यहां भी घरेलू उत्पादकों ने झूठा दावा किया है। आई एन आर 1250 पी एम टी की आय इस उद्योग के लिए एक औसत आय है। घरेलू उत्पादकों के लिए क्षमताओं का विस्तार करना अथवा नई कंपनी को प्रवेश करने देना आवश्यक नहीं है।
- xix. पाटनरोधी शुल्क के साथ अथवा उसके बिना जांच किए गए आयातों से पिछले दो वर्षों के लिए घरेलू उत्पादकों को कोई क्षति नहीं हुई है, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पाटनरोधी शुल्क जो प्रयोक्ताओं पर अनावश्यक बोझ है, को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- xx. जी एच सी एल जांच की अवधि के दौरान 87 प्रतिशत से अधिक पर कार्य कर रहा है जो इन उद्योगों में अधिकतम संभव क्षमता उपयोग है। जी एच सी एल 850000 मी.ट. की क्षमता के साथ प्रमुख उत्पादकों में से एक है। यह इस व्यापार से बहुत अच्छी लाभ राशि अर्जित कर रहा है। उसके बावजूद इसकी संबद्ध देशों सहित विभिन्न देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात करना मजबूरी है। यह नोट किया जा सकता है कि वे पाटनरोधी शुल्क के भुगतान के बाद इन वस्तुओं का आयात कर रहे हैं और उसकी पुनः बिक्री के माध्यम से पर्याप्त लाभ अर्जित कर रहे हैं।
- xxi. घरेलू उद्योग इन आंकड़ों का चयन कर रहा है जो उनके लिए लाभकारी है। ऐसे दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यद्यपि, आयात हो रहा था, फिर भी वे असाधारण प्रवृत्ति पर कीमतों को बढ़ाते रहे। जैसा कि

दिनांक 2-3-2016 के उनके अनुरोध के माध्यम से घरेलू उद्योग द्वारा सूचित किए गए सही आंकड़ों से देखा जा सकता है, 2013-14 में बिक्री की लागत बढ़कर केवल 111 हुई। परंतु बिक्री कीमतें बढ़कर 117 हो गई। 2014-15 में जब बिक्री की लागत में 1 प्रतिशत बिन्दु अर्थात् 110 तक की गिरावट देखी गई, बिक्री की कीमतों में पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत बिन्दु तक उछाल आया।

- xxii. घरेलू उद्योग की बिक्री प्राप्ति के साथ-साथ निर्यातक देश और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन पर विचार स्थायी प्रकृति की जांच के लिए किया जाना चाहिए क्योंकि संबद्ध वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन विश्व बाजार में दर्शाया गया है और भारत में निर्यात कीमत में वृद्धि एक स्वतंत्र घटना नहीं है।
- xxiii. पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत अनुबंध-III स्पष्ट रूप से यह कहता है कि अन्य स्थान पर भाड़े जो निर्माण खर्च के बाद होते हैं, पर विचार एन आई पी के प्रयोजन से नहीं किया जाएगा। घरेलू उद्योग अब यह दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि उनका तर्क एन आई पी का निर्धारण नहीं है बल्कि क्षति मार्जिन का निर्धारण है, जबकि दोनों एक ही हैं, क्योंकि क्षति मार्जिन पर विचार आयातों के अवतरित मूल्य और कारखानागत स्तरों पर एन आई पी के बीच किया जाता है।
- xxiv. यह दावा कि शुल्कों को एक प्रत्याशित भावी निवेश के रूप में संरक्षित करने के लिए जारी रखा जाना चाहिए, जो किसी ठोस प्रकृति का नहीं है और ऐसे दावों को नहीं माना जा सकता है।
- xxv. उन मामलों में जहां स्वयं क्षति मार्जिन नकारात्मक है, अर्थात् अवतरित मूल्य एन आई पी से अधिक है, कोई पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश प्राधिकारी द्वारा नहीं की जा सकती है। चूंकि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है, अतः पाटनरोधी शुल्क वापस लिया जाना चाहिए।
- xxvi. घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित किए जा रहे अर्जित लाभ का प्रत्यक्ष संबंध इस बात से है कि आयात एन आई पी के बराबर है और इस अंतर का लाभ घरेलू उद्योग द्वारा लिया जा रहा है। ग्राहकों को अपने उद्योगों के लिए अपेक्षित सोडा ऐश की कृत्रिम रूप से बढ़ाई गई कीमत के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो बदले में विभिन्न औद्योगिक और उपभोक्ता मदों पर आगे ले जाया गया होता।
- xxvii. कीमतों में वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विनिमय दर और बढ़ी हुई कीमतों के कारण होती है। घरेलू उत्पादक बड़े हुए अवतरित मूल्य के संबंध में अवमूल्यित रूप से का लाभ उठा रहे हैं, इस तथ्य के कारण उनकी लागतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि घरेलू उत्पादक कच्चे माल का उपयोग कर रहे हैं जो स्वयं भारत में बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है।
- xxviii. आयात कीमत गुजरात में सबसे अधिक है। इस क्षेत्र में उच्च कीमत जहां संबद्ध वस्तु पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और कीमत कम है, जहां आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, भी यह सिद्ध करता है कि खरीदने का निर्णय कीमत की पसंदगी पर निर्भर नहीं है।
- xxix. आयात की मात्रा और कीमतों के बीच कोई संबंध नहीं है और घरेलू उत्पादकों को आयात की मात्रा और कीमतों पर ध्यान दिए बिना भारी मुनाफा हो रहा है। प्रयोक्ता घरेलू उद्योग को संरक्षण की बिना किसी आवश्यकता के पाटनरोधी शुल्क का भुगतान कर रहे हैं।
- xxx. आयातित वस्तु जिन्हें पुनः बेचा गया था, आयात के पत्तन पर दर्शाए गए अवतरित मूल्य की तुलना में बहुत अधिक था जिसके फलस्वरूप एनआई और एन एस आर के साथ ऐसे अवतरित मूल्य की तुलना के प्रयोजनों से परिवर्तित अवतरित मूल्य हुआ।
- xxxi. विदेशी विनिमय दर में वहां बदलाव हुआ, जहां भारतीय रूप से मूल्य में अमरीकी डॉलर की तुलना में बहुत अधिक गिरावट आई। ऐसे परिवर्तनों के संचयी प्रभाव के फलस्वरूप आयात की कीमतों में वृद्धि हुई है।
- xxxii. घरेलू उद्योगों के बंद पड़े संयंत्रों को शामिल करने के बाद भी कीमत में ह्रास और न्यूनीकरण नहीं हुआ, अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि घरेलू उद्योग कोई क्षति नहीं हो रही है।
- xxxiii. जिस प्रकार से घरेलू उद्योग इस जांच की शुरुआत के समय केवल पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के होने के संबंध में साक्ष्य प्रदान करता है और वास्तव में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के लिए साक्ष्य प्रदान नहीं करता है, उसी प्रकार से समीक्षा के मामले में आवेदकों से मात्र यह अपेक्षा है कि वे बदली हुई परिस्थितियों के संबंध में सकारात्मक साक्ष्य देते हुए आवेदन दायर करें।

- xxxiv. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि असयोगी निर्यातों के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण भारत में सूचित निम्नतम कीमतों के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रतिवादी इन अनुरोधों को गलत मानने से इंकार करते हैं और उनका यह अनुरोध है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को क्षति मार्जिन की गणना के लिए औसत भारित कीमत पर विचार करना चाहिए। वर्तमान मामले में संबद्ध देशों से निर्यातकों ने इस जांच में भाग लिया है और घरेलू उत्पादकों का भी इस जांच के अंतर्गत संबद्ध देशों में संबंधित पक्षकार है। इस कारण से क्षति मार्जिन की गणना निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर और न कि भारत में सूचित की गई न्यूनतम कीमत के आधार पर की जाए।
- xxxv. घरेलू उत्पादकों ने यह तर्क दिया है कि प्राधिकारी केवल उन्हीं लेन-देन पर विचार कर सकते हैं जहां क्षति मार्जिन सकारात्मक है। प्रतिवादी घरेलू उद्योग के इन अनुरोधों को गलत मानने से इंकार करते हैं। ऐसे अनुरोध करने का पूर्ण रूप से कोई आधार नहीं है और ऐसा कोई प्रावधान कहीं नहीं है जो केवल सकारात्मक क्षति मार्जिन पर विचार करने की अनुमति देता हो।
- xxxvi. घरेलू उत्पादकों ने यह तर्क दिया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के भावी निवेशों की जांच करने की आवश्यकता है और साथ ही प्राधिकारी को इस बात का विश्लेषण करना चाहिए कि क्या घरेलू उद्योग को कोई ठोस अवरोध पैदा हुआ है। प्रतिवादी इन अनुरोधों को सही नहीं मानने से इंकार करते हैं। प्रतिवादी का यह अनुरोध है कि घरेलू उद्योग यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सार्वजनिक सुनवाई के दौरान भी भारी निवेश किए हैं, हालांकि वे इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए सक्षम नहीं थे कि उन्होंने अपनी क्षमता में सुधार लाने के लिए पाटनरोधी शुल्क को लगाए जाने के बाद कोई निवेश किया था, जबकि संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई थी।
- xxxvii. निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे घरेलू उत्पादकों को उनके द्वारा किए गए आयातों के संबंध में सही तथ्य प्रस्तुत करने के लिए कहें। उनके लिए यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किन कीमतों पर घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं का आयात करते हैं। इसके अलावा, चूंकि घरेलू उत्पादकों के पास उनकी निवल बिक्री प्राप्ति की सूचना है, अतः उन्हें यह भी पता होगा कि क्या उनके द्वारा किए गए आयात निवल बिक्री प्राप्ति से अधिक थे अथवा नहीं। साथ ही घरेलू उत्पादकों को उन कीमतों के बारे में भी बताना चाहिए जिस पर आयातित वस्तुओं को खुले बाजार में फिर से बेचा गया था।
- xxxviii. घरेलू उत्पादक प्रमुख रूप से अपनी संबद्ध वस्तुओं को गुजरात और गुजरात के आस-पास के क्षेत्र में बहुत अच्छी कीमत पर बेचते रहे हैं। यह मान लिया गया है कि घरेलू उत्पादकों को भारी लाभ हो रहा है। कीमत में गिरावट केवल पश्चिम बंगाल में बहुत अधिक होने का उल्लेख किया गया है और यह गिरावट गुजरात और भारत के अन्य भागों में बहुत अधिक नहीं है।
- xxxix. वर्तमान मामले में आयात की मात्रा और कीमतों में कोई संबंध नहीं है और घरेलू उत्पादकों को आयात की मात्रा और कीमतों पर ध्यान दिए बिना बहुत अधिक लाभ हो रहा है। प्रयोक्ता घरेलू उद्योगों को संरक्षण की किसी आवश्यकता के बिना पाटनरोधी शुल्क का भुगतान कर रहे हैं।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

50. घरेलू उद्योग के अनुरोध निम्नानुसार हैं :-

- केवल घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में सुधार पाटनरोधी शुल्क को निरस्त किए जाने के लिए अपर्याप्त आधार है। नियम 23(1) क) प्राधिकारी को घरेलू उद्योग की वर्तमान स्थिति पर केवल ध्यान केंद्रित करने के बजाए घरेलू उद्योग पर शुल्क को निरस्त किए जाने के प्रभाव की जांच करने का अधिकार प्रदान करता है।
- स्थायी प्रकृति का स्पष्ट आशय यह है कि परिस्थितियों में परिवर्तन इस प्रकार से हुआ है कि वे वापस वहां पहुंच सकते हैं, जहां यह पहले था। आयात कीमत में गिरावट स्पष्ट रूप से यह सिद्ध करती है कि यह परिवर्तन स्थायी प्रकृति के नहीं थे और विशुद्ध रूप से यह अस्थायी प्रकृति के थे।
- निर्यातकों के असहयोग के मामले में क्षति मार्जिन का निर्धारण भारत में सूचित की गई निम्नतम कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके अलावा, प्राधिकारी को केवल क्षतिकारक आयातों पर विचार करना चाहिए और उन आयातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो एन आई पी से अधिक पर हुए हैं। नकारात्मक क्षति मार्जिन का मतलब पाटनरोधी शुल्क को वापस लेना नहीं है।

- iv. प्राधिकारी से सर्वप्रथम यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या घरेलू उद्योग को पर्याप्त क्षति हुई है। यदि प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि घरेलू उद्योग को कोई पर्याप्त क्षति नहीं हुई है, तब प्राधिकारी को इस बात की जांच करने की आवश्यकता है कि क्या घरेलू उद्योग को पाटनरोधी शुल्क को समय से पहले वापस लिए जाने की स्थिति में पर्याप्त क्षति हो सकती है। यदि ऐसा नहीं है तब प्राधिकारी को इस बात की अवश्य जांच करनी चाहिए कि क्या विचाराधीन उत्पाद के लगातार पाटन से देश में घरेलू उद्योग को पर्याप्त रूप से अवरोध होने की संभावना सिद्ध होती है।
- v. इस दावे के संबंध में कि घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत 19,000 पीएमटी से अधिक है, सूचीबद्ध आंकड़े दर्शाते हैं कि बिक्री कीमत सुनवाई के समय हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उल्लिखित निवल बिक्री प्राप्ति से बहुत अधिक कम है।
- vi. लेखा खातों के आधार पर नियोजित पूंजी के मुद्दे के संबंध में, निर्धारित प्रपत्र क्षति के जारी रहने और न कि संभावित क्षति एवं क्षति की संभावना के निर्धारण के लिए ही संगत है। क्षति की संभावना के लिए संभावित स्थिति को देखा जाना अपेक्षित है।
- vii. जहां तक भाड़े को शामिल करने के मुद्दे पर रेस जुडीकेटा के सिद्धांत को लागू करने का संबंध है, यह सिद्धांत तभी लागू होता है जब अंतिम निर्णय इस मुद्दे पर लिया जाता है। मूल जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी के समय यथा उठाए गए मुद्दे माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील के रूप में लंबित हैं। अतः यह वर्तमान में भी जीवित और वैध है। समीक्षा के लिए आगे दिए गए आधार में “क्षति मार्जिन कम हो गया है” का उल्लेख है।
- viii. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग भाड़े के बारे में तर्क देते समय स्तह पर दिख रहे क्षति मार्जिन के बारे में बात कर रहा है। जब वास्तव में इसका आशय एन आई पी के निर्धारण से है, गलत है क्योंकि दोनों अलग-अलग पारिभाषिक शब्द हैं। क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए कोई कानून अथवा पद्धति नहीं दी गई है। अनुबंध-III केवल शासकीय सिद्धांतों से संबंधित है।
- ix. जहां तक अपेक्षाकृत कम शुल्क नियम से संबंधित ब्राजील की प्रथाओं पर निर्भरता का संबंध है, यह उपयुक्त है क्योंकि क्षति मार्जिन के निर्धारण के संबंध में दिशानिर्देश न होने पर प्रथा और सिद्धांत बनते रहते हैं। भाड़े का आपत्तन चयनित उत्पादों में महत्वपूर्ण है और इस कारण से इसका विगत में भारी विरोध नहीं किया गया है।
- x. जहां तक अनेक वर्षों तक शुल्क का संबंध है, पाटनरोधी शुल्क 2012 में लगाया गया था। इस उद्योग को 2011-12 में हानि हो रही थी और इसको बहुत कम लाभ हो रहा था और 2013-14 तक इसकी आय बहुत कम थी। शुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हुआ है और बाजार की व्यवहार्यता में बाद में वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप विस्तार योजना कार्यान्वित की जा सकी। मुनाफाखोरी के संबंध में तर्क उन निर्यातकों के लिए दिया जाना चाहिए, जो संभवतः घरेलू बाजार में उपभोक्ताओं को लूट रहे हैं।
- xi. भावी निवेश एक ठोस प्रकृति का है और इसे वापस नहीं लिया जा सकता है। चीन से विशुद्ध सिल्क टाइपराइटर रीबन फैब्रिक्स के आयातों पर ई सी के मामले पर निर्भरता गलत है क्योंकि ये तथ्य अलग-अलग हैं। उत्पाद की मांग बदलती रही थी और अन्य अंतरों के बीच लगभग नौ वर्षों से कोई आयात नहीं हुआ था।
- xii. जहां तक घरेलू उद्योग की अधिक लाभप्रदता का संबंध है, यह देखा गया है कि सोडा ऐश एक अत्यधिक पूंजी सघन, कच्चे माल की निम्न लागत और उच्च तैयार उत्पाद भाड़ा उद्योग है। भाड़े की लागत में उत्पादन की लागत का बहुत अधिक प्रतिशत होता है। इस कारण से इस मामले को विचाराधीन उत्पाद की विलक्षणताओं के आलोक में देखा जाना चाहिए।
- xiii. भारत में निर्यात कीमत में जांच की अवधि के बाद बहुत अधिक गिरावट आई है।
- xiv. सूची कीमतों पर बहुत अधिक छूट दी जा रही है। अतः बिक्री कीमत (छूट से पूर्व) कीमत सूची से बहुत अधिक कम है।
- xv. घरेलू उद्योग की कृत्रिम रूप से बढ़ी हुई कीमतों के वसूलने के तर्क के संबंध में, टर्की में कीमतें और उनके अपने बाजार में लाभ बहुत अधिक हैं, जो घरेलू उद्योग की किसी ऐसी चिंता को दूर करता है।
- xvi. जहां तक रूपए का अवमूल्यन और विनिमय दर के मुद्दे का संबंध है, रूपए के अवमूल्यन का भी प्रभाव घरेलू उत्पादकों पर पड़ा है क्योंकि उन्हें, लाइमस्टोन, कोल, कोक आदि जैसे विभिन्न कच्चे मालों का आयात करना पड़ता है, जबकि विनिमय दर में तब भी बदलाव हुआ है जब उस पर भारतीय रूपए में विचार किया गया है, वर्तमान में हो रहे आयात घरेलू उद्योग की एन आई पी से बहुत अधिक कम है।
- xvii. आबद्ध खपत में गिरावट इस कारण से हुई है कि एक घरेलू उत्पादक कड़ी प्रतिसपर्धा के कारण डाउन स्ट्रीम उत्पाद का उत्पादन नहीं कर सका। इस गिरावट से समग्र खपत पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है और यह घरेलू उद्योग को क्षति का

- कोई कारण नहीं है। डिटरजेंट की समग्र खपत में वृद्धि हुई है और इस प्रकार से डिटरजेंट के उत्पादन के लिए सोडा ऐश की खपत में कोई गिरावट नहीं हुई है।
- xviii. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के घरेलू उद्योग के दावों के क्षमता उपयोग का उत्तर नहीं देने का संबंध है, वास्तव में क्षमता के उपयोग में उच्चतर स्तर तक वृद्धि हुई है।
- xix. इस दावे के लिए कोई साक्ष्य अथवा आधार नहीं है कि एनआईपी और एन एस आर के साथ अवतरित मूल्य की तुलना, पुनः बेची गई आयातित वस्तुओं की कीमत आयात के पतन पर दर्शाए गए अवतरित मूल्य की तुलना में अधिक थी।
- xx. कीमत में कटौती की पद्धति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा इंकार न किए जाने के संबंध में यह सिद्ध हुआ है कि कीमत में कटौती का निर्धारण करने के लिए कोई एक पद्धति नहीं है।
- xxi. आर ओ सी ई के संबंध में, इन संयंत्रों का प्रचालन उद्योग द्वारा किया जा रहा है और इसमें बहुत ह्रास हुआ है, जिससे बहुत कम लाभ प्राप्त हो रहा है। चूंकि निवल निर्धारित परिसंपत्ति घरेलू उत्पादकों के लिए अनुचित है, और यह सही मूल्य को नहीं दर्शाता है, अतः घरेलू उत्पादकों ने आर ओ सी ई की गणना करने के लिए निवेश के वर्तमान मूल्य पर विचार किया है।
- xxii. वित्तीय लेखांकन में माल भंडार के मूल्यांकन पर विचार वर्तमान उद्देश्यों से नहीं किया जा सकता है। यह एन आई पी की विशिष्ट नियमों के अनुरूप नहीं होगा, जिस पर इसमें विचार किया जाना चाहिए।
- xxiii. वर्तमान में घरेलू उद्योग की नियोजित वर्तमान पूंजी नियोजित पूंजी पर आय का निर्धारण करने के लिए उपयुक्त आंकड़े नहीं हैं। नियोजित वर्तमान पूंजी 2994435 मी.ट. की क्षमता के विरुद्ध है जबकि 8 लाख मी.ट. तक क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए *** करोड़ रु० का निवेश किया जा रहा है। यह स्वतः स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि नियोजित वर्तमान पूंजी उद्योग द्वारा अपेक्षित आय का निर्धारण करने के लिए पूर्ण रूप से अपर्याप्त है। घरेलू उद्योग के पास क्षमता 8 लाख टन हो सकती है और न कि 78 लाख टन, जैसा कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा आरोप लगाया गया है।
- xxiv. गुजरात में आयात की कीमत की तुलना की जा सकती है। उत्तर में कीमत तुलनात्मक रूप से अधिक है और गुजरात में आयात का हिस्सा कुल आयात के 5 प्रतिशत से कम है।
- xxv. इस तर्क के संबंध में कि अवतरित मूल्य सिम्पलीसिटर का उपयोग एनआईपी अथवा एन एव आर के साथ क्षति मार्जिन अथवा क्षति का आकलन करने के लिए तुलना करने हेतु नहीं किया जा सकता। यह अनुरोध है कि कीनिया से अधिकांश आयात प्रत्यक्ष तौर पर उपभोक्ताओं द्वारा किए जाते हैं।
- xxvi. जहां तक लाभ के मार्जिन को अनुचित मानने का प्रश्न है, यह अनुरोध है कि कोई भी व्यापारी जो निवेश करता है, वह उचित तौर पर ऐसे लाभ की आशा करेगा। विशेष रूप से रोहित सर्फेक्टेस का निवेश व्यौरा इस बात को सिद्ध करने के लिए प्रत्युत्तर के साथ संलग्न किया गया था।
- xxvii. टर्की और रूस से सोडा ऐश के अंतिम जांच परिणाम पर निर्भरता के संबंध में, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए मूल जांच परिणाम में मै० तूतीकोरिन अल्कली कैमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लि० की क्षमता को शामिल नहीं किया गया क्योंकि यह आवेदक नहीं था और न ही उक्त जांच में घरेलू उद्योग का भाग था। इसके अलावा कंपनी संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन भी नहीं कर रही थी।
- xxviii. कीमत में 20 प्रतिशत के समायोजन के आरोप के संबंध में घरेलू उद्योग ऐसे किसी समायोजन का दावा नहीं करता है।
- xxix. उन संभावनाओं के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं है कि ऐसे ग्रेड हो सकते हैं जिनके स्थान पर किसी अन्य ग्रेड का उपयोग नहीं किया जा सकता।
- xxx. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उत्पादक कुछ क्षेत्रों में आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है और इसलिए आयात पर पाटनरोधी शुल्क नहीं वसूला जाना चाहिए, घरेलू उद्योग का मानना है कि इस कारण से भाड़े को क्षति मार्जिन का निर्धारण करते समय जोड़ा जाना चाहिए।
- xxxi. जहां तक घरेलू उद्योग की कचचे माल की उपलब्धता से निकटता का संबंध है, ऐसी निकटता से उपभोक्ता के हित में लागत में कमी आई है। कच्चे माल पर वहन की गई भाड़े की लागत पर विचार एन आई पी और उत्पादन की लागत के भाग के रूप में किया जा रहा है जिसका वहन उपभोक्ताओं द्वारा किया जा रहा है। उत्पादन की लागत को कीमत से जोड़ कर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने एक तरह से समग्र अर्थव्यवस्थाओं के साथ किसी उपभोक्ता को अपने आप को आदर्शतम स्तर तक लाकर सृजित कार्यक्षमताओं को वापस ले लिया है।

- xxxii. घरेलू उपभोक्ताओं का निवेश करने का गंभीर इरादा है। लाभ की वर्तमान दर पर भी निवेश की वसूली 32 वर्षों में की जाएगी। इसके अलावा, जांच की अवधि के दौरान पाटनरोधी शुल्कों की भारित औसत मात्रा इस पर विचार करते हुए 1290 पीएमटी थी कि निर्यात शुल्क तालिका में नामित निर्यातकों द्वारा किया गया है। इस प्रकार से, यदि घरेलू उद्योग को पाटनरोधी शुल्क का मात्रा तक अपनी कीमत कम करना था, तब अब जो नया निवेश किया जा रहा है, उसकी वसूली 34 वर्षों में की जाएगी। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क की संभावित वापसी का अर्थ इन निवेशों पर गंभीर पुनर्विचार करना होगा।
- xxxiii. आई एच एस ग्लोबल सोडा ऐश सर्विस द्वारा सूचित की गई कीमत विभिन्न देशों/क्षेत्रों में घरेलू बाजारों में संबद्ध वस्तुओं की मौजूदा कीमतों का एक अच्छा संकेत है। इसके अलावा, चूंकि यह जर्नल उच्च और निम्न कीमतों का उल्लेख करता है, अतः घरेलू उत्पादकों ने औसत कीमत को अपनाया है।
- xxxiv. आयात की अवतरित कीमत में वृद्धि 32 प्रतिशत और न कि 56 प्रतिशत थी, जैसा कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किया गया है।
- xxxv. घरेलू उद्योग द्वारा बढ़ाई गई कीमत 65 प्रतिशत की तुलना में 27 प्रतिशत थी, जिसका दावा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया है। देश में उत्पाद के पाटन पर रोक के कारण ऐसा हुआ है।
- xxxvi. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता आयात प्रतिस्पर्धा के कारण दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में बहुत अधिक प्रतिकूल है।
- xxxvii. जांच की अवधि के दौरान समग्र मांग में वृद्धि हुई है। पाटनरोधी शुल्क के लागू रहने के बावजूद जांच की अवधि में आयात में वृद्धि हुई है।
- xxxviii. उत्पादन की तुलना में आयात में भी वृद्धि हुई है और खपत की तुलना में आयात में गिरावट आई है।
- xxxix. पाटनरोधी शुल्क निरस्त किए जाने की स्थिति में कीमत बहुत अधिक सकारात्मक होगी।
- xl. सोडा ऐश के भारतीय उत्पादक कच्चे माल की उपलब्धता के कारण गुजरात राज्य में स्थित हैं। बहुत अधिक ढुलाई लागत के कारण घरेलू उद्योग की बिक्री की कीमत की तुलना ढुलाई लागत को जोड़ने के बाद ही आयात के अवतरित कीमत से की जानी चाहिए।
- xli. प्राधिकारी को इस बात का निर्धारण करना चाहिए कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है। शुल्क को समय से पूर्व वापस लिए जाने से बाजार में कीमत में बहुत अधिक कटौती होने की संभावना है।
- xlvi. लागू पाटनरोधी शुल्कों के साथ कीमत में कोई वर्तमान ह्रास अथवा न्यूनीकरण का प्रभाव नहीं पड़ा है। तथापि, यदि शुल्कों को वापस ले लिया जाएगा, तब पाटन से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर पर्याप्त न्यूनीकरण प्रभाव पड़ेगा।
- xlvi. उत्पादन, क्षमता उपयोग, लाभ, निवेश पर आय, नकदी के प्रवाह के मामले में घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के साथ सुधरने लगा है। शुल्कों को वापस लिए जाने के फलस्वरूप पर्याप्त हानि पुनः होगी।
- xlv. मूल जांच में कारणात्मक संबंध को पहले ही सिद्ध किया जा चुका है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों में पाटनरोधी शुल्क के लागू रहने के बावजूद वृद्धि हुई है।
- xlv. संबद्ध आयात घरेलू कीमतों की तुलना में कम कीमतों पर उपलब्ध है। संबद्ध देशों में उत्पादकों की अतिरिक्त क्षमताएं शुल्कों के निरस्त किए जाने की स्थिति में पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि की संभावना को दर्शाती है।
- xlvi. कीमत में कटौती से उपभोक्ता आयातित माल को पसंद करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग की बिक्री में कमी होने लगती है। इसके फलस्वरूप माल भंडार में वृद्धि होती है जिससे उत्पादन में गिरावट और क्षमता उपयोग में और अधिक गिरावट होती है।
- xlvii. कीमत प्रभाव के संबंध में, कीमत में कटौती के फलस्वरूप एक ऐसी स्थिति पैदा होगी, जिसमें घरेलू उद्योग को कीमत में वृद्धि करने से रोका जा सकता है, जिसके फलस्वरूप लाभप्रदता में कमी आती है। इस कमी के फलस्वरूप अर्जित सकल लाभ में कमी आती है, जिससे नकद लाभ में कमी आती है और उसके फलस्वरूप नियोजित पूंजी पर आय में और अधिक गिरावट आती है।
- xlviii. कच्चा माल का उपयोग और उपयोगिताओं पर विचार विगत में सबसे अधिक प्राप्त स्तरों पर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि खपत में वृद्धि का कारण ऐसे इनपुट के अकार्यक्षम उपयोग नहीं है बल्कि इनपुट की भौतिक परिस्थितियों में अंतर

है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को खपत पद्धति में परिवर्तनों के लिए खपत के इनपुट तथा परिवर्तनों के कारणों पर विचार करना चाहिए ताकि उसे सामान्य स्थिति में लाया जा सके।

- xlix. कैप्टिव इनपुट्स पर विचार बाजार कीमत पर किया जाना चाहिए। वास्तविक कच्चे माल और उपभोक्ता कंपनियों की खपत पर विचार किया जाना चाहिए। उत्पादन की वास्तविक कीमत का निर्धारण उस कीमत का निर्धारण करने के उद्देश्य से उत्पादन की राष्ट्रीय निम्न लागत के बजाए किया जाना चाहिए, जिसकी तुलना क्षति मार्जिन का आकलन करने के उद्देश्य से आयात की कीमत से की जा सकती है।
- i. संबद्ध भाड़े को जोड़ने के बाद आयातों की अवतरित कीमत के साथ संबद्ध भाड़े को शामिल किए बिना घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत की तुलना एक उचित तुलना नहीं होगी और इससे उद्योग द्वारा उठाई जा रही क्षति का आकलन कम होगा।
 - ii. भाड़ा लागत उत्पादन की लागत का एक हिस्सा होता है। घरेलू उद्योग कारखाने से भंडार/वेयर हाउस तक सामानों को ले जाने के लिए भाड़े की लागत का वहन करता है जिससे कारखाने के द्वार तक बढ़ाया जाता है। वस्तुओं का अधिकार उत्पादकों के पास होता है और यह वेयर हाउस से सामग्री के निकाले जाने पर ही खरीददारों को हस्तांतरित हो जाता है।
 - iii. चूंकि सीमाशुल्क को भुगतान न किए जाने पर भी क्षति रहित कीमत के साथ तुलना करने के पूर्व जोड़ दिया जाता है, अतः घरेलू उत्पाद में वहन की जा रही अंतरदेशीय भाड़े को भी अवश्य जोड़ा जाना चाहिए। इसका पालन सफेद सीमेंट के मामले में किया गया था और इसका पालन वर्तमान जांच में भी किया जाना चाहिए।
 - liii. घरेलू उद्योग द्वारा वहन किए गए भाड़े की लागत, विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों और भारतीय उद्योग द्वारा दी गई भुगतान शर्तों में पर्याप्त अंतर जिससे आयात होता है, घरेलू और आयात किए गए उत्पाद के बीच करें और शुल्कों में विसंगतियां होती हैं, वर्तमान एन आई पी कानून की मौजूदगी और उससे उसकी की गई वयाख्या, एन आई पी कानून के मौजूद होने के बावजूद प्रमुख तत्वों के संबंध में कोड वाली प्रथा का अभाव जैसे कारकों पर विचार न करना कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जो संरक्षण स्तर को कम करते हुए पाटनरोधी शुल्कों की मात्रा पर अलग-अलग और सामूहिक रूप से प्रभाव डालते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटनरोधी कानून के तहत हकदार होना चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

51. प्राधिकारी ने क्षति के संबंध में हितवद्ध पक्षकारों के तर्कों और विरोध में दिये गए तर्कों पर विचार किया है। घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-3 के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया गया है।

52. घरेलू उद्योग द्वारा वहन किए गए भाड़े पर क्षति विश्लेषण में एक कारक के रूप में विचार करने के लिए घरेलू उद्योग के तर्कों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि सर्वप्रथम पाटनरोधी नियमावली का अनुबंध-III। इस प्रकार की प्रथा की अनुमति नहीं देता है। इसके अलावा, भाड़े के मुद्दे को शामिल करते हुए सफेद सीमेंट के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी का अंतिम जांच परिणाम सेस्टेट के समक्ष विचाराधीन है, ऐसे ही मामले दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष भी लंबित हैं।

53. यहां नीचे प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण वास्तव में हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।

ड संचयी आकलन

54. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- II के पैरा (iii) में इस उपबंध की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है कि यदि एक से अधिक देश से किसी उत्पाद के हुए आयात के साथ-साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उस स्थिति में ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण करेंगे जब वह यह निर्धारित करें कि:-

- क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में पुष्टिकृत पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से हुए आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात की मात्रा की 3 प्रतिशत से कम है वहां संचयी रूप से आयात समान वस्तु के आयात के साथ सबसे अधिक बनता है; तथा
- ख. आयातित वस्तु एवं समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के मद्देनजर आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण उचित है।

55. इस संबंध में प्राधिकारी यह टिप्पणी करते हैं कि:

- i. संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से पाटन का मार्जिन ऊपर में निर्धारित सीमाओं से अधिक है।

- ii. संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से आयात की मात्रा निर्धारित सीमाओं से अधिक है।
- iii. आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात प्रत्यक्ष तौर पर भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा दी गई समान मदों से प्रतिस्पर्धा करता है। यह निम्नलिखित से स्पष्ट है :
 - क. संबद्ध देशों से उत्पादकों द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तु अपने आप में और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पादों की तुलना में हैं। दूसरे शब्दों में विभिन्न संबद्ध देशों से और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की जा रही संबद्ध वस्तु आपस में समान वस्तु हैं।
 - ख. कुछ साझे पक्षकार हैं जो विभिन्न स्रोतों से आयात की गई सामग्री तथा घरेलू सामग्री के उपयोग का सहारा ले रहे हैं। इस कारण से आयात की गई और घरेलू सामग्रियों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा रहा है तथा घरेलू उत्पाद एवं आयात किए गए उत्पाद के बीच सीधी प्रतिस्पर्धा है।
 - ग. संबद्ध देशों के निर्यातकों और घरेलू उद्योग ने एक ही उत्पाद को एक ही अवधि में समान ग्राहक समूह को बेचा है। बिक्री के रास्ते तुलनीय नहीं हैं।
 - घ. संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश में से आयातों की मात्रा अधिक है।
 - ड. उपभोक्ता विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दी जा रही कीमतों के आधार पर खरीद के संबंध में निर्णय लेते हैं।

56. उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी इसे उपयुक्त मानते हैं कि वह आयात किए गए उत्पाद और समान घरेलू उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में घरेलू उद्योग पर टर्की और रूस से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के प्रभावों का संचयी रूप से आकलन करें। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से पाटन मा मार्जिन और आयुक्तों की मात्रा ऊपर निर्धारित सीमाओं से अधिक है।

57. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में (क) पाटित आयातों की मात्रा और घरेलू बाजार में समान वस्तुओं की कीमत पर पाटित आयातों के प्रभाव, एवं (ख) ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जांच का प्रावधान है। जहां तक पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। जहां तक कि पाटित के कीमत प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कीमत में पर्याप्त कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे उत्पादों के प्रभाव से कीमत में काफी अधिक मात्रा में अन्यथा गिरावट आई है अथवा होने वाली इस वृद्धि में रुकावट आई है जो अन्यथा काफी अधिक स्तर तक बढ़ गई होती।

58. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- II के पैरा (IV) में निम्नानुसार उल्लेख है:

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"

59. भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच के लिए प्राधिकारी ने ऊपर में दी गई नियमावली के अनुबंध-II (IV) के अनुसार ऐसे और सूचकांकों पर विचार किया है, जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, भंडार, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि।

60. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के तथ्यों और तर्कों को वस्तुपरक रूप से विचार करते हुए क्षति के मानदंडों की जांच की है। क्षति के मानदंडों का विश्लेषण करने के लिए, घरेलू उद्योग के तुलन पत्र सहित सभी संगत दस्तावेजों की जांच की गई है और उसका सत्यापन प्राधिकारी द्वारा किया गया है। भारतीय उद्योग के हित से संबंधित मुद्दों और अन्य मुद्दों पर भी विचार प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त शीर्षकों के अंतर्गत किया गया है।

मांग और बाजार हिस्सा

61. संबद्ध वस्तुओं की मांग/घरेलू खपत के आकलन के प्रयोजन से, घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री की मात्रा को भारत में कुल आयात में जोड़ा गया है और उसे संक्षिप्त रूप में नीचे दिया गया है :

विवरण	यूओएम	2011- 12	2012- 13	2013-14	पीओआई	पोस्ट पीओआई	पीओआई पश्चात वार्षिकीकृत
कैपिटल सहित भारत में मांग							
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.ट.	14,31,825	15,19,990	15,78,148	16,01,302	8,22,679	16,45,357
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	110	112	115	115
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	मी.ट.	7,51,493	7,26,475	7,37,588	7,55,169	3,79,582	7,59,164
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	98	100	101	101
कुल घरेलू बिक्री	मी.ट.	21,83,318	22,46,466	23,15,737	23,56,471	12,02,261	24,04,521
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	106	108	110	110
संबद्ध देशों से आयात	मी.ट.	1,10,695	1,19,014	62,103	49,071	19,305	38,611
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	56	44	35	35
आयात-अन्य देश जिन पर शुल्क लागू है	मी.ट.	3,29,828	5,53,416	4,89,270	6,73,706	3,47,389	6,94,779
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	168	148	204	211	211
आयात-अन्य देश	मी.ट.	3,952	19,799	16,214	1,201	1,123	2,246
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	501	410	30	57	57
कुल मांग	मी.ट.	26,27,793	29,38,694	28,83,324	30,80,449	15,70,079	31,40,157
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	110	117	119	119
मांग में बाजार हिस्सा							
घरेलू उद्योग	%	54.49	51.72	54.73	51.98	52.40	52.40
अन्य भारतीय उत्पादक	%	28.60	24.72	25.58	24.51	24.18	24.18
समस्त रूप में भारतीय उत्पादक	%	83.09	76.44	80.31	76.50	76.57	76.57
संबद्ध देश	%	4.21	4.05	2.15	1.59	1.23	1.23
अन्य देश जिन पर शुल्क लागू है	%	12.55	18.83	16.97	21.87	22.13	22.13
अन्य देश	%	0.15	0.67	0.56	0.04	0.07	0.07

62. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान मांग में वृद्धि हुई है। जांच की अवधि के बाद के दौरान भी मांग में बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शायी गई है। घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों का बाजार हिस्सा आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान कम हुआ है। हालांकि, जांच की अवधि के बाद के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से ने बढ़ी हुई प्रवृत्ति वृद्धि दर्शायी है। इसके विपरीत संबद्ध देश का बाजार हिस्सा आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान बहुत कम हो गया है और यह जांच की अवधि के दौरान और अधिक कम हो गया है।

ढ. पाटित आयातों की मात्रा का प्रभाव

आयात की मात्रा और बाजार हिस्सा

63. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी से इस पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या स्वतंत्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पाटित आयातों में अधिक वृद्धि हुई है। क्षति के विश्लेषण के प्रयोजन से प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस से लिए गए आयात आंकड़ों पर विचार किया है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा का विश्लेषण नीचे दिए गए अनुसार किया गया है :-

विवरण	यूओएम	2011- 12	2012- 13	2013-14	पीओआई	पोस्ट पीओआई	वार्षिकीकृत पीओआई पश्चात
आयात मूल्य							
टर्की	मी.ट.	61,670	89,842	62,103	42,114	10,125	20,250
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	146	101	68	33	33
रूस	मी.ट.	49,025	29,171	-	6,957	9,180	18,361
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	60	-	14	37	37
संबद्ध देश	मी.ट.	1,10,695	1,19,014	62,103	49,071	19,305	38,611
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	56	44	35	35

विवरण	यूओएम	2011- 12	2012- 13	2013-14	पीओआई	पोस्ट पीओआई	वार्षिकीकृत पीओआई पश्चात
अन्य देश जिन पर शुल्क लागू है	मी.ट.	3,29,828	5,53,416	4,89,270	6,73,706	3,47,389	6,94,779
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	168	148	204	211	211
अन्य देश	मी.ट.	3,952	19,799	16,214	1,201	1,123	2,246
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	501	410	30	57	57
कुल आयात	मी.ट.	4,44,475	6,92,228	5,67,587	7,23,978	3,67,818	7,35,636
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	156	128	163	166	166
बाजार हिस्सा							
टर्की	%	13.87	12.98	10.94	5.82	2.75	2.75
रूस	%	11.03	4.21	-	0.96	2.50	2.50
संबद्ध देश	%	24.90	17.19	10.94	6.78	5.25	5.25
अन्य देश जिन पर शुल्क लागू है	%	74.21	79.95	86.20	93.06	94.45	94.45
अन्य देश	%	0.89	2.86	2.86	0.17	0.31	0.31
कुल	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से बढ़ती हुई मांग के बावजूद आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक गिरावट आई है। संबद्ध देशों से आयात में जांच की अवधि के बाद के दौरान भी और अधिक गिरावट आई है।

ण. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों की कीमत का प्रभाव

64. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, निर्दिष्ट प्राधिकारी से इस बात पर विचार करने की अपेक्षा है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में अधिक कटौती हुई है अथवा इस प्रकार के आयातों का प्रभाव अन्य प्रकार से कीमतों को काफी हद तक कीमत ह्रास करेगा अथवा कीमत में वृद्धि को रोकगा जो अन्य प्रकार से काफी हद तक बढ़ गई होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत में कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के उद्देश्य से घरेलू उद्योग का उत्पादन की लागत, निवल बिक्री प्राप्ति (एन एस आर) और क्षति रहित कीमत (एन आई पी) की तुलना संबद्ध देशों से आयातों के अवतरित मूल्य से की गई है।

पाटित आयातों का कीमत ह्रास तथा कीमत न्यूनीकरण का प्रभाव:

65. पाटित आयातों का कीमत ह्रास तथा कीमत न्यूनीकरण के प्रभाव की जांच की अवधि तथा जांच की अवधि के बाद की अवधि सहित जांच अवधि की तुलना में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का अवतरित मूल्य, उत्पादन की लागत, निवल बिक्री प्राप्ति के संदर्भ में जांच की गई है।

विवरण	यूओएम	2011- 12	2012- 13	2013-14	पीओआई	पोस्ट पीओआई
संबद्ध आयातों की अवतरित कीमत	रू./मी.ट.	12,099	15,223	14,730	16,508	17,979
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	122	136	149
बिक्री की लागत	रू./मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	110	106	102
बिक्री कीमत	रू./मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	113	123	125

उपरोक्त सूचना से, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयातों की अवतरित कीमत आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान बढ़ी है। जांच की अवधि के बाद के दौरान उसमें और अधिक वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत भी आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान बढ़ गई है। परंतु, घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में वृद्धि संबद्ध देशों से अवतरित कीमत में वृद्धि की तुलना में बहुत कम है। जांच की अवधि के बाद के दौरान जबकि अवतरित कीमत में वृद्धि हुई है, घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में गिरावट आई है।

कीमत कटौती तथा कम कीमत पर बिक्री का प्रभाव**कीमत कटौती**

66. घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति का निर्धारण करते समय, घरेलू उद्योग द्वारा दी जा रही छूट, डिस्काउंट और कमीशन तथा प्रदत्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को घटा दिया गया है। आयातों के अवतरित मूल्य की गणना संबद्ध देशों से निर्यात/सीआईएफ कीमतों, जिसकी सूचना प्रत्येक प्रतिवादी निर्यातक द्वारा दी गई है, में 1 प्रतिशत अवतरण शुल्क और लागू मूल सीमा शुल्क और शिक्षा उपकर को जोड़कर की गई है। अन्य श्रेणियों के लिए अवतरित कीमत की गणना डी जी सी आई एंड एस आंकड़ों के अनुसार आकलनीय मूल्य में लागू मूल सीमाशुल्क और शिक्षा उपकर को जोड़कर की गई है।

विवरण	इकाई	2011- 12	2012- 13	2013-14	पीओआई	पोस्ट पीओआई
टर्की						
आयातों का पहुंच मूल्य	रू./मी.ट.	11,610	15,295	14,730	16,548	19,475
निवल बिक्री प्राप्ति	रू./मी.ट.	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रू./मी.ट.	***	***	***	***	(***)
कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	% रेंज	20-25	0-5	10-15	5-10	Negative
रूस						
आयातों का पहुंच मूल्य	रू./मी.ट.	12,714	15,003	-	16,265	16,330
निवल बिक्री प्राप्ति	रू./मी.ट.	***	***	-	***	***
कीमत कटौती	रू./मी.ट.	***	***	-	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	-	***	***
कीमत कटौती	% रेंज	10-15	5-10		10-15	10-15
समग्र रूप में संबद्ध देश						
आयातों का पहुंच मूल्य	रू./मी.ट.	12,099	15,223	14,730	16,508	17,979
निवल बिक्री प्राप्ति	रू./मी.ट.	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रू./मी.ट.	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	% रेंज	15-20	5-10	10-15	5-10	0-5

67. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान पाटित आयातों की कीमत में कटौती का प्रभाव संबद्ध देशों से अलग-अलग और सामूहिक रूप में आयातों के संबंध में सकारात्मक है। जांच की अवधि के बाद के दौरान जबकि टर्की से कीमत में कटौती नकारात्मक है, लेकिन रूस से यह सकारात्मक है और समस्त संबद्ध देशों से कीमत में कटौती का प्रभाव सकारात्मक है।

कम कीमत पर बिक्री

68. कम कीमत पर बिक्री के प्रयोजन से संबद्ध देशों से आयातों के अवतरित कीमतों की तुलना घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत (एन आई पी) से की गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कम कीमत पर बिक्री जांच की अवधि तथा जांच की अवधि की बाद की अवधि के दौरान नकारात्मक है।

पीओआई

विवरण	पहुंच मूल्य अम.डॉ./मी.ट.	क्षतिरहित कीमत अम.डॉ./मी.ट.	कम कीमत पर बिक्री अम.डॉ./मी.ट.	कम कीमत पर बिक्री %	कम कीमत पर बिक्री % रेंज
Turkey	268.24	***	(***)	(***)	नकारात्मक
Russia	263.65	***	(***)	(***)	नकारात्मक

पोस्ट-पीओआई

विवरण	पहुंच मूल्य अम.डॉ./मी.ट.	क्षतिरहित कीमत अम.डॉ./मी.ट.	कम कीमत पर बिक्री अम.डॉ./मी.ट.	कम कीमत पर बिक्री %	कम कीमत पर बिक्री % रेंज
Turkey	301.52	***	(***)	(***)	नकारात्मक
Russia	252.82	***	(***)	(***)	नकारात्मक

त. घरेलू उद्योग के अन्य आर्थिक मापदंडों की जांच
उत्पादन, क्षमता, बिक्री तथा क्षमता उपयोग

69. उत्पादन, क्षमता और क्षमता उपयोग का विवरण निम्नानुसार है :-

विवरण	यूओएम	2011- 12	2012- 13	2013-14	पीओआई	पोस्ट पीओआई	वार्षिकीकृति पोस्ट पीओआई
स्थापित क्षमता	मी.ट.	19,61,000	19,61,000	19,61,000	19,61,000	10,15,500	20,31,000
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100	52	104
उत्पादन	मी.ट.	15,78,674	16,11,377	16,02,002	16,45,154	8,48,136	16,96,272
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	101	104	54	107
क्षमता उपयोग	%	80.50%	82.17%	81.69%	83.89%	83.52%	83.52%
प्रवृत्ति	मी.ट.	100	102	101	104	104	104
घरेलू बिक्री	सूचीबद्ध	12,67,561	13,86,286	14,66,643	15,03,224	7,68,250	15,36,499
प्रवृत्ति	मी.ट.	100	109	116	119	61	121
मांग	सूचीबद्ध	26,27,793	29,38,694	28,83,324	30,80,449	15,70,079	31,40,157
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	110	117	119	119

उपरोक्त सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के उत्पादन की क्षमता जांच की अवधि सहित क्षति अवधि के दौरान स्थिर रही है। जांच की अवधि के बाद दौरान क्षमता में वृद्धि हुई है। बिक्री और क्षमता उपयोग दोनों मांग में वृद्धि के अनुरूप आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान बढ़ी है। जांच की अवधि के बाद के दौरान जबकि क्षमता के उपयोग में मामूली गिरावट आई है, बिक्री में और अधिक वृद्धि हुई है।

मालसूची:

70. मालसूची को दर्शाने वाले आंकड़े निम्नानुसार हैं :

विवरण	यूओएम	2011- 12	2012- 13	2013-14	पीओआई	पोस्ट पीओआई
प्रारंभिक	मी.ट.	***	***	***	***	***
अंतिम	मी.ट.	***	***	***	***	***
औसत	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	101	73	122

यह नोट किया जाता है कि औसत माल भंडार में पूर्व के वर्षों की तुलना में जांच की अवधि के दौरान अधिक गिरावट आई है। हालांकि औसत माल भंडार ने जांच की अवधि के बाद के दौरान बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शायी है।

लाभ तथा नकदी के प्रवाह पर वास्तविक और संभावित प्रभाव :

71. लाभ/हानि और नकदी के प्रभाव के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि कर और ब्याज पूर्व लाभ तथा नकद लाभ के संबंध में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जांच की अवधि के बाद के दौरान इस स्थिति में और अधिक सुधार हुआ है।

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	पीओआई	पोस्ट पीओआई	वार्षिकीकृति पोस्ट पीओआई
बिक्री की लागत	रु./मी.ट.	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	110	106	102	102
बिक्री कीमत	रु./मी.ट.	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	113	123	125	125
लाभ/हानि	रु./मी.ट.	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	176	146	293	356	356
लाभ/हानि	लाख रूपए	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	193	169	347	216	432
पीबीआईटी	लाख रु0	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	146	133	215	128	256
नकद लाभ	लाख रु0	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	168	153	270	171	342
निवेश पर आय	%	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	141	140	233	279	279

रोजगार, मजदूरी तथा उत्पादकता

72. रोजगार, मजदूरी तथा उत्पादकता से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित दर्शाते हैं :

विवरण	यूओएम	2011- 12	2012- 13	2013-14	पीओआई	पोस्ट पीओआई	वार्षिकीकृति पोस्ट पीओआई
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.ट.	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	99	102	105	105
रोजगार	सं.	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	103	102	102	102
मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	113	117	67	133

यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि और जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या तथा उत्पादकता में मामूली वृद्धि हुई थी। परंतु, आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि तथा जांच की अवधि के बाद के दौरान मजदूरी में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

पाटन का परिमाण

73. ऊपर पाटन मार्जिन से संबंधित धारा से यह देखा जा सकता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के अयातों के संबंध में पाटन मार्जिन जांच की अवधि तथा जांच की अवधि के बाद के दौरान सकारात्मक और पर्याप्त हैं।

वृद्धि :

74. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की वृद्धि जांच की अवधि तथा जांच की अवधि की बाद की अवधि के दौरान सकारात्मक थी।

निधि जुटाने की क्षमता

75. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष से जांच की अवधि तक संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की अपनी क्षमता में वृद्धि नहीं की है। यह इस बात का द्योतक है कि उनकी पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

थ. क्षति तथा क्षति मार्जिन का परिमाण

76. जैसा कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमत की तुलना जांच की अवधि और जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए संबद्ध देशों से निर्यातों का अवतरित मूल्य से किया गया है। इस प्रकार से निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे दिया गया है :-

पीओआई

देश	निर्यातक/ उत्पादक	एनआईपीअम.डॉ./मी.ट.	पहुंच मूल्य अम.डॉ./मी.ट.	क्षति मार्जिन अम.डॉ./मी.ट.	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन % रेंज
टर्की	सोडा सान्यी ए.एस.	***	***	***	(***)	नकारात्मक
	ईटीआई सोडा	***	***	***	(***)	नकारात्मक
	असहयोगी	***	***	***	(***)	नकारात्मक
रूस	समस्त	***	263.65	***	(***)	नकारात्मक

पोस्ट पीओआई

देश	निर्यातक/ उत्पादक	एनआईपीअम.डॉ./मी.ट.	पहुंच मूल्य अम.डॉ./मी.ट.	क्षति मार्जिन अम.डॉ./मी.ट.	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन % रेंज
टर्की	सोडा सान्यी ए.एस.	***	***	***	(***)	नकारात्मक
	ईटीआई सोडा	***	***	***	(***)	नकारात्मक
	असहयोगी	***	***	***	(***)	नकारात्मक
रूस	समस्त	***	252.82	***	(***)	नकारात्मक

प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान तथा जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान संबद्ध देशों के संबंध में क्षति मार्जिन नकारात्मक है। जांच की अवधि तथा जांच की अवधि के बाद के दौरान पाकिस्तान से अलग-अलग सहयोगी निर्यातक के संबंध में भी क्षति मार्जिन नकारात्मक है।

द. पर्याप्त क्षति के संबंध में निष्कर्ष

77. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जबकि उत्पादन की क्षमता जांच की अवधि सहित पूरी क्षति अवधि में स्थिर रही है, घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में उत्पादन, बिक्री की मात्रा, लाभ, नकद लाभ, नियोजित पूंजी पर आय और माल भंडार के मामले में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान बाजार हिस्से में गिरावट आई है। जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान आर्थिक मानदंडों ने बाजार हिस्से में बड़ी हुई प्रवृत्ति सहित लगातार सुधार दर्शाया है। इसके अलावा, निवल बिक्री प्राप्ति जांच की अवधि तथा जांच की अवधि के बाद के दौरान संबद्ध देशों से अवतरित कीमत से अधिक है। इसके अलावा, जबकि कीमत में कटौती और कम कीमत में बिक्री के प्रभाव नकारात्मक हैं और कीमत ह्रास तथा न्यूनीकरण का प्रभाव जांच की अवधि तथा जांच की अवधि के बाद के दौरान नहीं था। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की आर्थिक हालत में बहुत अधिक सुधार तथा जांच की अवधि के बाद के दौरान लगातार सुधार किसी पर्याप्त क्षति को नहीं दर्शाता है।

ध. अन्य ज्ञात कारक तथा कारणात्मक संबंध

78. पर्याप्त क्षति की मौजूदगी की जांच करने के बाद, घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों का इसकी कीमत में कटौती, कम कीमत पर बिक्री और कीमत ह्रास तथा कीमत न्यूनीकरण के प्रभावों, पाटनरोधी संबंधी भारतीय नियमावली और करार के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य सांकेतिक मानदंडों के संबंध में मात्रा और कीमत के प्रभाव की जांच प्राधिकारी द्वारा यह देखने के लिए की गई है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर कोई अन्य कारक घरेलू उद्योग को निम्नलिखित के अनुसार क्षति पहुंचा सकता था :-

(क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों को छोड़कर अन्य देशों से तथा उन देशों से जिन पर, पाटनरोधी शुल्क लगता है, संबद्ध वस्तुओं का आयात बहुत कम मात्रा में हुआ है।

(ख) मांग में संकुचन तथा खपत की पद्धति में परिवर्तन

प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान मांग में कोई कमी नहीं आई है। इसके विपरीत संबद्ध वस्तुओं की समग्र मांग में जांच की अवधि तथा जांच की अवधि के बाद के दौरान सुधार हुआ है।

(ग) प्रौद्योगिकी में विकास

प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितवद्ध पक्षकारों ने प्रौद्योगिकी में व्यापक परिवर्तनों, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी, को दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

(घ) विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा की व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु का आयात स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं का प्रमुख उत्पादक है और इसका घरेलू उत्पादन और बिक्री काफी मात्रा में होती है। इसके अलावा इस बात को छोड़कर कि यह बाजार अर्थव्यवस्था से स्पष्ट है कि घरेलू उत्पादकों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा दृष्टिगोचर नहीं है।

(ङ.) घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य निष्पादन

निम्नलिखित तालिका घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन को उनके द्वारा किए गए निर्यात के संबंध में संक्षिप्त में दर्शाती है :-

विवरण	यूओएम	2011- 12	2012- 13	2013-14	पीओआई	पोस्ट पीओआई	वार्षिकीकृत पोस्ट पीओआई
निर्यातक	मी.ट.	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	28	34	14	4	8

प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान बहुत तेजी से गिरावट आई है। हालांकि जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य निष्पादन ने जांच की अवधि की तुलना में कुछ सुधार दर्शाया है लेकिन वह आधार वर्ष के दौरान कार्य निष्पादन से बहुत कम रहा है।

79. उपर्युक्त विश्लेषण से प्राधिकारी नोट करते हैं कि न तो सूचीबद्ध ज्ञात मानदंड और न ही ऊपर में विश्लेषण किए गए अन्य कारक जांच की अवधि के दौरान अथवा जांच की अवधि के बाद के दौरान घरेलू उद्योग को कोई क्षति दर्शाते हैं। घरेलू उद्योग के आर्थिक स्वास्थ्य में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के लगातार पाटन के बावजूद आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग का जांच की अवधि के बाद का कार्य निष्पादन भी सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है। हालांकि, घरेलू उद्योग पर क्षतिकर प्रभाव के बिना लगातार पाटन के परिदृश्य को दर्शाता है।

घ. क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना

80. समीक्षा जांच में, प्राधिकारी को इस बात का निर्धारण करना है कि क्या संबद्ध वस्तु का भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर आना जारी है अथवा इसके पाटनरोधी शुल्कों को वापस लिए जाने की स्थिति में संबद्ध देशों से पाटित कीमतों पर निर्यात किए जाने की संभावना है। यहां यह भी जांच करना संगत होगा कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति, यदि शुल्क हटा लिया जाता है अथवा उनकी दरों में परिवर्तन किया जाता है, तब इन पाटित आयातों के कारण पुनः होने की संभावना है। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध II (vii) के अनुसार वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मापदण्डों पर विचार करते हुए पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच की जिसका उल्लेख नीचे किया गया हैरू

“वास्तविक क्षति की आपका का निर्धारण तथ्यों पर आधारित होगा और न कि आरोप, निराधार कल्पना या सुदूर संभावना पर। परिस्थितियों में परिवर्तन जिनसे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिनमें पाटन से क्षति होगी, स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए और असन्नवर्ती होने चाहिए। वास्तविक क्षति के खतरे की मौजूदगी के संबंध में निर्धारण करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे कारकों पर विचार करेंगे और;

- (क) भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की अधिक दर जिससे आयातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता हो।
- (ख) निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य, या आसन्नवर्ती, पर्याप्त वृद्धि जिनसे किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में पाटित निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता हो।
- (ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर हो रहे हैं, जिनसे घरेलू कीमतों पर काफी ह्रासकारी या न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा और इनसे अधिक उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है तथा
- (घ) उस वस्तु की वस्तु सूची की जांच की जा रही हो”

आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

81. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध निम्नलिखित है :

- i. उन परिस्थितियों, जिनमें पाटनरोधी शुल्क निर्यातक पर लगाया गया था, बहुत स्थायी प्रकृति का पर्याप्त परिवर्तन हुआ है और इस स्थिति में मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों को वापस लेना आवश्यक है क्योंकि घरेलू उद्योग को क्षति उस स्थिति में जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना नहीं है, यदि वर्तमान शुल्कों को हटा लिया जाता है या उनकी दरों में परिवर्तन किया जाता है।
- ii. घरेलू उत्पादकों का यह मानना कि यदि पाटन बंद हो जाता है, अथवा पाटन के फिर से होने की कोई संभावना नहीं है, तब शुल्क वापस नहीं लिया जा सकता है, सही नहीं है। यदि घरेलू उद्योग को क्षति अथवा क्षति की संभावना मौजूद नहीं है, तब शुल्क को वापस लेना कानूनी रूप से अपेक्षित है।
- iii. घरेलू उद्योग ने उन साक्ष्यों के आधार पर इस अनुरोध का निष्कर्ष के तौर पर खंडन नहीं किया है कि घरेलू उद्योग को क्षति, यदि उक्त पाटनरोधी शुल्क को हटाया जाता है अथवा उसकी दरों में परिवर्तन लाया जाता है, तब जारी रहने अथवा पुनः होने की संभावना नहीं है और इस कारण से यह अब आवश्यक नहीं रह गया है जो यह दर्शाता है कि कोई संभावना भी नहीं है।
- iv. यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि संबद्ध देशों में निर्यातकों के पास पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्र रूप से बेचने योग्य अथवा आसन्न, पर्याप्त वृद्धि निर्यातक की क्षमता में हो रही है, जो यह दर्शाती हो कि भारतीय बाजारों में पर्याप्त रूप से बढ़े हुए निर्यात होने की संभावना है।
- v. वर्तमान मामले में प्रमुख मापदंड जैसे आयातों का अवतरित मूल्य, क्षति रहित कीमत और क्षति मार्जिन में बहुत अधिक परिवर्तन हुए हैं, उपर्युक्त तथ्य स्वयं जांच की शुरुआत के लिए पर्याप्त आधार है और आगे यह सिद्ध करता है कि घरेलू उद्योग को क्षति मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों को हटाए जाने की स्थिति में जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना नहीं है।
- vi. घरेलू उत्पादकों को असहयोगी के रूप में माना जा सकता है और जांच की अवधि के शुरू होने की तिथि से तत्काल शुल्क को वापस लिया जाए। घरेलू उद्योग आयात की मात्रा और मूल्य से प्रभावित नहीं होता है, और इसलिए यदि पाटनरोधी शुल्क वापस लिया जाता है, तब क्षति होने अथवा उसके पुनः होने की कोई संभावना नहीं है। यह तथ्य कि प्रमुख घरेलू उत्पादक भी संबद्ध वस्तुओं का आयात कर रहे हैं, इस निष्कर्ष का समर्थन करता है कि पाटनरोधी शुल्क को लगातार लगाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- vii. टर्की से संबद्ध वस्तुओं की कीमत में बहुत अधिक वृद्धि हुई है और मात्रा में कमी आई है और जिस कीमत पर संबद्ध वस्तुओं का आयात किया गया था, उससे घरेलू उद्योग पर कोई क्षतिकारक प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इस प्रकार से शुल्क के वापस लिए जाने की स्थिति में पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की कोई संभावना नहीं है।
- viii. ईटीआई सोडा 90 से 100 प्रतिशत के उपयोगिता स्तर पर चल रहा है, जो आदर्श स्तर से अधिक है। कंपनी को इसके द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के लिए बहुत अधिक मात्रा और कीमत स्तर मिल रहा है और पी टी आई सोडा न तो किसी मात्रा के दबाव में है और न ही कोई आसन्न नए अतिरिक्त मात्रा की उपलब्धता का खतरा है। कंपनी कोई अधिक माल भंडार स्तर भी नहीं रख रही है। माल भंडार कंपनी द्वारा कुल उत्पादन के 1 प्रतिशत से कम थी।
- ix. जिस परिस्थिति में पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था, उसमें घरेलू उद्योग को बिना किसी क्षति तथा फिर से होने की संभावना के बिना स्थायी प्रकृति के व्यापक परिवर्तन हुए हैं। इस कारण से शुल्क को वापस लिए जाने की आवश्यकता है।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

82. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- i. याचिकाकर्ता संभावना के संबंध में सूचना देने के लिए बाध्य हैं और यह प्राधिकारी को इस संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य देने में असफल रहा है। जांच को शुरू करने की मांग करते समय संगत मानदंडों के संबंध में साक्ष्य होना चाहिए।
- ii. घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता के विस्तार के संबंध में, निर्दिष्ट प्राधिकारी कृपया इस बात की जांच करें कि क्या पाटनरोधी शुल्क को वापस लेने से क्षमताओं, जिन्हें पहले ही स्थापित किया गया है और प्रचालन संबंधी क्षमताएं जिन्हें अब तक स्थापित नहीं किया गया है और जो निकट भविष्य में चालू हो जाएंगी, दोनों के संबंध में घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।
- iii. पूर्व की जांच और वर्तमान जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन अधिक है। पर्याप्त सकारात्मक पाटन और क्षति मार्जिन अपने आप में पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता को सिद्ध करता है।
- iv. वर्तमान में आयात की कीमतों में मूल जांच के समय प्रचलित स्तरों से नीचे तक गिरावट आई है। ये कीमतें क्षति मार्जिन के निर्धारण के संबंध में घरेलू उद्योग के विभिन्न तर्कों पर विचार किए बिना भी घरेलू उद्योग की एन आई पी से कम है। यह दर्शाता है कि परिस्थितियों में कथित परिवर्तन बहुत ही क्षणिक प्रवृत्ति के थे और वे स्थायी प्रकृति के नहीं थे।
- v. पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत में कटौती सकारात्मक और बहुत है जो स्पष्ट संभावना को दर्शाता है।
- vi. वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति दर्शाती है कि विचाराधीन उत्पाद में बाजार की स्थिति में सुधार होने की संभावना नहीं है। पाटनरोधी शुल्क को रद्द किए जाने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से बहुत कम कीमत पर आयात करना पड़ेगा। अतः उपभोक्ता आयात किए गए उत्पाद का उपयोग करना शुरू करेंगे जिसके फलस्वरूप उत्पाद के आयातों में बहुत अधिक वृद्धि होगी।
- vii. घरेलू उद्योग द्वारा क्षमताओं के विस्तार में बहुत अधिक लागतों का वहन किया गया है जिसे जोड़े जाने की प्रक्रिया जारी है। पाटनरोधी शुल्क को वापस लिए जाने की स्थिति में क्षति की संभावना का निर्धारण करते समय इस पर विचार किया जाना चाहिए। यदि घरेलू उद्योग इस उत्पाद को उस कीमत पर बेचता है जो जांच की अवधि के दौरान प्रचलित थी, तब घरेलू उद्योग को नए निवेशों पर घाटा उठाना पड़ेगा।
- viii. संभावना के उद्देश्यों के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण वर्तमान और संभावित उत्पादन के लिए एन आई पी की भारित औसत के आधार पर किया जाना चाहिए अर्थात् विस्तार पर विचार किया जाना चाहिए।
- ix. हिंदुस्तान लीवर के संबंध में सेस्टेट का निर्णय संगत नहीं है क्योंकि इसे अस्वीकार कर दिया गया है और जिंदल स्टेनलैस लिमिटेड के संबंध में सेस्टेट के निर्णय पर विश्वास करना भी भ्रामक होगा, क्योंकि क्षति की संभावना का कोई साक्ष्य नहीं था और न ही इस तथ्य के संबंध में कोई तर्क दिया गया था।
- x. एंथ्रीलिक फाइबर मैन्युफैक्चरर्स फॉर्म के मामले पर निर्भरता भी भ्रामक है क्योंकि इस मामले के विपरीत अवतरित मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत अथवा क्षतिरहित कीमत के स्तर से बहुत अधिक नहीं है। ऐसे कई अन्य मानदंड हैं, जो पाटनरोधी शुल्क को वापस लिए जाने की स्थिति में पाटन और हानि के पुनः होने की संभावना को सिद्ध करते हैं।
- xi. स्वयं पाटनरोधी शुल्क के लगाने से ई टी आई पोस्ट द्वारा आयात की कीमत में वृद्धि के साथ-साथ निर्यात में गिरावट यह दर्शाती है कि कंपनी बिना पाटन के निर्यात नहीं कर सकती है। केवल परिस्थितियों में परिवर्तन से यह आवश्यक नहीं होता है कि पाटनरोधी शुल्क को समय से पहले हटा दिया जाए।
- xii. यह तर्क कि ई टी आई के पास कोई माल भंडार नहीं है, क्योंकि यूरोप में टाटा कैमिकल की उत्पादन सुविधा के बंद होने के कारण बाजार उपलब्ध है। क्षमता के किसी विस्तार का दावा सही नहीं है। कंपनी पर सार्वजनिक अनुसंधान यह दर्शाता है कि कंपनी यूरोप में सोडा ऐश की सबसे बड़ी उत्पादक बनने का प्रयास कर रही है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

83. भारत की पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 में प्राधिकारी से यह अपेक्षा है कि वह समय-समय पर शुल्क को लगातार लगाने की आवश्यकता की जांच करे। इस संबंध में प्राधिकारी नीचे दिए गए अनुसार नोट करते हैं :-

जांच की अवधि के पश्चात निर्यात की मात्रा

84. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना की जांच करने के उद्देश्य से प्राधिकारी ने जांच की अवधि तथा जांच के बाद की अवधि के दौरान भी संबद्ध देश से भारत में संबद्ध वस्तुओं के निर्यात की मात्रा का विश्लेषण किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि तथा जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध देशों से निर्यात की मात्रा डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों के आधार पर 49071 मी.ट. और 38611 मी.ट. (वार्षिकीकृत) थी, जो निर्यात में गिरावट को दर्शाता है क्योंकि जांच की अवधि के बाद के दौरान भी पाटन मार्जिन सकारात्मक है। लेकिन पाटन कीमतों पर भी केवल निर्यात में वृद्धि वास्तव में यदि ऐसे आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना नहीं हो, पाटनरोधी शुल्क को लगातार लगाने का औचित्य बताते हुए एक संभावित स्थिति को नहीं दर्शाता है।

भारतीय बाजार में संबद्ध देशों का बाजार हिस्सा

85. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक गिरावट हुई है और जांच की अवधि के बाद के दौरान भी गिरावट की प्रवृत्ति जारी रही। इसके विपरीत घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में भी आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है परंतु यह जांच की अवधि के बाद के दौरान बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शा रहा है। इस प्रकार से यह स्थिति दर्शाती है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर संबद्ध देशों से आयातों का प्रभाव नहीं पड़ा है।

भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता

86. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से अवतरित मूल्य एन आई पी से अधिक है। हालांकि कीमत में कटौती जांच की अवधि तथा जांच की अवधि के बाद संबद्ध देशों से सकारात्मक है। कम कीमत पर बिक्री का प्रभाव जांच की अवधि तथा जांच की अवधि के बाद नकारात्मक है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्कों को हटाए जाने की स्थिति में भारतीय कीमतें विदेशी उत्पादकों के लिए बहुत अधिक आकर्षक नहीं रहेगी और इसकी कोई संभावना नहीं है कि भारतीय उपभोक्ता पर्याप्त मात्रा में बढ़ती हुई मांग के कारण आयात करेंगे।

विदेशी उत्पादकों का निर्यात उन्मुखीकरण

87. यदि संबद्ध देश निर्यातोन्मुख भी हों, तब स्वयं संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों के बीच निर्यातोन्मुखीकरण तब तक एक मजबूत संभावना का कारक नहीं हो सकता है, जब तक उसके समर्थन में अनुकूल बाजार स्थितियां न हों और भारत में कमजोर घरेलू उद्योग न हो। यद्यपि, भारत में संबद्ध वस्तुओं की बहुत अधिक मांग है, फिर भी भारतीय बाजार में प्रचलित कीमत तथा मजबूत घरेलू उद्योग आधार संबद्ध देशों के लिए इन शुल्कों को निरस्त किए जाने की स्थिति में भारतीय बाजार की ओर लक्ष्य करने के लिए अनुकूल नहीं हो सकता है।

वर्तमान और विगत पाटन मार्जिन का स्तर

88. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान मूल जांच तथा वर्तमान एमटीआर में पाटन मार्जिन सकारात्मक है। वर्तमान जांच की जांच अवधि के बाद, टर्की के सहयोगी निर्यातकों के संबंध में पाटन मार्जिन नकारात्मक है, परंतु समस्त देश के रूप में यह सकारात्मक है। रूस के मामले में पाटन मार्जिन जांच की अवधि तथा जांच की अवधि के बाद के दौरान सकारात्मक है। परंतु किसी भी परिमाण का पाटन का तब तक भारतीय पाटनरोधी कानून के अंतर्गत कोई संगतता नहीं है जब तक इससे घरेलू उद्योग को क्षति नहीं होती हो। वर्तमान जांच में जांच की अवधि तथा जांच की अवधि के बाद की अवधियों के दौरान क्षति मार्जिन नकारात्मक है, जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं पहुंची है और इन शुल्कों को हटाए जाने की स्थिति में भी घरेलू उद्योगों को क्षति होने की कोई संभावना नहीं है।

89. इस जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार जांच के आवश्यक तथ्य पर्याप्त रूप से यह सिद्ध करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का लगातार पाटन होने के बावजूद, घरेलू उद्योगों की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और जांच की अवधि के पश्चात के दौरान और अधिक सुधार होगा। इस प्रकार से जैसा कि आवेदक द्वारा कहा गया है, बदली हुई परिस्थितियां क्षणिक नहीं हैं बल्कि यह शुल्कों को निरस्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग के पक्ष में रहेगी।

90. याचिकाकर्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई और प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई पत्र प्रकटीकरण टिप्पणियां निम्नलिखित हैं :

- i. प्राधिकारी द्वारा सुनवाई का कोई वास्तविक अवसर नहीं दिया गया था।
- ii. घरेलू उद्योग अच्छी तरह से निष्पादन कर रहा है और अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा एडी शुल्क का दुरुपयोग किया जा रहा है। यदि लागू पाटन-रोधी शुल्क समाप्त किया जाता है अथवा परिवर्तित किया जाता है तो घरेलू उद्योग के लिए क्षति जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसलिए प्राधिकारी को पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने की सिफारिश करनी चाहिए।

- iii. संबद्ध देशों के लिए प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सामान्य मूल्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुसार नहीं हैं।
- iv. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा संबद्ध देश से आयातों से अप्रभावित रहा है। घरेलू उद्योग के निष्पादन से सभी आर्थिक प्राचलों के संबंध में सुधार हुआ है।
- v. आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में संबद्ध वस्तुओं की मांग में 17% तक वृद्धि हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग की क्षमता वही बनी रही है। इसलिए आयात केवल बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए बढ़ा है जिसे घरेलू उद्योग पूरा करने में सक्षम नहीं है।
- vi. इस प्रकार भारत में आने वाले आयात के लिए कारण ही मांग-आपूर्ति अंतर की उपस्थिति है। विशेष रूप से बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग की असक्षमता के परिणामस्वरूप आयात के अलावा प्रयोक्ता के पास कोई विकल्प नहीं बचा है।
- vii. आयात उन कीमतों पर हो रहा है जो कि घरेलू उद्योग की अंडरकटिंग अंडरसेलिंग कीमतें नहीं है और घरेलू उद्योग की कीमतें शमित अथवा मंद निषेधात्मक अथवा निराशाजनक नहीं है। इसलिए संबद्ध देशों से आयात के संबंध में कोई ऋणात्मक कीमत प्रभाव नहीं है।
- viii. प्राधिकारी के लिए यह निष्कर्ष निकालने का कोई कारण नहीं है कि संबद्ध देश से आयातों के संबंध में क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है। इसलिए घरेलू उद्योग को भारी क्षति और आगे घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति की कोई संभावना नहीं होने के कारण संबद्ध वस्तुओं पर लगाए गए शुल्क को बंद कर दिया जाना चाहिए।

घरेलू उद्योग के सुधरे हुए निष्पादन को ध्यान में रखते हुए क्षति तथा क्षति के संभावित नहीं होने के कारण पाटनरोधी शुल्क का निरसन किया जाना चाहिए।

91. घरेलू उद्योग द्वारा की गई और प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई पञ्च प्रकटीकरण टिप्पणियां निम्नलिखित हैं:

- i. घरेलू उद्योग ने यह सिद्ध किया है कि पाटनरोधी शुल्क के वापस लिए जाने की स्थिति में क्षति की काफी संभावना थी। तथापि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सिद्ध करने की संभावना का दायित्व याचिकाकर्ताओं के स्थान पर घरेलू उद्योग पर डाल दिया है। संपूर्ण कानूनी आधार जिस पर वर्तमान जांच शुरू की गई है और जांच की गई है, एडी नियमावली के नियम 23 के विरुद्ध है।
- ii. प्रकटीकरण विवरण के लिए टिप्पणियां दायर करने के लिए उपलब्ध कराया गया समय बहुत कम है।
- iii. मूल जांच में पाटन मार्जिन के साथ-साथ वर्तमान एमटीआर धनात्मक है और वर्तमान जांच की पञ्च पीओआई में पाटन मार्जिन भी धनात्मक है। इस प्रकार पाटन रोधी के समयपूर्व वापस लिए जाने की स्थिति को पाटन न केवल जारी रहेगा बल्कि बढ़ जाएगा। यह निष्कर्ष कि जब तक किसी मात्रा के पाटन पाटनरोधी कानून के अंतर्गत कोई संबद्धता नहीं है तब तक घरेलू उद्योग के लिए यह क्षति कानूनी रूप से सही नहीं है।
- iv. प्राधिकारी ने संबंधित घटकों और प्राचलों को ध्यान में रखते हुए आकर्षक कीमत निर्धारित की है। आकर्षक कीमत तुलनात्मक विश्लेषण है। इसलिए, संबद्ध देशों से निर्यात कीमत अन्य प्रत्येक देश के लिए निर्यात की मात्रा जोकि एनआईपी से कम है तथा निर्यात की मात्रा एनआईपी से अधिक है, का पता लगाने के लिए जांच किए जाने की आवश्यकता है।
- v. आयात में वृद्धि, निर्यातक देशों के साथ पर्याप्त अधिशेष क्षमताएं होने से पाटनरोधी शुल्क के समाप्त किए जाने की स्थिति में मूल्यहास से पर्याप्त कम कीमत होती है। इसके साथ-साथ इससे पाटनरोधी शुल्क के समयपूर्व समाप्त किए जाने की स्थिति में क्षति की संभावना पाटन के बढ़ने होने की संभावना को स्पष्ट रूप से सिद्ध करती है। क्षति मार्जिन मानदण्ड क्षति के निर्धारण के लिए लागू नहीं किए जा सकते।
- vi. प्रकटीकरण विवरण संबद्ध देशों से प्रत्येक अन्य देश को निर्यातों के संबंध में क्षति की संभावना की जांच किए बिना जारी किया गया है।
- vii. प्राधिकारी को पाटित लेन-देन दर लेन-देन आधार पर पृथक-पृथक और गैर-पाटित से क्षति आयात मात्राओं तथा आयातों की उतराई कीमतों के साथ निर्यात कीमत और एनआईपी के साथ सामान्य मूल्य की तुलना के आधार पर गैर क्षति और उसके बाद पाटन और क्षति मार्जिन की गणना करनी चाहिए।
- viii. प्रमुख संबद्ध देशों (विशेष रूप से चीन और टर्की) के उत्पादकों के पास भारी मात्रा में बिना प्रयोग की गई क्षमताएं हैं। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क के वापस लिए जाने की स्थिति में उन उत्पादकों के भारत में अच्छे बाजार अवसरों का पता लगाए जाने की संभावना है और प्राधिकारी द्वारा निर्धारित एनआईपी से कम कीमत पर काफी मात्रा में निर्यात किए जाने की संभावना है क्योंकि निर्यातक पहले ही अन्य देशों में इस प्रकार की कम कीमतों पर विक्रय कर रहे हैं। इसलिए प्राधिकारी को विभिन्न अन्य देशों में निर्यातकों के व्यवहार और उनके पास प्रयोग नहीं गई क्षमताओं की जांच करनी चाहिए।

- ix. पर्याप्त निवेश करने के पश्चात घरेलू उद्योग द्वारा पर्याप्त क्षमता अभिवृद्धि की जा रही है। प्राधिकारी को इस बात की जांच करनी चाहिए कि उन क्षमताओं जो पहले से ही संस्थापित हैं और पहले से ही प्रचालनरत हैं और उन क्षमताओं जो अब तक संस्थापित नहीं की गई हैं और जो निकट भविष्य में प्रचालनरत हो जाएंगी, दोनों के संबंध में घरेलू उद्योग को क्षति के कारण पाटनरोधी शुल्क को वापिस लिए जाने की संभावना है, प्राधिकारी को जांच करनी चाहिए।
- x. अनुबंध-III के तहत लागू किया गया एनआईपी कानून केवल एनआईपी के निर्धारण से संबंधित है जबकि प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया है कि निष्पक्ष तुलना के सिद्धांतों को क्षति मार्जिन निर्धारित करते समय लागू नहीं किया जा सकता। यह पक्षपातपूर्ण है क्योंकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विगत कई जांचों में निष्पक्ष तुलना के सिद्धांतों को लागू किया है और वर्तमान घरेलू उद्योग के विरुद्ध पक्षपात करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- xi. प्राधिकारी ने इस बात पर गलत ढंग से विचार किया है कि माल भाड़े का संवर्धन गैर क्षति कीमत (एनआईपी) के निर्धारण से संबंधित मुद्दा है। किसी सीमा तक यह निष्पक्ष तुलना का मुद्दा है।
- xii. निष्कर्ष के लिए कोई कानूनी आधार नहीं है, क्योंकि अनुबंध-III केवल एनआईपी के निर्धारण तक ही प्रतिबंधित है और क्षति मार्जिन के निर्धारण से संबंधित नहीं है। निष्पक्ष तुलना के सिद्धांतों के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को निष्पक्ष तरीके से घरेलू उद्योग की कीमतों की आयात कीमतों से तुलना किए जाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से घरेलू उद्योग आयातों से प्रतिस्पर्द्धा का सामना कर रहा है और वह स्तर जिस पर घरेलू उद्योग आयातों से प्रतिस्पर्द्धा का सामना कर रहा है, की अवहेलना नहीं की जा सकती है। अनुबंध-I में उल्लिखित निष्पक्ष तुलना के सिद्धांत, सूचक सिद्धांत हैं जिनका पाटन मार्जिन के निर्धारण के संदर्भ में क्षति की सीमा अथवा क्षति के मार्जिन के निर्धारण के लिए अनुपालन किए जाने की आवश्यकता है।
- xiii. प्राधिकारी को उस रिट याचिका के निर्णय का इंतजार करना चाहिए जिसमें यह मामला 3 अक्तूबर, 2016 को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। नियम 17 में उल्लिखित समय-सीमा जांच शुरू किए जाने की तारीख से 18 माह है और इसलिए इस जांच को पूरा करने के लिए प्राधिकारी के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध है।
- xiv. प्राधिकारी ने अनुबंध-III में दिए गए सिद्धांत को गलत ढंग से लागू किया है और किसी परिस्थिति को प्रकट किए बिना एनआईपी को अत्यधिक घटा दिया है।
- xv. अनुबंध-III क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए निष्पक्ष तुलना के सिद्धांतों पर विचार करने और लागू करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता जबकि स्वयं अनुबंध-III केवल एनआईपी निर्धारण पर ही प्रतिबंध लगाता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

92. याचिकाकर्ताओं, घरेलू उद्योगों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई, प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई पत्र प्रकटीकरण टिप्पणियों की नीचे दिए अनुसार जांच की गई है :

- i. कुछ हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क कि सुनवाई का कोई वास्तविक अवसर नहीं दिया गया, के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों को 1 मार्च, 2016 को हुई जन सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। वे पक्षकार जिन्होंने मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत किए थे, को लिखित में अनुरोध प्रस्तुत करने और उसके बाद प्रत्युत्तर देने के लिए कहा गया था। मौखिक सुनवाई तथा प्राधिकारी द्वारा संगत माने जाने पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत लिखित अनुरोधों और प्रत्युत्तरों की जांच की गई है और इस निष्कर्ष में ध्यान रखा गया है।
- ii. कुछ हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क कि संबद्ध देशों के लिए प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सामान्य मूल्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुसार नहीं है, के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों के संबंध में सामान्य मूल्य संगत नियमों तथा डीजीएडी में प्रक्रिया के अनुरूप तथा अपनाई गई पद्धति के अनुरूप निर्धारित किए गए हैं और इस निष्कर्ष के संबंधित पैराओं में पर्याप्त ढंग से स्पष्ट कर दिए गए हैं।
- iii. घरेलू उद्योग के इस तर्क कि प्राधिकारी ने संभावना सिद्ध करने का दायित्व अनुपयुक्त ढंग से याचिकाकर्ताओं के स्थान पर घरेलू उद्योग पर डाल दिया है के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि अपने तर्कों को सिद्ध करना दोनों पक्षकारों का दायित्व है।
- iv. घरेलू उद्योग के इस तर्क कि प्रकटीकरण विवरण पर टिप्पणियों के लिए प्राधिकारियों द्वारा कम समय दिया गया था, के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी जांच समयबद्ध है और निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी जानी होती है। फिर भी वर्तमान मामले की समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटीकरण विवरण पर टिप्पणियां देने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रकटीकरण विवरण में यह स्पष्ट किया गया था कि चूंकि पाटनरोधी जांच समयबद्ध है इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी आगे समय बढ़ाने के लिए किसी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।

- v. घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि मूल जांच के साथ-साथ वर्तमान एमटीआर में पाटन मार्जिन धनात्मक है और वर्तमान जांच के पश्चात् पीओआई में पाटन मार्जिन भी धनात्मक है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क के समयपूर्व वापस लिए जाने की स्थिति में पाटन न केवल जारी रहेगा, बल्कि बढ़ेगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन स्वतः जब तक कार्रवाई योग्य नहीं है तब तक क्षति का कारण हो। पाटन की किसी भी मात्रा का पाटनरोधी कानून के अंतर्गत किसी भी मात्रा में पाटन का कोई संबंध नहीं है जब तक कि यह घरेलू उद्योग के लिए क्षति का कारण न हो।
- vi. घरेलू उद्योग के इस तर्क कि पाटित आधार पर किए गए लेन-देन दर लेन-देन में अंतर किया जाना चाहिए और गैर-पाटित से क्षतिपूर्ण आयात मात्रा और गैर-क्षति में अंतर होना चाहिए, के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि सुझावित कार्रवाई को शून्य किया जा सकता है और इसलिए प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता।
- vii. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि प्रमुख संबद्ध देशों (और विशेष रूप से, चीन और टर्की में) के उत्पादकों के पास बिना प्रयोग की गई भारी क्षमताएं हैं और पाटनरोधी शुल्क वापस लिए जाने की स्थिति में इन देशों से निर्यात के पाटित कीमतों पर बढ़ने की संभावना है, घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है। प्राधिकारी ने पीओआई के लिए डब्ल्यूटीए में उपलब्ध आंकड़ों का अध्ययन किया है और नोट करते हैं कि अन्य देशों के लिए संबद्ध देशों की औसत कीमतें घरेलू उद्योग के एनआईपी से अधिक है, इसका अभिप्राय है कि शुल्क के निरसन की क्षति में इस प्रकार की कीमतों पर अन्य देशों से आयात से घरेलू उद्योगों को क्षति नहीं हो सकती।
- viii. घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्राधिकारी को इस बात की जांच करनी चाहिए कि उन क्षमताओं जो पहले से ही संस्थापित हैं और पहले से ही प्रचालनरत हैं और उन क्षमताओं जो अब तक संस्थापित नहीं की गई है और जो निकट भविष्य में प्रचालनरत हो जाएंगी, दोनों के संबंध में घरेलू उद्योग को क्षति के कारण की संभावना पाटनरोधी शुल्क को वापस लिया जाना है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षमता विस्तार से संबंधित कोई भी आंकड़ा घरेलू उद्योग की लेखा बहियों में विधिवत रूप से प्रदर्शित होना चाहिए, ऐसा नहीं किए जाने की स्थिति में इस प्रकार के आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया जा सकता।
- ix. घरेलू उद्योग के इस तर्क कि अनुबंध-III के तहत लागू किया गया एनआईपी कानून केवल एनआईपी के निर्धारण से संबंधित है और कोई निष्पक्ष तुलना के लिए नहीं है, के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि कुछ पाटनरोधी जांचों के संबंध में एनआईपी मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायाधीन है और इसलिए कोई टिप्पणी करना उपयुक्त नहीं होगा।
- x. घरेलू उद्योग के इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी ने संगत कारकों और मापदंडों पर विचार किए बिना कीमत आकर्षण निर्धारित किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड एटलस (डब्ल्यू टी ए) में उपलब्ध सूचना के अनुसार तीसरे देशों को संबद्ध देशों की औसत पहुंच कीमत भारत को उनकी कीमत से उच्चतर स्तर पर है अतः यदि शुल्क हटाया जाता है तो संबद्ध देश बड़ी मात्रा में भारत को वस्तुओं की आपूर्ति नहीं करेंगे क्योंकि उनकी कीमतें उतनी आकर्षक नहीं हैं जितनी उन्हें अन्य देशों से अन्यथा प्राप्त होती हैं।
- xi. उद्योग के इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी ने संगत कारकों और मापदंडों पर विचार किए बिना कीमत आकर्षण निर्धारित किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड एटलस (डब्ल्यू टी ए) उपलब्ध सूचना के अनुसार तीसरे देशों को संबद्ध देशों की औसत पहुंच कीमत तुलनीय कीमत पर है और इसलिए यदि शुल्क हटाया जाता है तो संबद्ध देश भारत को उनकी वस्तुओं की आपूर्ति नहीं करेंगे।

93. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के स्रोत के रूप में संबद्ध देशों की अन्य देशों की निर्यात कीमतों के प्रभाव की संभावना का विश्लेषण किया है, यदि उक्त देश शुल्क के निरसन की स्थिति में भारत को उस कीमत स्तर पर संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करते हैं। पीओआई अवधि के डब्ल्यूटीओ आंकड़ों और एफओबी मूल्य पर 0.5% ट्रांजिट बीमा, भारत को प्रत्येक संबद्ध देश से समुद्री माल-भाड़ा, 1% पत्तन प्रभार, सीमा शुल्क के 7.5 % और सीमा शुल्क के उपकर के 3% के अनुसार शेष विश्व को संबद्ध देशों द्वारा निर्यात की भारित औसत एफओआर कीमत के आधार पर भारत को संबद्ध देशों से निर्यात की उतराई कीमत की गणना की गई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत और तीसरे देशों को तुर्की से प्रतिवादी निर्यातकों की कीमतें तुलनीय स्तर पर हैं तथापि, डब्ल्यू टी ए आंकड़ों में उपलब्ध भारित औसत एफओबी कीमत तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती है क्योंकि वह प्रतिवादी निर्यातकों की कीमतों की तुलना में असामान्य रूप से कम पाई गई है। अतः तीसरे देशों को निर्यात के लिए तुर्की का क्षति विश्लेषण नहीं किया गया है। रूस के लिए भारत को रूस से आयातों की सीआईएफ कीमत और डब्ल्यू टी ए आंकड़ों के अनुसार संबद्ध वस्तु की भारत को रूस की निर्यात कीमत (एफओबी) के बीच अंतर पर भाड़ा और बीमा ज्ञात करने के लिए विचार किया गया है। तदनुसार जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों द्वारा तीसरे देश की पहुंच कीमत के आधार पर भारत को संबद्ध वस्तु के उनके निर्यातों के संभावित क्षति मार्जिन की गणना डब्ल्यू टी ए आंकड़ों के आधार पर यथोक्त ढंग से निम्नानुसार की गई है :-

तीसरे देशों को निर्यात के लिए क्षति मार्जिन						
संबद्ध देश	यूओएम	पहुंच कीमत	एनआईपी	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन %	रेंज
टर्की	यूएसडी/अमडा	-	-	-	-	-
रूस	यूएसडी/अमडा	295.12	***	(***)	(***)	नकारात्मक

उपरोक्त उल्लिखित सूचना दर्शाती है कि पीओआई के दौरान भारत को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की उतराई कीमत, अन्य देशों की गणना की गई निर्यात कीमतों के आधार पर घरेलू उद्योग की गैर-क्षति कीमत (एनआईपी) से काफी अधिक है, इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी शुल्क के निरसन की स्थिति में संबद्ध देशों द्वारा संबद्ध वस्तुओं का निर्यात उन कीमतों जिन पर वे अन्य देशों को निर्यात कर रहे हैं, घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं होगा।

V. निष्कर्ष

94. ऑल इंडिया ग्लास मेनुफेक्चर्स फेडरेशन (एआईजीएमएफ) द्वारा दायर आवेदन, तथा उठाए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के जरिए प्राधिकारी के पास उपलब्ध तथ्यों अथवा अन्यथा इस निष्कर्ष में रिकार्ड किए अनुसार के आधार पर वर्तमान समीक्षा शुरू करने और किए जाने तथा चालू तथा संभावित पाटन एवं क्षति की स्थिति के विश्लेषण के आधार पर एवं पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना के आधार पर प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे हैं :

- तथापि लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद पाटन जारी है और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पाटन पीओआई के दौरान धनात्मक है, इसलिए घरेलू उद्योग की मात्रा, कीमतों और लाभप्रदता पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पीओआई के दौरान एवं पीओआई के पश्चात नहीं है।
- अंडरकटिंग एवं अंडरसेलिंग दोनों पीओआई तथा पीओआई के पश्चात ऋणात्मक हैं।
- पीओआई के दौरान तथा पीओआई के पश्चात क्षति मार्जिन ऋणात्मक है।
- पीओआई के दौरान संबद्ध देशों द्वारा अन्य देशों के निर्यात की आधार कीमतों पर संभावित क्षति मार्जिन भी ऋणात्मक है।
- कीमत में वृद्धि और कीमत में कमी का प्रभाव नहीं है।
- घरेलू उद्योग के लगभग सभी मात्रा प्राचल और कीमत प्राचल पीओआई के दौरान तथा पीओआई के पश्चात धनात्मक है और घरेलू उद्योग के निष्पादन में लंबी अवधि के लिए उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
- तथापि पाटन करने वाले देश, न तो घरेलू उद्योग की क्षति का कारण है और न ही पाटनरोधी शुल्क के निरसन की स्थिति में संभावित क्षति का कारण हैं।

इसलिए, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यदि संबद्ध देशों के मूल की अथवा से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति होने की पुनरावृत्ति की कोई संभावना नहीं है।

ब. सिफारिश

95. इस निष्कर्ष के पश्चात कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और यदि शुल्क का निरसन किया जाता है तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं को पाटित आयात के कारण क्षति की पुनरावृत्ति की कोई संभावना नहीं है, प्राधिकारी का मत है कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क के लगाए रखने को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और उसे वापस लिए जाने की आवश्यकता है।

96. प्राधिकारी ने पूर्व में भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-I, खण्ड-I में प्रकाशित अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना सं. 14/17/2010-डीजीएडी दिनांक 17 फरवरी, 2012 के तहत संबद्ध देश के मूल की अथवा से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी और केंद्र सरकार की अधिसूचना सं. 34/2012-कस्टम्स (एडीडी) दिनांक 3 जुलाई, 2012 के तहत निश्चित शुल्क लगाया था। उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी इसे आवश्यक समझते हैं और संबद्ध देशों के मूल की अथवा के निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के निरसन की सिफारिश करते हैं।

भ. आगे की प्रक्रिया

97. इस अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना से उत्पन्न केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार, सीमाशुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

ए. के. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd September, 2016

Final Findings**Subject : Mid-term Review (MTR) Anti-dumping investigation concerning imports of 'Soda Ash', originating in or exported from Turkey and Russia.**

No. 15/17/2015-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter referred as the Rules);

A. Background of the case:

1. Whereas, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), had notified its final findings vide Notification No.14/3/2011-DGAD dated 9th February 2013, recommending imposition of definitive anti-dumping duties on the imports of "Soda Ash" (hereinafter referred to as the subject goods, or product under consideration or Disodium Carbonate), originating in or exported from Turkey and Russia (hereinafter referred to as the subject countries). The definitive anti- dumping duties were imposed by the Central Government vide Notification No. 08/2013 – Customs (ADD) dated 18th April 2013.
2. Whereas, the All India Glass Manufacturers' Federation (AIGMF), a representative body of importers/users of the subject goods, hereinafter referred to as the applicant, submitted an application requesting for initiation of a midterm review of the anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods from the subject countries in accordance with section 9A of the Customs Tariff Act 1975 read with Rule 23 of the Rules. They have claimed that the circumstances that were prevalent during the period of investigation of the original investigation have changed significantly leading to a situation where the existing anti-dumping duties are no longer warranted.
3. Whereas, the applicant has submitted that the import prices of the subject goods have increased significantly; that domestic selling prices have also increased significantly; that the cost of major raw materials have also increased, but not in proportion to the increase in the prices of the imports of the subject goods from the subject countries. The applicant has further submitted that coupled with a significant increase in import prices leading to an increase in the landed value of imports, the injury margin has come down and as a consequence, a need for reviewing the current level of duties has arisen.
4. And Whereas, Rule 23 of the Rules read with Section 9A of the Act require that the Designated Authority shall review the need for the continued imposition of any anti-dumping duty, wherever warranted, on its own initiative or upon request by any interested party who submits positive information substantiating the need for such review, and a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty and upon such review, the Designated Authority shall recommend to the Central Government for its withdrawal, where it comes to a conclusion that the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur, if the said anti-dumping duty is removed or varied and is therefore no longer warranted.
5. Having regard to the information provided by the applicant, substantiating the need for such review and indicating changed circumstances, necessitating a review of the measure in force, the Authority, vide Notification No. 15/17/2015-DGAD dated 1st October, 2015, initiated the present Mid-term Review (MTR) investigation of the final findings notified vide Notification No. 14/3/2011-DGAD dated 9th February 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary Part I, Section I and the definitive duties imposed by the Central Government vide Notification No. 08/2013 – Customs (ADD) dated 18th April 2013 to review the need for continued imposition of the anti-dumping duties.
6. Earlier, vide Notification No. 15/28/2014-DGAD dated 21st July, 2015, the Authority had initiated another MTR investigation for the same POI and involving the same domestic industry in respect of imports of the subject goods, originating in or exported from China PR, EU, Kenya, Pakistan, Iran, Ukraine and USA.

B. Procedure

7. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

- i. The Authority sent copies of the initiation notification dated 1st October, 2015 to the embassies of the subject countries in India, known exporters from the subject countries, known importers and other interested parties, and the domestic producers, as per available information. The known interested parties were requested to file the questionnaire responses and make their views known in writing within the prescribed time limit.
- ii. Copies of the letter and questionnaires sent to the exporters were also sent to embassies of the subject countries along with a list of known exporters/producers, with a request to advise the exporters/producers from the subject countries to respond within the prescribed time.
- iii. Copy of the non-confidential version of the application filed on behalf of the applicant was made available to the known exporters, domestic producers and the embassies of the subject countries in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules.
- iv. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating the MTR to the following known producers/exporters in the subject countries and gave them opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rules 6(2) & 6(4) of the Rules:

Soda Sanayii A.S. Turkey TurkiyeSiseVe Cam Fabrikalari A.S. Is Kuleleri, Kule – 334330 4, Levent Istanbul Turkiye
ETI Soda, Ciner Group, Pasalimani Cad No. 4, Uskudar 34674, Istanbul Turkey
SASS SODA ASH SALES & SERVICES M. Tolmachevskiy per. 10 Office 7, 8 119017 Moscow Russia
JSC Bashkirian Chemistry 8, B PoluyaroslavsiyPereulok, Moscow, 105 120, Russia

- v. In response to the initiation of the subject investigation, following producers/exporters from Turkey have responded by filing questionnaire response and made submissions:
 - i. Soda Sanayii A.S.
 - ii. ETI Soda.
- vi. Questionnaires were sent to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Anti-dumping Rules:

Gujarat Guardian Ltd, Village- Kondh, Valia Road, Plant Sate Highway No.13, Ankleshwar, Bharuch 393001
Float Glass India Ltd., T-7, Midc, Industrial Area, Taloja, Maharashtra
Hindustan National Glass & Ind. Ltd., Rishra, West Bengal
Procter & Gamble Hygiene & Health Care, Mandideep Plnt L&C-MFG, Plot No.182, Mandideep, Madhya Pradesh
Advatecg Industries Pvt Ltd, Dhanali, Village –Dhanali, Al-Kadi Distrcit, Mahesana, Gujarat
U.P. Glass Manufacturer, Syndicate, 14-Monapuram, Near Ganesh Nagar, Firozabad-283203, U.P.
Fena (P) Ltd, A-237, Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi-20
Pollachi Chamber of Commerce & Industry, RP Complex, IInd floor, 14, Balagopalapuram Street, Pollachi-642001
Power Soap Ltd, 62-B, North Boag Road, T. Nagar Chennai – 600017

Alembic Glass Industries Ltd, Alembic Road, Baroda (Vadodara) Gujarat
Deepak Nitrite Ltd, 4/12, Chemical Complex, GIDC, Nanfessari, Baroda (Vadodara) Gujarat
Hindustan Unilive Ltd., Party Address Dakshina Building, 8th Floor, Plot No-2 Sector-11, CBD Belapur, Navi Mumbai
Albright Morarji & Pandit Ltd, Ambernath, Dist. Thane, Maharashtra
Saint-Gobain Glass India, Head Office and Plant: A-1 SIPCOT Industrial Park, Sriperumbudur-602105, Kanchipuram District – Tamil Nadu
Asahi India Glass Ltd., 5th Floor, Tower-B, Global Business Park, Mehrauli-Gurgaon Road, Gurgaon-122002 (India)
Shree Union Organics P Ltd, BS-3, Apeejay. 130, Bombay Samachar Marg, Mumbai-23
Vasundhara Rasayan Ltd, C-104, MIDC Industrial Area, Mahed, Dist. Raigad, Maharashtra
Shantinath Detergents Pvt Ltd, P-15, Kalakar Street, Kolkata-700007
Advance Home & Personal Care Ltd, Advance Surfactants India Ltd, 511/2/1, Village Rajokri, New Delhi-38
S. Kumar Detergent P. Ltd, Plot No. 34, Sector-2, Industrial Area, Pithampur-454775 Distt Dhar, M.P.
Hind Silicates Pvt Ltd., 3A, Auckland Place, 5th floor, Kolkata-17
P & J Cretechem (P) Ltd, 318, Swapnalok, 92/93, SD Road, Secunderabad-500003, AP, India
J.J. Patel Industries, Gondal Road, B/H Rajkamal Petrol Pump, Vavdi, Rajkot-360004
Modern Glass Industries, Coal Siding Road, S.N. Road, Firozabad-283203
Sandeep Organics Pvt Ltd., 104, Nain Krupa, 118/122, Kazi Syeed, Street, Masjid Bunder (West), Vadgadi, Mumbai -400003
Alembic Glass Industries Ltd., Alembic Road, Baroda (Vadodara) Gujarat
Rohit Surfactants(P) Ltd., 117/H-2/202, Pandu Nagar, Kanpur-05
BDJ Glass Industries Pvt. Ltd, 1 Kyd Street, Place Court, 1 st Floor, Suite-14-A, Kolkata-700016
Jagatjit Industries Ltd., Plot No.78, Sector-18, Institutional Area, Gurgaon-122001
Haldyn Glass Gujarat Ltd., 9, Gayatri Commercial Complex, Behind Mittal Industrial Estate No. 5, Andheri Kurla Road, Marol Naka, Andheri(E), Mumbai-400059
Hipolin Limited, Madhuban", 4 th Floor, Ellisbridge, Ahmedabad-380006
Modern Glass Industries, Coal Siding Road, S.N. Road, Firozabad-283203
Detergent Manufacturers, Association (Delhi Region) 148, New Okhla Industrial Complex-1, New Delhi-110020
Mauli Exports, Plot No.97-98, Sector – 25, Part-II, Industrial Area, HUDA, Panipat – 132 104, Haryana
M/s Chempex International, 393/III/6 Bazer, Bikanerian, Katra, Ahluwalia, Amritsar, Punjab
Tata Chemicals Ltd., Leela Business Park, Andheri Kurla Road, Andheri (E), Mumbai -59

M/s Tuticorin Alkali Chemicals and Fertilizers Ltd., 534, Anna Salai, Teynampet, Chennai -18
AGI Glasspac, Glass factory Road, Moti Nagar, Post Box. 1930, Shanth Nagar, Hyderabad – 500 018
Power Soaps Ltd., A-8, 1st Main Road, Ambattur Industrial Estate Chennai – 600 058
Hindcon Chemicals (P) Ltd., 62/B, Braunfled Row, 1st floor, Calcutta – 700 027
Empire Industries Ltd., Empire House, 414, Senapati Bapat, Lower Parel, Mumbai – 13

- vii. In response to the above notification, following importers/users have filed importer questionnaire response and made submissions.
- Gold Plus Glass Industry Limited
 - Gujarat Borosil Ltd
 - HNG Float Glass Limited
 - HSIL Limited, Packaging Products Division
 - La Opala Rg Limited
 - Piramal Glass Limited
- viii. Questionnaires were also sent to the known domestic producers of the subject goods in India for necessary information and response.

M/s DCW Ltd
M/s GHCL Ltd
M/s Nirma Ltd
M/s Saurashtra Chemicals Ltd
Tata Chemicals Ltd

- ix. Initiation notification was also sent to the following associations:

Detergent Manufacturers Association
Indian Chemical Merchants & Manufacturers Association
Bulk Drug Manufacturers Association(India)
Indian Glass Manufacturers' Association
The Dyers & Chemical Merchants Association
All India Glass Manufacturer's Federation
Alkali Manufacturers Association of India
Indian Soap & Toiletries Maker's Association

- x. Apart from the respondent producers/exporters, importers/users, domestic producers and their representatives, the following parties also made submissions during the course of this investigation:
- Detergent Manufacturers Association of India
 - Detergent Manufacturers Association (Delhi Region)
 - Bengal Soaps and Detergents Manufacturers Welfare Association
 - Indian Home & Personal Care Industry Association
 - Hindustan Unilever Ltd

- vi. Sandeep Organics Ltd
- vii. RSPL Ltd
- viii. Asoka Enamel and Glass Works Pvt Ltd.
- ix. Indian Council of Small Industries
- x. All India Glass Manufacturers Federation
- xi. Saint Gobain Glass India Ltd.
- xii. Ministry of Trade & Industry of Russian Federation
- xiii. Embassy of Republic of Turkey.
- xi. Exporters, producers and other interested parties who have not responded to the Authority, nor supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating interested parties.
- xii. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange for details of imports of subject goods for the past three years, including the period of investigation. The Authority has, therefore, relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis.
- xiii. Optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry. The NIP has been determined by the Authority in terms of the principles laid down under Annexure III to the Anti-dumping Rules.
- xiv. Investigation was carried out for the period starting from 1st April, 2014 to 31st March, 2015 (POI). However, injury examination was conducted for a period from 2011-12, 2012-13, 2013-14 and the POI. The Authority also called relevant information/data from the interested parties for post POI (1st April 2015 to 30th Sep. 2015) for conducting likelihood analysis.
- xv. In accordance with Rule 6(6) of the Anti-dumping Rules, the Authority also provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 1st March, 2016. The parties, which presented their views in both the oral hearings, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- xvi. The submissions made by the interested parties during the course of the investigation have been considered by the Authority, wherever found relevant, in this finding. Verification to the extent deemed necessary was carried out in respect of the information & data submitted by the domestic industry.
- xvii. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xviii. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded the disclosure on the basis of available facts.
- xix. *** represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xx. The average exchange rate of 1US\$ = Rs 61.69 prevailing during the POI has been adopted by the Authority in this finding.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE:

8. The Product under Consideration (PUC) in the original investigation as well as in the present review is 'Soda Ash'. In the original investigation the product was defined as under:

"i. The product under consideration in the present investigation is Disodium Carbonate, also known as Soda Ash having chemical formula Na_2CO_3 . Soda Ash is produced in two forms- Light Soda Ash and Dense Soda Ash. The difference in the two types is bulk density. It can be produced through synthetic route and natural route, known as dissolution process. The present investigation includes all types and forms of Soda Ash.

ii. Soda Ash is an essential ingredient in the manufacture of detergents, soaps, cleaning compounds, sodium based chemicals, float glass, container and specialty glasses, silicates and other industrial chemicals. It is also widely used in textiles, paper, metallurgical industries and desalination plants. Soda Ash is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act under subheading No. 2836.20. The customs classification is, however, indicative only and is not binding on the scope of the present investigation."

9. None of the importers, consumers, exporters, domestic industry and other interested parties has made any comment or submissions with regard to product under consideration and like articles. The applicant submitted that they have no issues regarding the product under consideration and like article. In view of the above, the scope of the product under consideration in the present review investigation remains the same as that in the original investigation.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

Submissions made by the Petitioner and other interested parties

10. The following submissions have been made by the applicant and other interested parties with regard to standing and scope of the domestic industry:
- i. Concerned domestic producers claiming themselves to be domestic industry are themselves big importers of subject goods from the subject countries. Wholly owned subsidiaries of certain domestic producers have also exported subject goods to India significantly. Domestic producers categorically admitted that for supplying customers of southern and eastern India they are predominantly relying on imports. Therefore such domestic producers are not eligible for becoming domestic industry as per anti-dumping rules.
 - ii. The largest Indian domestic producer "Tata Chemicals Ltd." imported material from its subsidiary from Kenya and from unrelated producers from EU and China.
 - iii. Nirma has acquired wholly owned companies in other countries and importing subject goods from those companies. Designated Authority should examine whether low price of import may have been compensated in price received by Nirma.
 - iv. GHCL is also importing from other producers/exporters. GHCL has more than 87% capacity utilization in the period of investigation which is maximum for these industries. GHCL is a major producer with capacity of 8,50,000 MT and it has compulsion to import subject goods from various countries including subject countries. They are paying Anti Dumping Duty while importing subject goods and still they are earning profits.
 - v. Saurashtra Chemicals Ltd. (SCL) is already amalgamated with Nirma and does not exist as legal entity/company.
 - vi. Tuticorin Alkali Chemicals & Fertilizers Ltd is the smallest and the most inefficient member of the domestic producers in terms of production. It suspends its production again and again because of non-availability of raw material CO_2 .
 - vii. Only DCW is a small player having the capacity of about 3,00,000 MT per year. It is utilizing the capacity at higher rate and earning profit. Such a company is not entitled for any continued protection.
 - viii. Neither the so-called domestic industry, nor the Authority, has clarified which of the domestic producers constitute domestic Industry" in terms of Rule 2(b) of anti-dumping rules before the oral hearing was held.

Submissions made by Domestic Industry

11. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to standing of the domestic industry:
- i. Barring GHCL and Tata Chemicals, none of the companies have themselves imported the subject goods during the POI.

- ii. The imports by GHCL were only to maintain market presence in order to afford continuity when enhanced capacities are made available.
- iii. GHCL had a related company in Romania which is now closed. Nirma has a related producer in USA, which has exported Soda Ash to India during the POI. However, the exports have been directly made by the company.
- iv. DCW does not have any related producer-exporter outside India.
- v. Tata Chemicals has a related producer in Kenya, US and Europe. The Kenyan company is a subsidiary of Tata Chemicals which has exported goods to India. These exports have been directly made by Tata Chemicals. TCL may be considered as ineligible domestic industry if it is deemed fit.
- vi. There are many reasons for imports by domestic industry. Firstly the landed price is materially below the price at which domestic producers can sell in these regions. Secondly, the near future expansion of capacities requires prior creation of demand which is being done by supplying imported product to these consumers. Thirdly very nominal profits have been earned on these imports. Fourthly, duties were recommended without including freight which should have been included to ensure fair comparison.
- vii. Anti-dumping duties are on non discriminatory basis and if the domestic producers have imported the product under consideration they have paid applicable anti-dumping duty.
- viii. As regards hearing being ineffective, it was incumbent upon the applicant importer association to identify the domestic industry and thereafter establish no injury and no likelihood therein.
- ix. The capacity of Nirma shown is including the capacity of SCL. SCL was a separate entity in the beginning of the injury period and later merged to Nirma. The information of Nirma includes information of SCL.

Examination by the Authority

12. The Authority notes that Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules read as follows:-

“domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

13. Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules provides that domestic producers which are related to the exporters or importers or which are themselves importers of the allegedly dumped articles may be excluded when determining the domestic industry in certain situations. The Authority is of the considered view that the use of the word ‘may’ in Rule 2(b) suggests that the two types of producers in question, i.e. related producers and producers importing the dumped product, are not automatically excluded from being part of the domestic industry. On the contrary, it has been the consistent practice that exclusion of such producers must be decided on a case-by-case basis, on reasonable and equitable grounds, and by taking into consideration all the legal and economic aspects involved.
14. The Authority notes that in the original investigation also the domestic industries were involved in imports of subject goods from the subject countries or were related to the exporters/importers of subject goods from the subject countries. In the final findings of the original investigation, the Authority had noted as below:

“49. The Authority considers that the domestic producers who import an insignificant quantum of the dumped goods or whose related exporter, exports the dumped goods or whose related importer, imports the dumped goods, do not unduly benefit from dumping practices, if these imports do not represent a significant part of their sales or market size. Indeed, no advantage occurs to such domestic producers because of the competition from other suppliers in the market. The Authority also notes that another distinction drawn by the Investigating authorities of other countries, while deciding whether a domestic producer should be excluded is: Is the domestic producer merely supplementing its domestic production with some dumped imports or whether it is primarily an importer with relatively limited production? The Authority considers that in the latter case, such company should be excluded from the scope of domestic industry. Another element which can be considered is whether or not the domestic producer in question is committed to production in the country of imports.

50. In view of the above, the Authority holds that the only relevant issue for determination is whether or not GHCL, Nirma, SCL and Tata Chemicals should be treated as eligible domestic industry. In the instant case, there is no allegation that any of the domestic producers is related to an importer. The arguments of the interested parties are that SCL, Nirma and GHCL should be treated as ineligible domestic industry in view of their relationship with foreign producers/exporters in subject countries or, in case of Nirma, additionally because of imports made by Nirma.

51. The Authority has examined the issue of eligibility of the applicant companies by applying the aforesaid principles to the facts and circumstances of the present case. The facts of the instant case are as follows in so far as the issue of relationship and eligibility of the applicant companies is concerned.

- i. The application was filed by Alkali Manufacturers' Association of India (AMAI). AMAI is an association of producers of caustic soda (including chlorine) and soda ash.
- ii. DCW, GHCL, Nirma and Saukem have provided information relevant to injury to the domestic industry and have requested to be considered as "domestic industry" for the purpose of the present investigation. These companies are being treated as "participating companies". The petition has express support of all Indian Producers of soda ash during POI, except Tata Chemicals. Tata Chemicals has neither supported nor opposed the imposition of anti-dumping duties. It is however noted that Magadi Soda Company, Kenya (renamed as Tata Chemicals Magadi Ltd) is a 100% subsidiary of Tata Chemicals and the company is participating in the present investigations by filing exporters' questionnaire response.
- iii. Post initiation and after holding of 1st oral hearing, Tuticorin Alkali Chemicals (TAC) has filed its written submissions vide their letter dated 23rd May, 2011 supporting the application and requesting the Designated Authority to impose anti-dumping duties. It is noted that TAC has not participated in the proceedings by way of filing response to the initiation notification. It is also noted that they were not producing the subject goods during POI. The Authority has, therefore, not considered the submissions of TAC at this belated stage.
- iv. None of the petitioner companies are related to any of the importers of the product under consideration in India;
- v. DCW Ltd. does not have any related producer-exporter outside India. The company has not imported the product under consideration, nor is the company related to any exporter or importer. There is no dispute that DCW is an eligible domestic producer constituting 'domestic industry'. Petitioner has strongly contended that in the event the Authority holds that GHCL, Nirma and SCL are ineligible domestic industry, DCW alone shall constitute domestic industry, as the production of the company in that event shall constitute 100% of the "production by the domestic industry".
- vi. SCL and Nirma are undisputedly related companies.
- vii. Nirma has imported soda ash from its related supplier in USA. Barring Nirma, none of the petitioner companies have themselves imported the material from any of the subject countries during the entire injury period.
- viii. GHCL has a related company in Romania, namely S.C. GHCL Upsom. The related exporter of GHCL has exported Soda Ash to India over the current injury period. GHCL has also provided details of their related company in Romania regarding production and exports to India (volume information only). Details of exports made by related exporter over the injury period show that (a) these exports have been directly made by the Romanian company to unrelated Indian customers during the POI, and (b) the volume of exports by the company steeply declined over the injury period. Table below shows the volume of exports from Romania, exports by GHCL Upsom and other relevant details.

S. No.	Particulars	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
A	(a) Exports by S.C. GHCL Upsom	MT	17,356	51,353	6,489	4,101
B	Exports to related parties	MT	11,082	-	-	-
C	Exports to unrelated Indian parties	MT	6,274	51,353	6,489	4,101
D	(b) Total imports from Romania	MT	46,594	67,121	7,652	47,148
2	Exports made by S.C. GHCL Upsom in relation to	MT	17,356	51,353	6,489	4,101
A	Indian production		0.85%	2.54%	0.32%	0.20%
B	Indian Consumption		0.80%	2.33%	0.29%	0.17%
C	Production of GHCL		3.31%	8.68%	1.05%	0.61%
D	Imports made by GHCL in relation to					
A	GHCL's production		2.11%	0.00%	0.00%	0.00%
B	Indian production		0.54%	0.00%	0.00%	0.00%
C	Indian consumption		0.51%	0.00%	0.00%	0.00%
3	Gross imports from Romania	MT	46,594	67,121	7,652	47,148
A	• Exports by GHCL Upsom	MT	17,356	51,353	6,489	4,101
B	• Exports by Other exporters	MT	29,238	15,768	1,163	43,047
C	Share of GHCL Upsom in total exports from Romania		37.25%	76.51%	84.80%	8.70%

52. The Authority holds that

- (i) GHCL Upsom is not the majority exporter of soda ash from Romania. Other exporters from Romania constitute majority exports from Romania.
- (ii) Exports by GHCL Upsom declined significantly in absolute terms as also in relation to imports from Romania.
- (iii) Exports by GHCL Upsom are quite insignificant when compared with total imports of soda ash in India, production of soda ash by GHCL and consumption of soda ash in India.
- (iv) The imports were not made by GHCL, India. The imports were made directly by unrelated consumers.
- (v) The volume of exports by GHCL Upsom is not so significant as to have caused or provoked injury to the domestic industry.
- (vi) Focus of GHCL continues to be on production. The company has not turned trader. Nor the company has unduly benefited from dumping. In fact, imposition of anti-dumping duty would imply imposition of anti-dumping duty on exports made by GHCL Upsom as well. The injury determination shall not get distorted by including GHCL within the scope of the domestic industry.
- (vii) None of the opposing interested parties have advanced any justification for exclusion of GHCL from the scope of the domestic industry, barring the fact of relationship itself.

53. SCL & Nirma have related producer in USA, namely Searles Valley Minerals. Details of exports made by related exporter over the injury period show that (a) these exports have been made only during the POI, (b) the exports have been made to Nirma, (c) Nirma has used this material for self-consumption. Table below shows the volume of exports from US, exports by Searles Valley Minerals (related producer of Nirma and SCL in USA) and other relevant details

S. No.		Unit	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	(a) Exports by Searles Valley Minerals	MT	-	-	-	2,700
	Exports to Nirma	MT	-	-	-	2,700
	Exports to unrelated Indian parties	MT	-	-	-	-
	(b) Total imports from USA	MT	123	629	830	32,679
	Direct	MT	123	629	830	17,852
	Transshipments	MT	-	-	-	14,827
2	Exports made by Searles Valley Minerals (USA) in relation to					
	Indian production		0.00%	0.00%	0.00%	0.13%
	Indian Consumption		0.00%	0.00%	0.00%	0.11%
	Production of Nirma		0.00%	0.00%	0.00%	0.58%
	Imports made by Nirma in relation to					
	Nirma's production		0.00%	0.00%	0.00%	0.58%
	Indian production		0.00%	0.00%	0.00%	0.13%
	Indian consumption		0.00%	0.00%	0.00%	0.11%
3	Imports from USA in India	MT	123	629	830	32,679
	Exports by affiliated parties of Nirma/ Saukem	MT	-	-	-	2,700
	Exports by Other Parties from USA	MT	123	629	830	29,979
	Share of exports by Nirma's affiliated producer in total exports from USA		0.00%	0.00%	0.00%	8.26%

54. The Authority notes that –

- (i) Searles Valley Minerals (related company of Nirma and SCL in USA) is not the majority exporter of soda ash from USA during the POI. Other exporters (non-related) from USA have a majority and much larger share in exports from USA.
- (ii) Exports by Searles Valley Minerals are insignificant when compared with total imports of soda ash in India, production of soda ash by Nirma and Saukem and consumption of soda ash in India.
- (iii) The volume of exports by Searles Valley Minerals is not so significant as to have caused or provoked injury to the domestic industry.
- (iv) The imports from the related company in USA by Nirma have not been used for trading in the domestic market. The same has been used for captive consumption by Nirma and the volume thereof is insignificant compared to the total production of Nirma.
- (v) Focus of Nirma (or Saukem) continues to be on production. It can be reasonably stated that the company has not shifted to trading in imported goods. Nor the company can be said to have unduly benefited from dumping. In fact, imposition of anti-dumping duty would imply imposition of anti-dumping duty on exports made by Searles Valley Minerals as well. The injury determination shall not get distorted by including Searles Valley Minerals within the scope of the domestic industry.
- (vi) None of the opposing interested parties have advanced any justification for exclusion of Searles Valley Minerals from the scope of the domestic industry, barring the fact of relationship itself.

55. Tata Chemicals (one of the domestic producers of subject goods) has a related producer in Kenya as per information available on record and the Authority notes that there are significant imports from Kenya during POI. The present investigation includes Kenya as one of the subject countries. Details of exports made by related exporter in Kenya over the injury period show that (a) the Kenyan

company is a subsidiary of Tata Chemicals, (b) records do not show any other producer of soda ash in Kenya, (c) these exports have been made throughout the injury period (d) petitioner claimed and other interested parties have not disputed with cogent reasons that Tata Chemicals should be treated ineligible domestic producer under Rule 2(b) to qualify as a domestic industry. Table below shows the volume of exports from Kenya, exports by Magadi Soda Ash (renamed as Tata Chemicals Magadi Ltd) and other relevant details

S. No.		Unit	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	(a) Exports by Magadi Soda	MT	85,797	1,15,520	1,17,572	1,06,585
	Exports to related parties	MT	-	-	-	2,005
	Exports to unrelated Indian parties	MT	85,797	1,15,520	1,17,572	1,04,580
	(b) Total imports from Kenya	MT	85,797	1,15,520	1,17,572	1,06,585
2	Exports made by Magadi Soda (Kenya) in relation to	MT	85,797	1,15,520	1,17,572	1,06,585
	Indian production		4.19%	5.72%	5.79%	5.13%
	Indian consumption		3.97%	5.24%	5.33%	4.32%
	Production of TCL		11.33%	16.57%	16.91%	15.32%

56. From the above, the Authority notes that-

- i. Magadi Soda, Kenya (renamed as Tata Chemicals Magadi Ltd) is the sole exporter of soda ash from Kenya.
- ii. Exports by Magadi Soda (Kenya) are quite significant when compared with total imports of soda ash in India, production of soda ash by Tata Chemicals and consumption of soda ash in India.
- iii. The volume of exports by Magadi Soda (Kenya) is significant so as to have caused or provoked injury to the domestic industry.
- iv. Focus of Tata Chemicals continues to be on production. The company has not turned trader. However, the undue benefit to the company from dumping by related company cannot be ruled out, given the volume of exports by the related company from Kenya during POI.
- v. While the petitioner has argued that Tata Chemicals should be treated ineligible domestic industry, none of the opposing interested parties have sought inclusion of Tata Chemicals within the scope of domestic industry.

57. It is, thus, seen that –

- i. 85% of exports from USA and 93% of exports from Romania are by producers unrelated to Indian producers. However, 100% of exports from Magadi are by the producer related to one of the Indian producers.
- ii. As regards Tata Chemicals, the exports made by Magadi Soda are quite significant. Magadi Soda is the sole producer of soda ash in Kenya, the volume of exports has not declined. Magadi Soda has low domestic demand and the focus of the company is on exports (exports by the company are almost 90% of its total sales). The Authority holds that even though Tata Chemicals is a domestic producer, the company must be considered ineligible to be treated as “domestic industry” for the purpose of the present investigations.
- iii. As regards GHCL, the Authority notes that the exports made by related exporter have significantly declined over the injury period, 93% of the exports from Romania are by unrelated producers in Romania, focus of GHCL has not shifted from manufacturing to trading, nor any undue benefit can be said to have accrued either to related exporter or to GHCL. The Authority holds GHCL as eligible to be treated as “domestic industry” for the purpose of the present investigations.
- iv. As regards Nirma and Saukem, the Authority notes that the exports made by related exporter were only in the investigation period. 85% of the exports from USA are by unrelated

producers in USA. Focus of Nirma has not shifted from manufacturing to trading, as the relevant figures would indicate. Exports made by the related producer in USA cannot be said to have resulted in undue benefit to the domestic producer in India, namely, Nirma or Saukem. Rather, the insignificant quantity of the material has been imported for internal consumption. In view of the above position, the Authority holds Nirma and Saukem as eligible to be treated as “domestic industry” for the purpose of the present investigations.

58. Thus, the Authority is of the view that it is appropriate to consider GHCL, Nirma, Saukem and DCW Limited as the domestic industry under Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules. Accordingly, the Authority considers GHCL, Nirma, Saukem and DCW Limited, the constituent applicants as “domestic industry”, satisfying the requirements of Rule 2(b) read with Rule 5(3) of the Anti-dumping Rules.”

15. In the present MTR investigation, none of the industries constituting domestic industry has imported the subject goods from the subject countries during the POI. However, some of the industries constituting domestic industry in the present MTR investigation as well as the other MTR investigation initiated by the Authority in respect of imports of the subject goods from China PR, EU, Kenya, Pakistan, Iran, Ukraine and USA for the same POI, have imported the subject goods from the said countries. The position of the domestic industry in the said MTR investigation is as given below.
16. In the MTR investigation initiated by the Authority in respect of China PR, EU, Kenya, Pakistan, Iran, Ukraine and USA, DCW has neither imported subject goods from the subject countries nor is related to either importers or exporters of subject goods from the subject countries. Nirma also has not imported the subject goods from the subject countries. Only their 100% owned subsidiary in USA has exported the subject goods to India during the POI. GHCL Ltd has imported an insignificant volume of the subject goods from the subject countries. Only Tata Chemicals has not made a significant volume of imports of subject goods from their subsidiary in Kenya in the POI, but neither in the original investigation nor in the present review do they constitute domestic industry. The details of imports of subject goods, from the subject countries, during the POI, made by the various domestic producers involved in the present investigation and claiming to be domestic industry, are as follows:

GHCL

SN	Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	Post POI
1	Imports by GHCL	MT			3,021	12,689	14,760
a	Subject Countries(China etc)	MT			3,021	12,689	14,760
b	Subject Countries(Turkey and Russia)	MT			-	-	-
2	Total Imports	MT	4,44,475	6,92,228	5,67,587	7,23,978	3,67,818
a	Subject Countries(China etc)	MT	3,29,828	5,53,416	4,89,270	6,73,706	3,47,389
b	Subject Countries(Turkey and Russia)	MT	1,10,695	1,19,014	62,103	49,071	19,305
3	Indian Production	MT	23,55,710	23,61,482	23,35,596	24,17,331	12,36,435
4	Indian Consumption-Without Captive	MT	24,30,534	27,77,552	27,35,605	29,42,744	14,86,940
5	Production of GHCL	MT	6,76,007	6,85,101	6,76,523	7,04,835	3,49,820
6	Imports made by GHCL in relation to						
a	GHCL Production	%	-	-	0.45	1.80	4.22
b	Indian Production	%	-	-	0.13	0.52	1.19
c	Indian Consumption	%	-	-	0.11	0.43	0.99
d	Total Imports	%	-	-	0.53	1.75	4.01
i	Subject Countries(China etc)	%			0.62	1.88	4.25
ii	Subject Countries(Turkey and Russia)	%			-	-	-

17. As regards Nirma Ltd, the Authority notes that the said company has not imported the subject goods from the subject countries during the POI directly. However, their 100% owned subsidiary in USA has exported some volume of the subject goods to India during the POI. But, Nirma's subsidiary is not the sole producer or exporter from USA and therefore, had it not exported the volume it has exported to India during the POI, another USA exporter would have filled the gap. The details of exports of subject goods made by the related USA entity, as provided by Nirma, are as follows:

SN	Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	Post POI
1A	Exports by Searless Valley Minerals Inc	MT				48,228	59,523
	a)Related	MT	-	-	-	-	-
	b)Unrelated	MT	-	-	-	48,228	59,523
2	Import from all Subject Countries by Nirma Limited	MT	-	-	-	-	-
3	Total Exports by Searless Valley Minerals Inc	MT	-	-	-	48,228	59,523
4	Total Imports	MT	4,44,475	6,92,228	5,67,587	7,23,978	3,67,818
a	Subject Countries(China etc)	MT	3,29,828	5,53,416	4,89,270	6,73,706	3,47,389
b	Subject Countries(Turkey and Russia)	MT	1,10,695	1,19,014	62,103	49,071	19,305
5	Indian Production	MT	23,55,710	23,61,482	23,35,596	24,17,331	12,36,435
6	Indian Consumption	MT	24,30,534	27,77,552	27,35,605	29,42,744	14,86,940
7	Production of Nirma Ltd	MT	8,21,064	8,43,699	8,43,444	8,58,359	4,56,112
8	Exports by Searless Valley Minerals Inc in relation to						
a	Nirma Production	%	-	-	-	5.62	13.05
b	Indian Production	%	-	-	-	2.00	4.81
c	Indian Consumption	%	-	-	-	1.64	4.00
d	Total Imports	%	-	-	-	6.66	16.18
ii	Subject Countries(China etc)	%	-	-	-	7.16	17.13
ii	Subject Countries(Turkey and Russia)	%	-	-	-	-	-

18. As regards Tata Chemicals Ltd, the Authority notes that the Company has themselves imported the subject goods from their related party in the subject countries. Further, the related party of Tata Chemicals Ltd has exported significant volume of subject goods to India. In view of the above position, the case of Tata Chemicals is not comparable with either GHCL or Nirma and therefore the Authority does not consider Tata Chemicals Ltd as an eligible domestic industry. The details of their imports, as furnished by the domestic industry, are as follows:

Tata Chemicals Ltd

SN	Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	Exports by Tata Chemicals Magadi Limited	MT	-	-	-	1,32,725
	a)Related	MT	-	-	-	16,407
	b)Unrelated	MT				1,16,318
2	Import from Subject Countries(China etc) net of Kenya	MT	-	-	-	43,253
3	Total Imports/Exports by Tata	MT	-	-	-	1,75,978
4	Subject Countries(Turkey and Russia)	MT	-	-	-	-
5	Total Imports	MT	4,44,475	6,92,228	5,67,587	7,23,978
a	Subject Countries(China etc)	MT	3,29,828	5,53,416	4,89,270	6,73,706
b	Subject Countries(Turkey and Russia)	MT	1,10,695	1,19,014	62,103	49,071
6	Indian Production	MT	23,55,710	23,61,482	23,35,596	24,17,331
7	Indian Consumption	MT	24,30,534	27,77,552	27,35,605	29,42,744
8	Production of Tata Chemicals	MT	6,90,181	6,93,396	7,23,819	7,23,892
9	Imports made by TCL in relation to					
a	TCL Production	%	-	-	-	24.31
b	Indian Production	%	-	-	-	7.28
c	Indian Consumption	%	-	-	-	5.98
d	Total Imports	%	-	-	-	24.31
i	Subject Countries(China etc)	%	-	-	-	26.12
ii	Subject Countries(Turkey and Russia)	%	-	-	-	-

19. The Authority notes that the intent of the provisions laid down under Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules is not to debar any domestic producer from the ambit of domestic industry merely because they have imported the subject goods from the subject countries. Imports of subject goods from the subject countries by a domestic producer claiming the status of domestic industry under the Rules cannot be treated as a sacrilege. What is important to be assessed by the Authority is the intent and tone and tenor of such domestic producers, the magnitude of such imports, the situation under which such imports have been effected and the impact of such imports on the financial parameters of such industries. As per the facts available in the present investigation, GHCL and Nirma, who have claimed to be treated as domestic industry along with DCW, have neither made significant imports of subject

goods from the subject countries during the POI, nor have their related exporters in the subject countries marketed the subject goods in India through them. Their focus of business has also not shifted from production to trading. Both GHCL and Nirma have utilized more than 80% of their capacity of production during the POI. Therefore, the imports of subject goods made by them or exports made by their related party cannot be interpreted as an effort to involve themselves in trading. If at all they have imported some volume of subject goods from the subject countries, it is either to match the price of imports or to retain a customer, which otherwise would have shifted to cheaper imports. Moreover, such imports by them are of course on payment of anti-dumping duties and therefore cannot be seen to have accrued undue financial advantage to them.

20. The production position of the constituents of the domestic industry in the present investigation is as given below:

Particular	UOM	2011- 12	2012- 13	2013-14	POI
Domestic Industry Production	MT	15,78,674	16,11,377	16,02,002	16,45,154
Other Producers Production	MT	7,77,036	7,50,106	7,33,594	7,72,177
Total Indian Production	MT	23,55,710	23,61,482	23,35,596	24,17,331
Share of Domestic Industry	%	67.01	68.24	68.59	68.06
Share of Other Producers	%	32.99	31.76	31.41	31.94

21. In view of the above position, the Authority considers GHCL, Nirma Ltd and DCW Limited as “domestic industry” in the present MTR investigation, satisfying the requirements of Rule 2(b) read with Rule 5(3) of the Anti-dumping Rules.

E. Confidentiality

22. The applicant and other interested parties have made the following submissions with regard to the issue of confidentiality:
- There is no reasonable basis for grant of confidentiality to the domestic producers. Information pertaining to sales value, opening and closing stock is easily available in the respective balance sheets of the Applicants, but the same has not been given in their response.
 - There are discrepancies in the non confidential version of domestic producers. Therefore, the information supplied by the domestic producers needs to be rejected.
23. The domestic industry has made the following submissions with regard to confidentiality:
- As regards the confidential figures are concerned, there were clerical/calculation or cumulation errors in the data which have been corrected and information provided to all the parties before the hearing.
 - The domestic industry did not materially change the figures. It filed an additional letter and there was no difference as regards the confidential information contained in the two submissions.
 - There is no basis for publically disclosing volume of imports made by the domestic industry constituents or volume of exports made by related parties.

EXAMINATION BY THE AUTHORITY

24. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows: -

Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules and (7) of rule 6, sub-rule(2),(3)(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.

25. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file. The Authority notes that any information which is available in the public domain cannot be treated as confidential.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

Submissions made by the Applicant and other Interested Parties

26. Following miscellaneous submissions have been made by applicant and other interested parties:

- i. The domestic industry did not exercise any due diligence or care in ensuring the accuracy of the data provided in response to the MTR and they did not even file the necessary certificate of correctness.
- ii. The claim of inclusion of freight has no legal tenability and in fact principle of res judicata is applicable to this issue since the domestic industry is once again pressing this issue before the same Authority which they did in the original investigation and was rejected by the Authority.
- iii. During the oral hearing, the domestic industry did not rebut the submissions made by the Respondents and in view of principle of 'Doctrine of Non-Traverse', it is deemed that the Domestic Producers admitted such submissions.
- iv. The two mid-term reviews should be combined as the product under consideration, the composition of the Domestic Producers as well as the period of investigation are the same.
- v. The domestic industry has to be inferred as domestic industry as defined in the previous investigation. It is only and only the domestic producers themselves, who can lead information in this regard and not the applicant. There exists no need under Rule 23(1A) of Anti-Dumping Rules for the Applicant to identify the domestic industry and make allegations.
- vi. Since writ petitions and appeals are pending in High Court and CESTAT on the issue of inclusion of freight, filed by the domestic producers, authority should not change its settled practice regarding determination of non-injurious price and continue to exclude inland freight while determining non-injurious price. This issue of inclusion/non-inclusion of freight may be decided as and when the matter is finally settled by the High Court or the CESTAT.
- vii. There is a demand supply gap in the domestic market since the domestic industry is unable to supply despite having capacities.
- viii. There are thousands of tiny, small and medium scale detergent producers in India providing employment to masses. Anti-dumping duties imposed on soda ash, the major raw material for detergents, cause much hardship to them. Non supply of required volume by domestic industry due to demand supply gap forces these industries to depend upon imported material by bearing the anti-dumping duty, thereby making their products cost ineffective.
- ix. There is a mutual understanding among the domestic producers of soda ash in terms of price fixation amounting to cartelization at the cost of downstream industries.

Submissions made By Domestic Industry

27. Following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:

- i. The petition is deficient as it claims absence of injury without establishing "domestic industry".
- ii. The petition doesn't establish why antidumping duties are required to be withdrawn. The objective of midterm review is to analyze whether the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur in the event of premature revocation of duty.
- iii. The Authority is requested to consider the submissions by domestic industry with regard to methodology for determination of injury margin generally applied by the Authority and as applied at the time of original investigations and reasonableness and appropriateness of the same in the facts and circumstances of the present case. As regards NIP practice and law the provisions

- prescribed under Annexure III were being practiced earlier and were being followed by the Authority prior to introduction of law.
- iv. As regards difference in production in the standing table and injury statement given that the standing statement contains company wise breakdown, it is was a clerical error which is regrettable but it cannot be said to cause serious prejudice to the interested parties that the duties should be terminated.
 - v. There is no prescribed requirement for filing of certificate of correctness with the information filed. The domestic industry cannot be penalized on the ground of clerical human errors and depriving it of a legitimate protection.
 - vi. As regards the argument of interested parties that domestic industry is not willing to supply in South due to freight, it is submitted that firstly domestic industry has not regretted material to any consumer and secondly that this shows that freight could be recognized for determining injury margin.
 - vii. The reliance on Doctrine of Non Traverse is unfounded because hearing has a meaning when submissions are made and rejoinder submissions are made to submissions raised by other parties.
 - viii. The domestic industry has no objection to cumulation of two mid-term reviews, however this will render initiation invalid and warrant initiation of a fresh midterm review investigation.
 - ix. India is short in soda ash production vis-à-vis global market having surplus. RSPL Ltd, a leading detergent manufacturer, is setting up a soda ash plant in India with 5 lakh MT production capacity for captive consumption and sale in domestic market. With their entry, India would become self sufficient in Soda Ash. If the present anti-dumping duties are withdrawn and the prices decline, then RSPL would suffer injury. Therefore, the present anti-dumping duties should continue.

EXAMINATION OF THE AUTHORITY

28. Rule 23 of Anti-dumping Rules states as follows:

(1) Any anti-dumping duty imposed under the provision of section 9A of the Act, shall remain in force, so long as and to the extent necessary, to counteract dumping, which is causing injury.

(1A) The Designated Authority shall review the need for the continued imposition of any anti-dumping duty, where warranted, on its own initiative or upon request by any interested party who submits positive information substantiating the need for such review, and a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty and upon such review, the Designated Authority shall recommend to the Central Government for its withdrawal, where it comes to a conclusion that the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur, if the said anti-dumping duty is removed or varied and is therefore no longer warranted.

(1B) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) or (1A), any definitive anti-dumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the Designated Authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

(2) Any review initiated under sub-rule (1) shall be concluded within a period not exceeding twelve months from the date of initiation of such review.

(3) The provisions of rules 6, 7, 8, 9/10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 shall be mutatis mutandis applicable in the case of review.

29. Article 11.2 of the Anti-dumping Agreement provides that the Authority shall review the need for the continued imposition of the duty, where warranted, on their own initiative or, provided that a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti dumping duty, upon request by any interested party which submits positive information substantiating the need for a review. Interested parties shall have the right to request the authorities to examine whether the continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both. If, as a result of the review under this paragraph, the Authority determines that the anti dumping duty is no longer warranted, it shall be terminated immediately.

30. The applicant and the other interested parties have contended that the scope of mid-term review is different from the scope of sunset review. The applicant has contended that in a mid-term review DGAD is required to consider and determine whether there is sufficient justification for withdrawal of anti-dumping duty before completion of five years, whereas in sunset review DGAD is required to determine whether anti-dumping duty is required to be extended further or not after expiry of five year. On the other hand, domestic industry contended that in a mid-term review, current performance alone is insufficient to conclude whether the anti-dumping duty can be withdrawn at this stage and that the Authority is required to consider the likely situation when anti dumping duty is withdrawn.
31. The Authority has examined the issues raised by the interested parties and domestic industry and notes that Rule 23 of the Anti-dumping Rules obligates the Authority to review the need for the continued imposition of an anti-dumping duty, *inter alia*, upon request by any interested party who submits positive information substantiating the need for such review after a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty and upon such review, the Authority shall recommend to the Central Government for its withdrawal, where it comes to the conclusion that the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur if the said anti-dumping duty is removed or varied and is therefore no longer warranted.
32. As regards the contention of the applicant and other interested parties that domestic industry did not exercise any due diligence or care in ensuring the accuracy of the data provided in response to the MTR and they did not even file the necessary certificate of correctness, the Authority notes that the relevant data/information of the domestic industry has been verified.
33. As regards the argument of applicant and other interested parties that the claim of the domestic industry for inclusion of freight in the NIP has no legal tenability and should not be acceded by the Authority, it is noted that the NIP has been determined strictly as per the provisions laid down under Annexure III of the Anti-dumping Rules.
34. The applicant and other interested parties have argued that two mid-term reviews i.e. the present one and the one against Turkey and Russia initiated by the Authority should be combined as the product under consideration, the composition of the domestic producers as well as the period of investigation are the same, the Authority notes that the two midterm reviews are concerning two different final findings and duty notifications involving different set of countries. Therefore, it would not be appropriate to combine both these investigations.
35. As regards the argument of the interested parties that there is a demand supply gap in the domestic market since the domestic industry is unable to supply despite having capacities and because of which downstream industries, especially tiny, small and medium scale detergent producers, are suffering, the Authority notes that in the anti-dumping law the domestic industry is not obliged to fulfill the entire demand in the domestic market. Since imposition of anti-dumping duties do not prevent import and its intent is only to rectify an unfair position due to dumping, the user sector can always import and fulfill their extra demand.
36. As regards the argument of the interested parties that there is a mutual understanding among the domestic producers of soda ash in terms of price fixation amounting to cartelization at the cost of downstream industries, the Authority notes that the allegation is unsubstantiated.

G. Determination of Dumping Margin

Market Economy Claims, Normal Value, Export Price and Dumping Margin

Submissions made by the Applicant and Other Interested Parties

37. The submissions made by the Applicant and other interested parties with regard to market economy, normal value, export price and dumping margin are as follows:
 - i. The cost of production is significantly lower when soda ash is produced from natural resources. If such revelation is correct, then the Normal Value in those countries would be significantly lower.
 - ii. As no evidence has been provided by the Domestic Producers in respect to how they have taken the values for the Ocean freight, Marine Insurance, Commission, Inland Transportation, Port Expenses and Bank Charges, the Designated Authority is requested to call for evidence and seek such information instead of relying blindly on the information furnished by the domestic producers.
 - iii. Normal Value and the Export Price for the non-cooperating exporters should be calculated on the basis of export price and normal value of the cooperating exporters.
 - iv. Since the imposition of anti-dumping duties by India against Russian imports, the Russian exports of Soda Ash to India have gone down drastically.

- v. Worldwide increase in soda ash prices is the result of increase in the prices of raw materials. Therefore, the impact of Russian prices on Indian soda ash sector is not possible in the foreseeable future.
- vi. The export price of soda ash of ETI and Soda Sanayii has gone up significantly. Exports by ETI Soda Ash are not causing any injury to the domestic industry.

Submissions made by the domestic industry

38. The submissions made by the domestic industry with regard to market economy, normal value, export price and dumping margin are as follows:
- i. The export price has been on the basis of DGCI&S transaction wise data. The export prices have been adjusted for ocean freight, marine insurance, commission, inland transportation, port expenses, bank charges and VAT difference.
 - ii. Both the normal value and export price have been determined at ex-factory level. Domestic industry has taken into account all physical characteristics of the product for which the information is available. Thus, the comparison made by the domestic industry constitutes a fair comparison.
 - iii. The dumping margins are not only de-minimis but also substantial.
 - iv. As regards cost of production being lower in countries where production is from natural resources, the IHS Chemical Journal gives out the price prevalent in the countries which leads to presumption of high profits made in these countries.
 - v. The domestic industry has provided price prevailing in the country which is what needs to be considered.
 - vi. The domestic industry has followed conservative approach with respect to evidence taken for various adjustments.
 - vii. The Authority should take the highest normal value and lowest export price transaction in order to determine dumping margin for non cooperative exporters.

H. DETERMINATION OF NORMAL VALUE

39. The Authority notes that exporter's questionnaire response has been submitted by only two producers/exporters of Turkey namely Soda Sanayii A.S. and ETI Soda. The same has been accepted by the Authority and considered for the purpose of determination of normal value, export price and dumping margin. The Authority further notes that no producer/exporter of Russia has submitted exporter questionnaire response in the present investigation.

Soda Sanayii A.S, Turkey

40. Soda Sanayii A.S, Turkey has reported total domestic sales of *** MT of subject goods during POI with gross invoice value of *** TL. Adjustment has been claimed on account of discount, inland freight, warehouse charges, credit cost and inventory carrying cost. The Authority has admitted the adjustments as claimed and determined the normal value at ex-factory level in respect of Soda Sanayii A.S, Turkey. The proposed normal value so determined for Soda Sanayii A.S, Turkey has been mentioned in the dumping margin table given below.

ETI Soda, Turkey

41. ETI Soda, Turkey has reported total domestic sales of *** MT of subject goods during POI with gross invoice value of *** TL. Adjustment has been claimed on account of inland freight and credit cost. The Authority has admitted the adjustments as claimed and determined the normal value at ex-factory level in respect of ETI Soda, Turkey. The proposed normal value so determined for ETI Soda, Turkey has been mentioned in the dumping margin table given below.

Non Cooperative exporters of Turkey

42. The Authority notes that no other producer/exporter from Turkey has cooperated in the present investigation. Therefore, the Authority has adopted the highest normal value of the two cooperative exporters from Turkey for determining the normal value for the non cooperative producers/exporters from Turkey. The details of the proposed normal value so determined for the non cooperative producers/exporters from Turkey have been mentioned in the dumping margin table given below.

Normal value in case of Russia

43. The Authority notes that none of the producers/exporters from Russia has cooperated and submitted exporter's questionnaire response. Therefore, the Authority has relied upon the best available information in terms of Rule 6(8) of the Rules for the determination of normal value in respect of Russia. The proposed normal value so determined for Russia has been mentioned in the dumping margin table given below.

I. EXPORT PRICE**Turkey****Soda Sanayii A.S, Turkey**

44. As per the exporter's questionnaire, during the POI, Soda Sanayii A.S, exported *** MT of subject goods to India for the gross invoice value of US\$ ***. The company claimed adjustment on account of inland freight, clearing and handling charges, credit cost, net forex gain/loss, duty draw back. However, the Authority notes that the claimed adjustments on account of net forex gain/loss cannot be accepted since the same is not directly related to the export sales. As regards claimed adjustment on account of duty drawback, the same cannot be acceded without being substantiated with supportive documents. Therefore, after making the price adjustments on account of inland freight, clearing and handling charges and credit cost, the net export price, at ex-factory level, has been determined. The details of the proposed net export price so determined for Soda Sanayii A.S have been mentioned in the dumping margin table given below.

ETI Soda, Turkey

45. As per the exporter's questionnaire, during the POI, ETI Soda, Turkey exported ***MT of subject goods to India for the gross invoice value of US\$ ***. The company claimed adjustment on account of inland freight, overseas transport, overseas insurance, and bank charges. After making price adjustments, as claimed by the Company, the net export price, at ex-factory level, has been determined. The details of the proposed net export price so determined for ETI Soda, Turkey have been mentioned in the dumping margin table given below.

All other exporters of Turkey

46. The Authority notes that no other exporter from Turkey has submitted exporter's questionnaire response. Therefore, the Authority has adopted the lowest representative net export price to India of the cooperative exporters for all other exporters of Turkey as the net export price after making the due adjustments. The proposed net export price so determined for the non-cooperative exporters from Turkey has been mentioned in the dumping margin table given below.

All exporters of Russia

47. The Authority notes that none of the exporters/producers of subject goods from Russia has cooperated and responded to the Authority in the form and manner prescribed. In the absence of exporter's questionnaire response from the producers/exporters from Russia, the Authority has determined the export price on the basis of best available information in terms of Rule 6(8) of the Rules. The proposed export price so determined at ex-factory level for all exporters of Russia has been mentioned in the dumping margin table given below.

J. DUMPING MARGIN

48. Comparing the aforesaid normal values and export prices as determined, the proposed dumping margin determined for the subject countries during POI and Post POI are as follows:

POI

Country	Exporter/ Producer	Normal Value US\$/MT	Net Export Price US\$/MT	Dumping Margin US\$/MT	Dumping Margin %	Dumping Margin % Range
Turkey	Soda Sanayii A.S	***	***	***	***	20-30
	ETI Soda	***	***	***	***	0-10
	Non- Cooperative	***	***	***	***	25-35
Russia	All	***	***	***	***	25-35

Post POI

Country	Exporter/ Producer	Normal Value US\$/MT	Net Export Price US\$/MT	Dumping Margin US\$/MT	Dumping Margin %	Dumping Margin % Range
Turkey	Soda Sanayii A.S	***	***	(***)	(***)	Negative
	ETI Soda	***	***	(***)	(***)	Negative
	Non-Cooperative	***	***	***	***	10-20
Russia	All	***	***	***	***	30-35

K. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK**Submissions made by the Applicant and Other Interested Parties**

49. Following are the submissions made by the applicant and other interested parties in this regard:

- i. Import is occurring only because domestic producers forcing it upon the users. Even the domestic producers, who use the subject goods in downstream production, use the imported products only. Therefore, the Anti-dumping Duty may be recommended to be withdrawn with effect from the date on which such MTR has been initiated.
- ii. The domestic producers never disputed the fact that the capacity utilization could be achieved more than what has been achieved. It has not been disputed that Nirma along with earlier SCL made a claim before the BIFR that the plant of SCL was in the state of scrap.
- iii. It was not disputed by the domestic producers that the price at which imported goods, which were resold, were significantly higher than the landed value shown at the port of import, resulting into a distorted Landed Value for the purposes of comparison of such Landed Value with the NIP and NSR.
- iv. 20% - 25% ROCE earned by the domestic producers has been arrived at from the Financial Records without applying the principles of Annexure III which requires to remove extra-ordinary expenses like expenses incurred during shutdown of the plant due to unavailability of the raw material.
- v. NSR of the domestic producers for the price undercutting have been arrived at after adding freight. It has been done even though according to the practice of the designated authority Net Sales Realization is arrived at the ex-factory gate of the domestic producers.
- vi. Gujarat Heavy Chemicals Limited ("GHCL") is a profit making company and that the related producers and exporters are not participating in the investigation as there is no dumping. The Domestic producers did not deny the fact that TATA Chemicals Limited ("TCL") is also a profit making company and earning huge profits on resale of the imported subject goods.
- vii. There are no price Suppression and Depression even after the inclusion of the non- functional plants of the domestic producers. Therefore it may be inferred that the domestic Industry is not suffering any injury.
- viii. Domestic Industry is not suffering any volume injury, price injury and that the plants are running at their best capacity utilizations. There is no need for continuation of Antidumping Duty on the import of subject goods from the subject countries.
- ix. The estimates of NIP, NSR and landed price show that there exists negative injury margin in the POI. Post POI also shows negative injury margin. Domestic Industry is not suffering any injury; there is no need for continuation of anti-dumping duty on the import of subject goods from the subject countries. There is no likelihood of continuation of injury as well to the domestic industry.
- x. It is undisputed fact that the landed value increased significantly because of the increase in export price in USD. The domestic producers are not dependent on imported material and therefore unaffected by depreciation in INR against USD. Such change is of lasting nature and continued for more than 3 years now. Therefore, there is no remote possibility for recurrence of injury to the domestic producers.
- xi. The production increased from 2,391,519 MT in base year to 2,405,410 MT in POI. The domestic producers have accepted during the public hearing that they are not suffering injury.

- xii. The total exports of domestic Industry have come down sharply from a figure of 2,00,354 MT in the year 2011-12 to 26,642 MT in the year 2014-15, which clearly falsifies the statement made by the Domestic producers that Domestic producers has to continue its exports to dispose of inventories.
- xiii. The domestic sales of the product increased from a figure of 20,06,729 MT in 2011-12 to 22,18,766 MT in 2014-15. The total sales, however, very marginally decreased from 24,19,438 MT in 2011-12 to 24,03,783 MT due to sharp decline in Captive Consumption & Exports.
- xiv. The largest Indian domestic producer "Tata Chemicals Ltd." imported material from its subsidiary from Kenya and from unrelated producers from EU and China. The domestic producer claimed that the product imported from Kenya was of lower grade and fetches lower price than the domestic producers in India. The price at which the domestic producers sold subject goods to the users after import, should be compared with the Net sale realization and the NIP.
- xv. The Domestic Producers achieved the optimal capacity utilization during the POI and injury period. The capacity indicated by them is only name plate capacity, the plants are worn out and they are not capable to achieve capacity utilization more than at which they are operating.
- xvi. Even after several years of duty, Soda Ash industry did not increase the capacity to such levels so as to meet the entire Indian demand. The purpose of ADD is to eliminate the trade-distorting effects of injurious dumping and not to create a monopolistic situation for the domestic industries.
- xvii. The capacity of the domestic producers has not increased from the original investigation which is under review. Further the claims of Domestic Industry about the investments made in the plants for increasing the capacity is not substantiated with any evidence
- xviii. As regard expansion plans, the domestic producers in ambiguous term are seeking protection to earn huge profits at the expense of the users. Here again the domestic producers made a false claim. The return of INR 1250 PMT is an average for the industry. It is not for the domestic producers who will expand capacities or the new entrant.
- xix. There is no injury to the domestic producers for last two years from imports examined with or without Anti-dumping Duty, it can be concluded that there is no need to continue Anti-dumping Duty which is an unnecessary burden on the users.
- xx. GHCL is operating at more than 87% during POI which is the maximum possible capacity utilization in these industries. GHCL is one of the major producers with capacity of 8, 50,000 MT. It is earning good amount of profit also from the business. Even than it has its compulsions to import the subject goods from various countries including the subject countries. It may be noted that they are importing the goods after payment of Anti-dumping Duty and then earning sufficient profit on resale of the same.
- xxi. Domestic Industry is choosing the figures as it is suiting them. Such an approach cannot be accepted. Even though import was taking place, they kept on increasing prices at extra-ordinary trend. As may be seen from the correct data reported by the domestic industry vide their submission dated 02.03.2016, in 2013-14, cost of sales increased only to 111, but selling prices increased to 117. In 2014-15 when cost of sales witnessed a decline by 1 percentage points to 110, selling prices jumped by 10 percentage points compared to previous year.
- xxii. The change in the prices of the subject goods in the exporting country and international market along with sales realization of the domestic industry should be considered for examination of lasting nature as the changes in prices of the subject goods are reflected in the world market and increase in export price to India is not a standalone event.
- xxiii. Annexure III under the AD Rules clearly says freight outward which is a post manufacturing expense shall not be considered for the purpose of NIP. The DI is now trying to create an impression that their contention is not NIP determination but determination of injury margin, in effect both are the same as the injury margin is considered as the difference between landed price of imports and NIP at ex-factory levels.
- xxiv. The claim that the duties should be continued to protect an anticipated future investment which is not of any concrete nature and such claims has no tenability.
- xxv. In cases where the injury margin itself is negative i.e., landed value is more than the NIP, no antidumping duty can be recommended by the Authority. Since no injury is caused to the domestic industry, anti-dumping duty should be withdrawn.

- xxvi. Super profits being generated by the domestic industry is directly related to the fact that imports are at par with the NIP and this difference is being taken advantage of by the domestic industry. The customers are suffering due to artificially inflated price of soda ash required for their industries, which in turn would have a carry forward on various industrial and consumer items.
- xxvii. The increase in prices is on account of the exchange rate as well as increased prices in the international market. Domestic producers enjoy the benefits of devalued rupee in terms of the increased landed value, there is no effect on their costs due to the fact that domestic producers are using raw material which is abundantly available in India itself.
- xxviii. Import price is highest in Gujarat. The high price in the region where subject goods is available in sufficient quantity and low price where supply is not available also establishes that the decision to buy is not dependent on price preference.
- xxix. There is no relation between import volume and prices and the domestic producers are earning huge profit irrespective of the import volume and prices. The users are ending up paying Anti-dumping Duty without any need of protection to the domestic producers.
- xxx. Imported goods which were resold were significantly higher than the landed value shown at the port of import resulting into a distorted Landed Value for the purposes of comparison of such Landed Value with the NIP and NSR.
- xxxi. The foreign exchange rate changed where value of INR depreciated significantly against USD. The cumulative effect of such changes resulted into increase in import prices.
- xxxii. There are no price Suppression and Depression even after the inclusion of the non- functional plants of the Domestic Producers. Therefore it may be inferred that the domestic Industry is not suffering any injury.
- xxxiii. Just as domestic industry at the time of initiation of investigation has to only provide evidence regarding existence of dumping, injury and causal link and not actually determine injury margin and dumping margin, similarly in case of review, the applicants are only required to file an application giving positive evidence on changed circumstances.
- xxxiv. The domestic producers have contended that the injury margin for non-cooperating exports should be determined on the basis of lowest prices reported in India. The Respondent denies the submissions as incorrect and submit that the Designated Authority should consider the Average weighted price for calculation of injury margin. In the present case exporters from the subject countries have participated in the investigation and even the Domestic producers have the related parties in the subject countries under the investigation. Therefore, the injury margin may be calculated on the basis of the data available with the Designated Authority and not at the lowest price reported in India.
- xxxv. The domestic producers have contended that Authority may consider only those transactions, where the injury Margin which are positive. The Respondent denies the submissions of the Domestic Industry as incorrect. There is absolutely no basis for making such a request and there is no provision anywhere, which allows consideration of only positive injury margin.
- xxxvi. The Domestic Producers have contended that the Designated Authority requires to look into the future investments of Domestic Industry as well as the Authority should analyze if any material retardation is caused to the Domestic Industry. The Respondents denies the submissions as incorrect. The Respondent submits that the Domestic Producers are claiming that they have made future investments during the time of public hearing as well. However they were unable to establish that they had made any investments after the imposition of antidumping duty to improve their capacity, whereas the demand of the subject goods had increased.
- xxxvii. DA is requested to also require the domestic producers to come clean regarding the imports made by them. It is necessary for them to clarify at what prices domestic producers import the subject goods. Further, since domestic producers have information of their net sales realizations, they must be aware whether imports made by them were above the net sales realization or not? Also, domestic producers must disclose the prices at which the imported goods were resold in the open market.
- xxxviii. Domestic producers have been predominantly selling their subject goods in Gujarat and region around Gujarat at a very good price. Admittedly, domestic producers are making huge profits. The price decline is stated to be high in West Bengal alone and the decline is not much in Gujarat and other parts of India.

- xxxix. In present case there is no relation between import volume and prices and the Domestic Producers are earning huge profit irrespective of the import volume and prices. The users are ending up paying Anti-dumping Duty without any need of protection to the Domestic Producers.

SUBMISSIONS MADE BY THE DOMESTIC INDUSTRY

50. The domestic industry has submitted as under:-

- i. Mere improvement in performance of the domestic industry is insufficient ground for revocation of antidumping duty. Rule 23(1A) mandates the Authority to examine the effect of the revocation of duty on domestic industry, instead of merely focusing on the present situation of domestic industry.
- ii. The meaning of lasting nature is evidently that the changes in circumstances are such that they would not reverse back to what it was earlier. The decline in import price clearly establishes that the changes were not of lasting nature and were purely temporary in nature.
- iii. Injury margin in case of non-cooperation of exporters should be determined on the basis of lowest price reported in India. Further, Authority must consider only injurious imports and ignore those imports which are above NIP. Negative injury margin does not mean withdrawal of antidumping duty.
- iv. The Authority is required to first examine whether the domestic industry has suffered material injury. If the authority comes to a conclusion that the domestic industry has not suffered material injury, the Authority needs to examine whether the domestic industry is threatened with material injury in the event of premature withdrawal of anti dumping duty. If not so, the Authority must examine whether continued dumping of the product under consideration is likely to materially retarded establishment of the domestic industry in the Country.
- v. As regards the claim that net selling price of domestic industry is above Rs. 19000 PMT that indexed figures show that the selling price is way below the net sales realization stated by the interested parties at the time of hearing.
- vi. As regards the issue of Capital employed based on books of accounts, the prescribed format is relevant only for determining continuation of injury and not potential injury and likelihood of injury. For likelihood of injury, potential situation is required to be seen.
- vii. As regards applicability of res judicata principle on issue of freight inclusion is concerned, the principle is applicable only when final judgment is made on issue. The issue as raised before the DA in original investigation is pending as an appeal before the Hon'ble Tribunal, therefore remains alive and valid presently. Further grounds for review mention 'injury margin has come down'.
- viii. As regards the contention that Domestic industry while arguing about freight is talking about injury margin on the surface when it actually means determination of NIP, is faulty as the two are different terms. There is no law or methodology provided to determine injury margin. Annexure III only relates to governing principles.
- ix. The reliance on Brazilian practices related to lesser duty rule is concerned, is appropriate since in the absence of guidelines on determination of injury margin, the practice and principles keep on developing. The incidence of freight is important is selective products and therefore has not been agitated heavily in the past.
- x. As regards several years of duty is concerned the antidumping duties were levied in 2012. The industry was incurring losses in 2011-12 and was making low level of profits and ROI till 2013-14. After imposition of duties, the situation of domestic industry gradually improved and market viability increased consequently resulting in planning of expansions. Arguments with regard to profiteering should be posed to exporters who are possibly looting the consumers in the domestic market.
- xi. The future investments are of a concrete nature and cannot be withdrawn. The reliance on EC case on imports of pure silk typewriter ribbon fabrics from China is misplaced as the facts are different. The demand of the product had been changing and there were no imports since almost 9 years among other differences.
- xii. As regards high profitability of domestic industry, it is seen that soda ash is a highly capital intensive, low raw material cost and high finished product freight industry. The freight costs constitute very high percentage of cost of production. Therefore this case should be seen in the light of peculiarities of the product under consideration.
- xiii. Export price in India has significantly declined in the post POI.
- xiv. Heavy discounts are being given on the list prices. Therefore, selling price (before discounts) are materially below the price lists.

- xv. As regards the argument of domestic industry charging artificially inflated prices, the Turkey prices and profits in their home market is much higher which dispels any similar concerns for the domestic industry.
- xvi. As regards issue of devaluation of rupee and exchange rate is concerned, the devaluation of rupee has also impacted domestic producers as they have to import various raw materials like Limestone, Coal, Coke etc. While exchange rate has changed even when considered in Indian rupee the imports occurring at present are materially below the NIP of domestic industry.
- xvii. Decline in captive consumption is because one domestic producer could not produce downstream product due to stiff competition. The decline has not adversely affected the overall consumption and is not a cause of injury to the domestic industry. Overall consumption of detergent has increased, thus there is no decline in consumption of Soda Ash for production of detergent.
- xviii. As regards not responding to the capacity utilization of domestic industry claims of interested parties is concerned the capacity utilization has in fact increased to higher levels.
- xix. There is no evidence or basis for the claim that comparison of landed value with NIP and NSR, price of resold imported goods were higher than the landed value shown at the port of import.
- xx. With regard to no denial of domestic industry to price undercutting methodology, it is established that there is no one methodology for determining price undercutting.
- xxi. As regards ROCE, the plants are being operated by industry are depreciated yielding very low returns. Since net fixed assets are unfair to domestic producers and don't represent true value the domestic producers have considered present value of investment for calculating ROCE.
- xxii. The valuation of inventory in financial accounting cannot be considered for present purposes. That wouldn't be in conformity with the specific rules of NIP which must be considered herein.
- xxiii. Present capital employed of domestic industry at present is not appropriate figure for determining return on capital employed. Present capital employed is against capacity of 29,94,435 MT; whereas *** Crores is being invested for enhancing capacities by 8 Lac MT. This itself clearly shows that the present capital employed is grossly insufficient to determine return required by the industry. Capacity with the domestic industry can be 8 lakh tones and not 78 lakh tons as has been alleged by the interested parties.
- xxiv. The import price in Gujarat is comparable. The price in North is comparatively higher and share of imports in Gujarat is less than 5% of total imports.
- xxv. As regards the argument that the landed value simpliciter cannot be used for comparison with NIP or NSR to assess injury margin or injury, it is submitted that majority of the imports from Kenya are directly by the consumers.
- xxvi. As regards the profit margin being considered unreasonable, it is submitted that any business making investment would legitimately expect such a return. The investment details of particularly Rohit Surfactants were enclosed with rejoinder to substantiate the point.
- xxvii. As regards reliance on Final Finding of Soda Ash from Turkey and Russia, the original finding issued by the Designated Authority did not include capacity of M/s Tuticorin Alkali Chemicals & Fertilizers Ltd as it was not an applicant and part of domestic industry in the said investigation. Further the company was not producing subject goods.
- xxviii. As regards the allegation of adjustment of 20% in price, the domestic industry claims no such adjustment.
- xxix. There is no evidence to support the possibilities that there may be grades that are not substitutable.
- xxx. As regards the argument that domestic producers are unable to supply in some areas and therefore imports should not be charged with antidumping duties, the domestic industry holds that for this reason freight should be added while determining injury margin.
- xxxi. As regards the domestic industry's proximity to raw material availability is concerned, such proximity has lowered cost in favour of consumer interests. The freight cost incurred on raw materials is being considered as a part of cost of production and NIP, which is being borne by the consumers. By linking price to cost of production, the Designated Authority has in a way taken away the efficiencies created by a producer in optimizing itself with overall economics.

- xxxii. The domestic producers have serious intentions of making investments. Even at present rate of profit the fresh investments will be recovered in 32 years. Further the weighted average quantum of anti dumping duties during the POI was Rs.1,290 PMT considering that exports have been made by exporters named in the duty table. Thus, if the domestic industry were to reduce its price by the quantum of anti dumping duty, the fresh investment now being made shall be recovered in 34 years! Thus, possible withdrawal of anti dumping duty shall imply serious reconsideration on these investments.
- xxxiii. The price reported by IHS Global Soda Ash service is a good indicator of the prevailing prices of subject goods in the domestic markets in various countries/regions. Further, since the journal mentions high and low prices, domestic producers have adopted average price.
- xxxiv. The increase in landed price of imports was 32% and not 56% as claimed by the interested parties.
- xxxv. The price increased by the domestic industry was 27% as against 65% claimed by the interested parties. This is due to check on dumping of the product in the country.
- xxxvi. Profitability of domestic industry is far adverse in Southern and Eastern regions due to import competition.
- xxxvii. The overall demand has increased over the injury period. Imports have increased over the injury period despite antidumping duty in force.
- xxxviii. Imports have also increased in relation to production and imports in relation to consumption have declined.
- xxxix. Price would be significantly positive in the event of revocation of anti dumping duty.
- xl. Indian producers of soda ash are located in the State of Gujarat due to availability of raw material. Due to substantial transportation costs the selling price of the domestic industry should be compared with the landed price of imports only after adding transportation costs.
- xli. Authority should determine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India. Premature withdrawal of duties is likely to lead to significant price undercutting in the market.
- xl.ii. There are no current price suppression or depression effects with the antidumping duties in force. However, if the duties are withdrawn the dumping would cause significant depressing effect on the prices of the domestic industry in the market.
- xl.iii. Performance of the domestic industry in terms of production, and capacity utilization, profits, return on investments, cash flow has started improving with imposition of antidumping duty. The withdrawal of duties will lead to recurrence of material injury.
- xl.ii. The causal link has already been established in the original investigation. The dumped imports from subject countries have increased despite antidumping duties in force.
- xl.ii. Subject imports are available at prices lower than domestic prices. The excess capacities of producers in subject countries show likelihood of increase in volume of dumped imports in case of revocation of duties.
- xl.ii. Price undercutting leads to consumers preferring imported material resulting in domestic industry losing sales. This leads to increase in inventories leading to decline in production and further decline in capacity utilization.
- xl.ii. As regards price effect the price undercutting will lead to a situation where the domestic industry is prevented from effecting price increases, which leads to decline in profitability. This decline leads to decline in gross profit earned leading to decline in cash profits resulting in further decline in the return on capital employed.
- xl.ii. The raw material utilization and utilities utilization should not be considered at the best achieved levels in the past because the cause of increase in consumption is not inefficient utilization of such inputs but changes in input physical circumstances. Designated Authority should consider the consumption inputs and the reasons for the changes in consumption pattern so as to normate the same.

- xlix. The captive inputs should be considered at market price. Actual raw materials and utilities consumption should be considered. Actual cost of production should be determined instead of a notional lower cost of production in order to determine a price which can be compared with the import price in order to assess injury margin.
- i. A comparison of non injurious price of the domestic industry without including associated freight with landed price of imports after adding associated freights will not constitute a fair comparison and would lead to gross under estimation of the injury suffered by the industry.
- ii. Freight cost forms a part of cost of production. The domestic industry incurs the freight cost for shifting the goods from factory to depots/warehouses which are extended factory gates. Title of goods remains with the producers and gets transferred to the purchasers only on clearance of the material from warehouses.
- iii. Since the customs duty is added before comparing with non-injurious price even if not paid, the inland freight being incurred in the domestic product must also be added. This was followed in the matter of white cement and should be followed in the present investigation as well.
- liii. Non-consideration of factors such as freight cost incurred by domestic industry, significant difference in payment terms offered by foreign producers/ exporters and Indian industry leading to imports, disparities in taxes & duties between domestic and imported product, existence of present NIP law and interpretations drawn there from, absence of codified practice on key elements despite existence of NIP law are some of the examples which are individually and collectively impacting the quantum of anti-dumping duties by reducing the protection level that the domestic industry should be entitled under anti-dumping law.

EXAMINATION BY THE AUTHORITY

51. The Authority has taken note of the arguments and counter-arguments of the interested parties on injury. The non injurious price of the domestic industry has been determined as per the guidelines laid down under Annexure III of the Anti-dumping Rules.
52. As regards the contention of the domestic industry for consideration of freight incurred by domestic industry as a factor in injury analysis, the Authority notes that first of all Annexure III of the Anti-dumping Rules does not permit such a practice. Moreover, the final finding of the Authority in the anti-dumping investigation concerning imports of White Cement, involving the freight issue is subjudice before CESTAT. Similar cases are also pending before the Delhi High Court.
53. The injury analysis made by the Authority hereunder *ipso facto* addresses the various submissions made by the interested parties.

L. Cumulative assessment

54. Attention is invited to Annexure II para (iii) of the Anti-dumping Rules which provides that in case imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti dumping investigations, the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that: -
- a. the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two per cent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three per cent of the import of like article or where the export of individual countries is less than three per cent, the imports collectively accounts for more than seven per cent of the import of like article and
- b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
55. In this regard the Authority observes that:
- i. the margins of dumping from each of the subject countries are more than the limits prescribed above;
- ii. the volume of imports from each of the subject countries is more than the limits prescribed;
- iii. Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate since the exports from the subject countries directly compete with the like articles offered by the domestic industry in the Indian market. This is evident from the following:

- a. The subject goods manufactured by the producers from the subject countries inter-se and in comparison to the product manufactured by the domestic industry. In other words, the subject goods supplied from various subject countries and by the domestic industry are inter-se like articles.
- b. There are common parties who are resorting to use of imported material from various sources and domestic material. Imported and domestic materials are, therefore, being used interchangeably and there is direct competition between the domestic product & imported product.
- c. The exporters from the subject countries and domestic industry have sold the same product in the same periods to the same set of customers. The sales channels are comparable.
- d. Volume of imports from each of the subject countries is significant.
- e. Consumers make purchase decision on the basis of prices offered by various suppliers.

56. In view of the above, the Authority considers it appropriate to cumulatively assess the effects of dumped imports of the subject goods from Turkey and Russia on the domestic industry in the light of conditions of competition between imported product and like domestic product. The Authority notes that the margin of dumping and quantum of imports from subject countries are more than the limits prescribed above.

57. The Authority has taken note of submissions made by the interested parties. Annexure II of the Anti-dumping Rules provides for objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in domestic market for the like articles; and (b) the consequent impact on domestic producers of such products. While examining the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to price effect of dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increase which would have otherwise occurred to a significant degree.

58. As regards the impact of dumped imports on the domestic industry, Para (iv) of Annexure-II of Anti-dumping Rules states as follows:

“The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.”

59. For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such further indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II(iv) of the Rules supra.

60. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and arguments of the interested parties. For analyzing the injury parameters, all relevant documents including the balance sheet of the Domestic Industry have been examined and verified by the Authority. The issues relating to the interest of the Indian industry and other issues have also been dealt by the Authority under appropriate headings.

Demand and market share

61. For the purpose of assessment of the domestic consumption/demand of the subject goods, the sales volume of the domestic industry and other Indian producers have been added to the total imports into India and the same has been summarized below:

Particular	UOM	2011- 12	2012- 13	2013-14	POI	Post POI	Post POI Annualized
Demand in India-Including Captive							
Sales of Domestic Industry	MT	14,31,825	15,19,990	15,78,148	16,01,302	8,22,679	16,45,357
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>106</i>	<i>110</i>	<i>112</i>	<i>115</i>	<i>115</i>
Sales of Other Indian producers	MT	7,51,493	7,26,475	7,37,588	7,55,169	3,79,582	7,59,164
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>97</i>	<i>98</i>	<i>100</i>	<i>101</i>	<i>101</i>
Total Domestic Sales	MT	21,83,318	22,46,466	23,15,737	23,56,471	12,02,261	24,04,521
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>103</i>	<i>106</i>	<i>108</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
Imports- Subject Countries	MT	1,10,695	1,19,014	62,103	49,071	19,305	38,611
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>108</i>	<i>56</i>	<i>44</i>	<i>35</i>	<i>35</i>
Imports- Other Countries attracting duties	MT	3,29,828	5,53,416	4,89,270	6,73,706	3,47,389	6,94,779
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>168</i>	<i>148</i>	<i>204</i>	<i>211</i>	<i>211</i>
Imports- Other Countries	MT	3,952	19,799	16,214	1,201	1,123	2,246
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>501</i>	<i>410</i>	<i>30</i>	<i>57</i>	<i>57</i>
Total Demand	MT	26,27,793	29,38,694	28,83,324	30,80,449	15,70,079	31,40,157
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>112</i>	<i>110</i>	<i>117</i>	<i>119</i>	<i>119</i>
Market Share in Demand							
Domestic Industry	%	54.49	51.72	54.73	51.98	52.40	52.40
Other Indian Producers	%	28.60	24.72	25.58	24.51	24.18	24.18
Indian Producers as a whole	%	83.09	76.44	80.31	76.50	76.57	76.57
Subject Countries	%	4.21	4.05	2.15	1.59	1.23	1.23
Other Countries attracting duties	%	12.55	18.83	16.97	21.87	22.13	22.13
Other Countries	%	0.15	0.67	0.56	0.04	0.07	0.07

62. The Authority notes that demand has increased during the POI as compared to the base year. The demand has shown increasing trend during the post POI as well. The market share of the domestic industry as well as other Indian producers has fallen during the POI as compared to the base year. However, during the post POI, the market share of the domestic industry has shown an upward trend. On the contrary, the market share of the subject countries has drastically fallen during the POI as compared to the base year and further fallen during the post POI.

M. Volume Effects of Dumped Imports**Import Volume and Market Share**

63. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from DGCIS. The volume of imports of the subject goods from the subject countries have been analysed as under:

Particulars	UOM	2011- 12	2012- 13	2013-14	POI	Post POI	Post POI Annualized
Import Volume							
Turkey	MT	61,670	89,842	62,103	42,114	10,125	20,250
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>146</i>	<i>101</i>	<i>68</i>	<i>33</i>	<i>33</i>
Russia	MT	49,025	29,171	-	6,957	9,180	18,361
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>60</i>	<i>-</i>	<i>14</i>	<i>37</i>	<i>37</i>
Subject Countries	MT	1,10,695	1,19,014	62,103	49,071	19,305	38,611
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>108</i>	<i>56</i>	<i>44</i>	<i>35</i>	<i>35</i>

Particulars	UOM	2011- 12	2012- 13	2013-14	POI	Post POI	Post POI Annualized
Other Countries attracting duties	MT	3,29,828	5,53,416	4,89,270	6,73,706	3,47,389	6,94,779
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>168</i>	<i>148</i>	<i>204</i>	<i>211</i>	<i>211</i>
Other Countries	MT	3,952	19,799	16,214	1,201	1,123	2,246
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>501</i>	<i>410</i>	<i>30</i>	<i>57</i>	<i>57</i>
Total Imports	MT	4,44,475	6,92,228	5,67,587	7,23,978	3,67,818	7,35,636
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>156</i>	<i>128</i>	<i>163</i>	<i>166</i>	<i>166</i>
Market Share							
Turkey	%	13.87	12.98	10.94	5.82	2.75	2.75
Russia	%	11.03	4.21	-	0.96	2.50	2.50
Subject Countries	%	24.90	17.19	10.94	6.78	5.25	5.25
Other Countries attracting duties	%	74.21	79.95	86.20	93.06	94.45	94.45
Other Countries	%	0.89	2.86	2.86	0.17	0.31	0.31
Total	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

The Authority notes that from the subject countries, imports have significantly declined during the POI as compared to the base year despite increasing demand. Imports from subject countries have further declined during the post POI.

N. Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry

64. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject countries has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis the cost of production, Net Sales Realization (NSR) and the Non-injurious Price (NIP) of the Domestic industry have been compared with the landed cost of imports from the subject countries.

Price suppression and depression effects of the dumped imports:

65. The price suppression and price depression effect of the dumped imports has also been examined with reference to the cost of production, net sales realization and the landed values of the subject goods from the subject countries in relation to injury period including POI and Post POI.

Particulars	UOM	2011- 12	2012- 13	2013-14	POI	Post POI
Landed price of Subject Imports	Rs./MT	12,099	15,223	14,730	16,508	17,979
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>126</i>	<i>122</i>	<i>136</i>	<i>149</i>
Cost of Sales	Rs./MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>101</i>	<i>110</i>	<i>106</i>	<i>102</i>
Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>108</i>	<i>113</i>	<i>123</i>	<i>125</i>

From the above information, the Authority notes that the landed price of the imports from the subject countries has increased during the POI as compared to the base year. The same has further increased during the post POI. The cost of sales of the domestic industry has also increased during the POI as compared to the base year. But, the increase in cost of sales of the domestic industry is much less as compared to the increase in the landed price from the subject countries. During the post POI, while the landed price has increased, the cost of sales of the domestic industry has fallen.

Price undercutting and Price underselling effects**Price Undercutting**

66. While working out the net sales realization of the domestic industry, the rebates, discounts and commissions offered by the domestic industry and the central excise duty paid have been deducted. The landed value of imports has been calculated by adding 1% landing charge and applicable basic customs duty and education cess to the export / CIF prices from the subject countries, as reported by each responding exporter. For others category, landed price has been computed by adding applicable basic customs duty and education cess to the Assessable value as per DGCI& S data.

Particulars	Unit	2011- 12	2012- 13	2013-14	POI	Post POI
Turkey						
Landed price of imports	Rs./MT	11,610	15,295	14,730	16,548	19,475
Net Sales Realisation	Rs./MT	***	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs./MT	***	***	***	***	(***)
Price Undercutting	%	***	***	***	***	—***
Price Undercutting	% Range	20-25	0-5	10-15	5-10	Negative
Russia						
Landed price of imports	Rs./MT	12,714	15,003	-	16,265	16,330
Net Sales Realisation	Rs./MT	***	***	-	***	***
Price Undercutting	Rs./MT	***	***	-	***	***
Price Undercutting	%	***	***	-	***	***
Price Undercutting	% Range	10-15	5-10		10-15	10-15
Subject countries as a whole						
Landed price of imports	Rs./MT	12,099	15,223	14,730	16,508	17,979
Net Sales Realisation	Rs./MT	***	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs./MT	***	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***	***
Price Undercutting	% Range	15-20	5-10	10-15	5-10	0-5

67. The Authority notes that during the POI, the price undercutting effect of dumped imports is positive in respect of imports from the subject countries individually and collectively. During the post POI, while the price undercutting from Turkey is negative, from Russia it is positive and from the subject countries as a whole, the price undercutting effect is positive.

Price Underselling

68. For the purpose of price underselling the landed prices of the imports from subject countries have been compared with the Non-injurious price (NIP) of the domestic industry. The Authority notes that the price underselling is negative during the POI as well as post POI.

POI

Particulars	Landed Value US\$/MT	Non Injurious Price US\$/MT	Price Underselling US\$/MT	Price Underselling %	Price Underselling % Range
Turkey	268.24	***	(***)	(***)	Negative
Russia	263.65	***	(***)	(***)	Negative

Post POI

Particulars	Landed Value US\$/MT	Non Injurious Price US\$/MT	Price Underselling US\$/MT	Price Underselling %	Price Underselling % Range
Turkey	301.52	***	(***)	(***)	Negative
Russia	252.82	***	(***)	(***)	Negative

O. Examination of other Economic Parameters of Domestic Industry**Production, Capacity, Sales and Capacity Utilization**

69. The Production, Capacity and Capacity Utilization details are as follows:

Particulars	UOM	2011- 12	2012- 13	2013-14	POI	Post POI	Annualised Post POI
Installed capacity	MT	19,61,000	19,61,000	19,61,000	19,61,000	10,15,500	20,31,000
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>52</i>	<i>104</i>
Production	MT	15,78,674	16,11,377	16,02,002	16,45,154	8,48,136	16,96,272
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>102</i>	<i>101</i>	<i>104</i>	<i>54</i>	<i>107</i>
Capacity Utilization	%	80.50%	82.17%	81.69%	83.89%	83.52%	83.52%
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>102</i>	<i>101</i>	<i>104</i>	<i>104</i>	<i>104</i>
Domestic Sales	MT	12,67,561	13,86,286	14,66,643	15,03,224	7,68,250	15,36,499
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>109</i>	<i>116</i>	<i>119</i>	<i>61</i>	<i>121</i>
Demand	MT	26,27,793	29,38,694	28,83,324	30,80,449	15,70,079	31,40,157
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>112</i>	<i>110</i>	<i>117</i>	<i>119</i>	<i>119</i>

From the above information, the Authority notes that the capacity of production of the domestic industry has remained constant during the injury period including the POI. However, during the post POI the capacity has been enhanced. Both sales and capacity utilization have increased during the POI as compared to the base year in line with increase in demand. During the post POI, while capacity utilisation has marginally declined, sales have further increased.

Inventories:

70. Data relating to inventories shows as follows:

Particulars	UOM	2011- 12	2012- 13	2013-14	POI	Post POI
Opening	MT	***	***	***	***	***
Closing	MT	***	***	***	***	***
Average	MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>101</i>	<i>101</i>	<i>73</i>	<i>122</i>

It is noted that average inventories have remarkably decreased during the POI as compared to the base year. However, the average inventory has shown increasing trend during the post POI.

Profits and actual and potential effects on the cash flow

71. With regard to Profit/Loss and cash flow, it is noted that the profitability of domestic industry in terms of profit before tax and interest and cash profit has remarkably increased in the POI as compared to base year. The position has further improved during the post POI.

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI	Post POI	Annualised Post POI
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>101</i>	<i>110</i>	<i>106</i>	<i>102</i>	<i>102</i>
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>108</i>	<i>113</i>	<i>123</i>	<i>125</i>	<i>125</i>
Profit/Loss	Rs/MT	***	***	***	***	***	***

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI	Post POI	Annualised Post POI
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	176	146	293	356	356
Profit/Loss	Rs.Lacs	***	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	193	169	347	216	432
PBIT	Rs.Lacs	***	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	146	133	215	128	256
Cash Profit	Rs.Lacs	***	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	168	153	270	171	342
Return of investment	%	***	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	141	140	233	279	279

Employment, wages and productivity

72. The data relating to employment, wages and productivity show as follows:

Particulars	UOM	2011- 12	2012- 13	2013-14	POI	Post POI	Annualised Post POI
Productivity per employee	MT	***	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	98	99	102	105	105
Employment	Nos.	***	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	104	103	102	102	102
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	113	113	117	67	133

It is noted that there was marginal increase in the number of employees as well as productivity during the POI and post POI as compared to the base year. But, wages have increased significantly during the POI as well as post POI as compared to the base year.

P. Magnitude of dumping

73. It is observed from the section pertaining to Dumping Margin above that dumping margins in respect of the imports of the subject goods from the subject countries are positive and substantial during the POI as well as post POI.

Growth

74. The Authority notes that the growth of the domestic industry was positive during POI as well post POI.

Ability to raise funds:

75. It is noted that the domestic industry has not enhanced its capacity of production of the subject goods from the base year to POI. This signifies that their ability to raise capital investment has not been affected.

Q. Magnitude of Injury and Injury Margin

76. The proposed non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority has been compared with the landed value of the exports from the subject countries for determination of injury margin during POI and Post POI. The proposed injury margin thus determined is as under:

POI

Country	Exporter/ Producer	NIP US\$/MT	Landed Value US\$/MT	Injury Margin US\$/MT	Injury Margin %	Injury Margin % Range
Turkey	Soda Sanayii A.S	***	***	-***	(***)	Negative
	ETI Soda	***	***	-***	(***)	Negative
	Non-Cooperative	***	***	-***	(***)	Negative
Russia	All	***	263.65	-***	(***)	Negative

Post POI

Country	Exporter/ Producer	NIP US\$/MT	Landed Value US\$/MT	Injury Margin US\$/MT	Injury Margin %	Injury Margin % Range
Turkey	Soda Sanayii A.S	***	***	-***	(***)	Negative
	ETI Soda	***	***	-***	(***)	Negative
	Non-Cooperative	***	***	-***	(***)	Negative
Russia	All	***	252.82	-***	(***)	Negative

The Authority notes that the injury margin is negative in respect of the subject countries during POI as well as post POI. The injury margin is also negative in respect of the individual cooperative exporter from Turkey during POI as well as post POI.

R. Conclusion on material injury

77. The Authority notes that while the capacity of production has remained constant throughout the injury period including the POI, the performance of the domestic industry has improved remarkably in terms of production, sales volumes, profit, cash profit, return on capital employed and inventory. The market share has declined during the POI as compared to the base year. During the post POI, the economic parameters has shown continued improvement including increased trend in the market share. Further, the net sales realization is more than the landed price from the subject countries during the POI as well post POI. Moreover, while the price undercutting and underselling effects are negative and price depression and suppression effects are absent during POI as well as post POI. Thus, the Authority notes that the tremendous improvement in the economic health of the domestic industry during POI and continued improvement during post POI period do not exhibit any material injury.

S. Other Known Factors & Causal Link

78. Having examined the existence of material injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, in terms of its price undercutting, underselling and price suppression and depression effects, other indicative parameters listed under the Indian Rules and Agreement on Anti-Dumping have been examined by the Authority to see whether any other factor, other than the dumped imports could have contributed to injury to the domestic industry, as follows:-

(a) Volume and prices of imports from third countries

The Authority notes that during POI, imports of the subject goods from countries other than the subject countries and countries attracting anti-dumping duty have remained very minimal in volume.

(b) Contraction of demand and changes in the pattern of consumption.

The Authority notes that there is no contraction in the demand during the POI. On the contrary, overall demand for subject goods has shown improvement during the POI as well as post POI.

(c) Developments in technology:

The Authority notes that none of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in technology that could have caused injury to the domestic industry.

(d) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

The Authority notes that the subject goods are freely importable. The domestic industry is the major producer of the subject goods and account for significant domestic production and sales. Further there is no perceptible competition among the domestic producers, except that is obvious of a market economy.

(e) Export performance of the domestic industry:

The table below summarises the performance of the domestic industry in respect of exports made by them.

Particulars	UOM	2011- 12	2012- 13	2013-14	POI	Post POI	Annualised Post POI
Exports	MT	***	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>28</i>	<i>34</i>	<i>14</i>	<i>4</i>	<i>8</i>

The Authority notes that the export performance of the domestic industry has fallen drastically during the POI as compared to the base year. However, during the post POI, the export performance of the domestic industry has shown some improvement vis-à-vis the POI, but remained much below the performance during the base year.

79. From the above analysis, the Authority notes that neither the listed known parameters, nor the other factors analysed above, show any injury to the domestic industry, either during POI or post POI. The economic health of the domestic industry has improved remarkably during the POI as compared to the base year despite continued dumping of subject goods from the subject countries. Further, the post POI performance of the domestic industry also shows positive trends. Therefore, it's a scenario of continuing dumping without injurious effect on the domestic industry.

T. Likelihood of continuation or recurrence of injury

80. In a review investigation, the Authority has to determine as to whether the subject goods are continuing to enter the Indian market at dumped prices or are likely to be exported at dumped prices from the subject countries in the event of withdrawal of anti dumping duties. It is also pertinent to examine whether injury to the domestic industry is likely to recur due to these dumped imports if the duty is removed or varied. The Authority examined the likelihood of continuation or recurrence dumping and injury considering the parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure II (vii) of the Rules, which states as under:

"A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances, which would create a situation in which the dumping would cause injury, must be clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the Designated Authority shall consider, inter alia, such factors and;

a. a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation.

b. Sufficient freely disposable or an imminent, substantial increase in capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian market, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports.

c. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely to increase demand for further imports and,

d. Inventories of the article being investigated."

Submissions made by the Applicant and other interested parties

81. Following submissions have been made by the applicant and other interested parties:

- i. The circumstances in which the AD duty was imposed on the exporter have under gone substantial changes of very lasting nature and the situation warrants withdrawal of existing AD duties since the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur if the present duties are removed or varied.

- ii. The understanding of the domestic producers that unless the dumping ceased or there is no likelihood of recurrence of dumping, the duty cannot be withdrawn is incorrect. It is legally required to withdraw duty if injury or likelihood of injury to the Domestic Industry is absent.
- iii. The domestic industry has not conclusively refuted the submission based on evidences that injury to the domestic industry is not likely to continue or recur, if the said anti-dumping duty is removed or varied and is therefore no longer warranted which shows there is no likelihood also.
- iv. There is no evidence to show that exporters in subject countries are having sufficient freely disposable or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased exports to Indian markets.
- v. In the present case, crucial parameters such as landed price of imports, non-injurious price and injury margin have undergone significant changes. the above facts itself constituted sufficient ground for initiation of investigation and further establishes injury to the domestic industry is not likely to continue or recur in the event of revocation of existing AD duties.
- vi. The domestic producers may be treated as non-cooperating and duty may be withdrawn immediately with effect from the date of commencement of POI. Domestic producers are not affected by volume and value of imports; therefore, there is no possibility of injury or any recurrence of injury if the Anti-dumping Duty is withdrawn. The fact that the major domestic producer is also importing the subject goods also supports the conclusion that there is no requirement for continued imposition of Anti-dumping Duty.
- vii. The price of subject goods from Turkey have increased significantly and volumes reduced and the price at which the subject goods were imported are not making any injurious effect on the domestic industry. Thus, there is no likelihood of continuation or recurrence of dumping in case of withdrawal of duty.
- viii. ETI Soda is running at a utilization of 90% to 100% level which is above optimal level. The company is realizing benevolent volume and price levels for the subject goods produced by it and ETI Soda is not under any volume pressure not it has any imminent fresh additional available volume. The company isn't having any significant inventory levels also. The inventories were less 1% of the total production by the company.
- ix. The circumstance in which anti-dumping duty was imposed has undergone substantial changes of lasting nature without any injury to the domestic industry and no likelihood of recurrence. Therefore, the duty needs to be withdrawn.

Submissions made by the Domestic Industry

82. Following submissions have been made by Domestic industry

- i. Petitioner is obliged to provide information on likelihood and has failed to supply the authority with prima facie evidence in this regard. There must be evidence pertaining to relevant parameters while seeking initiation of investigation.
- ii. As regards capacity expansion by domestic industry, the Designated Authority may kindly examine whether withdrawal of antidumping duty is likely to cause injury to the domestic industry both in respect of capacities which are already installed and operational capacities that have not been installed so far and which shall become operation in near future.
- iii. The dumping margin determined in previous investigations and present investigation is significant. Significant positive dumping and injury margins itself warrants continuation of antidumping duty.
- iv. Import prices at present have declined below the levels prevailing at the time of original investigation. The prices are below the NIP of the domestic industry even without considering various arguments of domestic industry with regard to determination of injury margin. This shows that alleged change in circumstances were highly temporary in nature and were not of lasting nature.
- v. Price undercutting without anti-dumping duty is positive and significant showing clear likelihood.
- vi. Current global economy situation shows that the market situation in the product under consideration is not likely to improve. The revocation of antidumping would lead to import prices being materially below the selling price of the domestic industry. The consumers would therefore switch to imported product which would lead to significant increase in imports of the product.

- vii. Significant costs have been incurred, in the expansion of capacities by the domestic industry that is in process of being added. This should be considered while determining likelihood of injury in the event of withdrawal of antidumping duty. The fresh investments of domestic industry shall suffer losses if domestic industry sells the product at a price prevailing in POI.
- viii. The injury margin for likelihood purposes should be determined on the basis of weighted average of NIP for present and potential production, i.e. the expansions must be considered.
- ix. The CESTAT decision on Hindustan Lever is not relevant as it has been set aside and the reliance on CESTAT decision on Jindal Stainless Ltd is misplaced as there was no evidence of likelihood of injury and nor that fact was argued.
- x. Reliance on Forum of Acrylic Fibre Manufacturers case is misplaced as unlike the case the landed value is not much above the level of non injurious price or selling price of the domestic industry. There are various other parameters that establish likelihood of recurrence of dumping and injury in the event of withdrawal of antidumping duty.
- xi. The decline in exports coupled with increase in import price by ETI post imposition of anti dumping duty itself shows that the company cannot export without dumping. Mere changes in circumstances do not mandate premature withdrawal of anti dumping duty.
- xii. The reason that ETI has no inventories is because of the market available in Europe due to closure of Tata Chemicals production facility there. The claim of no capacity expansion is not true. The public research on the company shows that the company is aiming to become the biggest producer of Soda Ash in Europe.

Examination by the Authority

83. Rule 23 of Anti-dumping Rules of India requires the Authority to examine the need for continued imposition of the duty from time to time. In this regard, the Authority notes as under:

Volume of Exports Post- POI

84. In order to examine, the likelihood of injury to the domestic industry due to dumping of the subject goods from the subject countries, the Authority has undertaken analysis of the volume of exports of the subject goods to India from the subject countries during the POI and post-POI periods. The Authority notes that the volume of the exports from subject countries to India during the POI and post POI on the basis of DGCI&S data was 49071 MT and 38611 MT (Annualised), showing a decline in exports. But, mere growth in exports, even at dumped prices, does not indicate a likely situation justifying continued imposition of anti-dumping duty, unless of course, such imports are likely to cause injury to the domestic industry.

Market share of Subject Countries in the Indian market

85. The Authority notes that the market share of the subject countries has drastically fallen during the POI as compared to the base year and the declining trend continued during the post POI as well. On the contrary, the market share of the domestic industry has also declined during the POI as compared to the base year, but showing upward trend during the post POI. Thus, the position indicates that the market share of the domestic industry has not been impacted by the imports from the subject countries.

Price attractiveness of Indian market

86. The Authority notes that the landed value from the subject countries is more than the NIP. However, the undercutting effect is positive during POI and post POI from the subject countries. The underselling effects are negative during POI as well as post POI. Thus, in the event of the revocation of anti-dumping duties, the Indian prices would not be too attractive to the foreign producers and there is no likelihood that Indian consumers would import substantially due to increasing demand.

Export orientation of foreign producers

87. Even if the subject countries are export oriented, export orientation among the producers of the subject goods in the subject countries itself cannot be a strong likelihood factor unless backed by favorable market conditions and weak domestic industry in India. Although there is high demand for the subject goods in India, the prices prevailing in Indian market and the strong domestic industry base may not be conducive for the subject countries to target Indian market in the event of revocation of the duties.

Level of current and past dumping margin

88. The Authority notes that during the POI, the dumping margin in the original investigation as well as the present MTR are positive. In the post POI, the dumping margin in respect of the cooperative exporters of Turkey is negative, but the country as a whole, it is positive. In case of Russia, the dumping margin is positive both during the POI as well as post POI. But, dumping of any magnitude has no relevance under the Indian anti-dumping law as long as it does not cause injury to the domestic industry. In the present investigation, injury margin is negative in the POI as well as post POI periods, thereby indicating no injury to the domestic industry and no likelihood of injury as well in the event of revocation of the duties.
89. The essential facts of the investigation, as analysed by the Authority in this finding, sufficiently prove that despite continued dumping of subject goods from the subject countries, the economic condition of the domestic industries has improved remarkably and indicate further improvement during the post POI. Thus, the changed circumstances, as alleged by the applicant, are not transient but there to stay in favour of the domestic industries in the event of revocation of the duties.

U. Post Disclosure Comments

90. The following are the post disclosure comments made by the petitioners and other interested parties and considered relevant by the Authority:
- i. No Effective Opportunity of hearing was given by the authority.
 - ii. The domestic industry is performing well and the AD duty is being misused by them to achieve maximum profits. The injury to the domestic industry is not likely to continue or recur, if the applicable anti-dumping duty is removed or varied. Therefore, the Authority should recommend withdrawal of the anti dumping duties.
 - iii. The normal value determined by the authority for the subject countries is not as per the relevant legal provisions.
 - iv. The market share of the domestic industry has remained unaffected by imports from the subject country. The performance of the domestic industry has improved in respect to all the economic parameters.
 - v. The demand for the subject goods has increased by 17% in the POI as compared to the base year. However, the capacity of the domestic industry has remained the same. Therefore, the imports have increased purely to cater to the increasing demand which the domestic industry is unable to meet.
 - vi. Thus, the only reason for the imports coming into India is the presence of a demand-supply gap. In particular, the users are left with no option but to import as a result of the inability of the domestic industry to cater to the rising demand.
 - vii. The imports have been coming in at prices that are not undercutting underselling the prices of the domestic industry and further are not suppressing or depressing the prices of the domestic industry. Therefore, there is no negative price effect with respect to imports from the subject countries.
 - viii. That there is no reason for the Authority to conclude that there is a likelihood of continuance or recurrence of injury with respect to imports from the subject country. Therefore, in the absence of material injury to the domestic industry and further no likelihood of recurrence of injury to the domestic industry, the duty imposed on the subject goods should be discontinued.
 - ix. Considering the improved performance of the domestic industry, absence of injury and likely injury, the anti-dumping duty should be revoked.
91. The following are the post disclosure comments made by the domestic industry and considered relevant by the Authority:
- i. The domestic industry has established that there was significant likelihood of injury in case of withdrawal of anti dumping duties. However, the designated authority has shifted the obligation of establishing likelihood onto the domestic industry instead of the petitioners. The entire legal basis on which the present investigation has been initiated and conducted is inconsistent with Rule 23 of the AD Rules.
 - ii. The time that was made available for filing comments to disclosure statement is grossly inadequate.

- iii. The dumping margin in the original investigation as well as the present MTR are positive and the dumping margin in the post POI of the present investigation is also positive. Thus, in the event of premature withdrawal of the anti-dumping duties, dumping shall not only continue but also intensify. The conclusion that dumping of any magnitude has no relevance under the anti-dumping law as long as it does not cause injury to the domestic industry is legally not correct.
- iv. Authority determined price attractiveness without considering relevant factors and parameters. Price attractiveness is a comparative analysis. Therefore, export price from subject countries to each of third countries is required to be examined to ascertain volume of exports which is below NIP and volume of exports above NIP.
- v. Increase in imports, significant surplus capacities with the exporting countries, significant price undercutting implies price depression in the event of cessation of anti dumping duties coupled with likelihood of intensified dumping clearly establishes likelihood of injury in the event of premature withdrawal of duty. Injury margin criteria cannot be applied for determination of injury.
- vi. The disclosure statement has been issued without examining the likelihood of injury in respect of exports to each of the third countries from subject countries.
- vii. Authority should differentiate on transaction by transaction basis dumped and injurious import volumes from un-dumped and non-injurious ones on the basis of comparison of normal value with export price and NIP with landed price of imports and then calculate dumping and injury margin.
- viii. The producers in major subject countries (and in particular, China and Turkey) are holding huge unutilized capacities. Thus, in the event of withdrawal of anti-dumping duties, these producers are likely to find good market opportunities in India and are likely to export significant volumes at a price below the NIP determined by the Authority, as the exporters are already selling at such lower prices in third countries. The Authority should therefore examine the behavior of exporters in various third countries and unutilized capacities with them.
- ix. Significant capacity additions are being made by the domestic industry after incurring significant investments. The Authority should examine whether withdrawal of anti dumping duty is likely to cause injury to the domestic industry both in respect of capacities which are already installed & already operational and capacities that have not been installed so far and which shall become operational in near future.
- x. While the NIP law introduced through Annexure-III deals only with determination of NIP; the Authority has considered that the principles of fair comparison cannot be applied while determining injury margin. This is discriminatory, as the Designated Authority has applied principles of fair comparison in several investigations in the past and there is no need to discriminate against the present domestic industry.
- xi. Authority has wrongly considered that addition of freight is an issue concerning determination of non injurious price (NIP). Rather it is an issue of fair comparison.
- xii. There is no legal basis for the conclusion, as Annexure-III is restricted only to determination of NIP and does not deal with determination of injury margin. Principles of fair comparison require the Designated Authority to compare the domestic industry prices with import prices in a fair manner. The way the domestic industry is facing competition from imports and the level at which the domestic industry is facing competition from imports cannot be ignored. Principles of fair comparison enshrined in Annexure-I are suggestive of the principles that needs to be followed for determination extent of injury or injury margin. in the context of determination of dumping margin.
- xiii. The Authority should wait for outcome of the Writ petition, wherein the case is now listed for final hearing on 3rd Oct., 2016. The time limit provided under Rule 17 is 18 months from the date of initiation and therefore significant time is available to the Authority for completing this investigation.
- xiv. Authority has wrongly applied principle given in annexure III and has drastically reduced the "NIP" without disclosing any circumstances.
- xv. Annexure-III does not bar consideration and application of principles of fair comparison for determination of injury margin when annexure-III restricts itself to only NIP determination

Examination by the Authority

92. The post disclosure comments made by the petitioners, domestic industries and other interested parties, considered relevant by the Authority, are examined as below:

- i. As regards the contention of some interested parties that no effective opportunity of hearing was given, the Authority notes that in accordance with Rule 6(6) of the Anti-dumping Rules, an opportunity was provided to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 1st March, 2016. The parties, which presented their views orally, were requested to file written submissions, followed by rejoinder submissions. The written submissions and the rejoinder submissions furnished by the interested parties pursuant to the oral hearing and considered relevant by the Authority, have been examined and addressed in this finding.
- ii. As regards the contention of some interested parties that the normal value determined by the authority for the subject countries is not as per the relevant legal provisions, the Authority notes that the normal values in respect of the subject countries have been determined as per the relevant Rules and consistent practice in the DGAD and the methodology adopted has been adequately explained in the relevant paras of this finding.
- iii. As regards the contention of the domestic industry that authority has inappropriately shifted the obligation of establishing likelihood onto the domestic industry instead of the petitioners, the Authority notes that it is the obligation of both the parties to substantiate their arguments.
- iv. As regards the contention of the domestic industry that inadequate time was provided by the Authority for comments on the disclosure statement, the Authority notes that anti-dumping investigations are time bound and have to be completed within the prescribed time frame. Nevertheless, keeping the time lines of the present case in view, adequate time was provided to the interested parties to comment on the disclosure statement. Further, it was made clear in the disclosure statement that since anti-dumping investigations are time bound, the Designated Authority shall not entertain any request for extension of time.
- v. It has been argued by the domestic industry that the dumping margin in the original investigation as well as the present MTR are positive and the dumping margin in the post POI of the present investigation is also positive. Thus, in the event of premature withdrawal of the anti-dumping duties, dumping shall not only continue but also intensify. The Authority notes that dumping per se is not actionable, unless it causes injury. Dumping of any magnitude has no relevance under the anti-dumping law as long as it does not cause injury to the domestic industry.
- vi. As regards the contention of the domestic industry that Authority should differentiate on transaction by transaction basis dumped and injurious import volumes from un-dumped and non-injurious ones, the Authority notes that the suggested action may amount to zeroing and therefore cannot be encouraged.
- vii. The domestic industry has argued that producers in major subject countries (and in particular, China and Turkey) are holding huge unutilized capacities and in the event of withdrawal of anti-dumping duties, exports from these countries is likely to intensify at dumped prices, causing injury to the domestic industry. The Authority studied the data available in the WTA for the POI and notes that the average prices of the subject countries to third countries are higher than the NIP of the domestic industry, thereby meaning that in the event of revocation of the duty, the imports from the third countries at such prices may not cause injury to the domestic industry.
- viii. It has been argued by the domestic industry that Authority should examine whether withdrawal of anti dumping duty is likely to cause injury to the domestic industry both in respect of capacities which are already installed & already operational and capacities that have not been installed so far and which shall become operational in near future, the Authority notes that any data concerning capacity expansion should be duly reflected in the books of accounts of the domestic industry, failing which such data cannot be relied upon.
- ix. As regards the contention of the domestic industry that the NIP law introduced through Annexure-III deals only with determination of NIP and not fair comparison, the Authority notes that the NIP matter is sub-judice before the Hon'ble Delhi High Court concerning certain anti-dumping investigations and therefore may not be appropriate to be commented.
- x. As regards the contention of the domestic industry that Authority determined price attractiveness without considering relevant factors and parameters, the Authority notes that as

per the information available in the World Trade Atlas (WTA), the average landed price of the subject countries to the third countries is at a higher level than their prices to India. Therefore, in the event of revocation of the duty, the subject countries are not going to divert their goods to India in a big way since its price is not more attractive than what they otherwise receive from other countries.

- xi. As regards the contention of the domestic industry that Authority determined price attractiveness without considering relevant factors and parameters, the Authority notes that as per the information available in the World Trade Atlas (WTA), the average landed price of the subject countries to the third countries is at comparable prices and therefore in the event of revocation of the duty, the subject countries may not divert their goods to India.

93. The Authority analysed the likelihood of impact of the third country export prices of the subject countries as a source of injury to the domestic industry, if the said countries export the subject goods at that price level to India in the event of revocation of the duties. The landed price of exports from the subject countries to India has been arrived based on the weighted average FOB price of exports by the subject countries to the rest of the world as per WTA data for the POI period plus 0.5% transit insurance on FOB value, ocean freight from each of the subject countries to India, 1% port handling charges, 7.5% of Customs duty and 3% of Cess on Customs duty. From the available information, the Authority notes that the prices of the respondent exporters of Turkey to India and third countries are at comparable level. However, the weighted average FOB price available in WTA data does not seem to be reasonable as the same is found to be unusually low as compared to the prices of the respondent exporters. Therefore, injury analysis of Turkey for third country export could not be done. For Russia, the difference between the CIF price of imports from Russia to India and export price (FOB) of Russia to India of the subject goods as per WTA data have been taken for deriving freight and insurance. Accordingly, the likely injury margin of exports of subject goods by the subject countries to India on the basis of their third country landed prices during the POI, computed as above on the basis of the WTA data, has been arrived as under:

Injury Margin for third country export.						
Subject Country	UOM	Landed Price	NIP	Injury Margin	Injury Margin %	Range
Turkey	USD/MT	-	-	-	-	-
Russia	USD/MT	295.12	***	(***)	(***)	Negative

The above stated information indicates that the landed prices of the subject goods from the subject countries to India during the POI, arrived at on the basis of their third country export prices, are much higher than the non-injurious price (NIP) of the domestic industry. Therefore, the Authority notes that in the event of revocation of the anti-dumping duties, exports of the subject goods by the subject countries, at the prices at which they are exporting to third countries, would not cause injury to the domestic industry.

V. **Conclusions**

94. Having initiated and conducted the present review on the basis of an application filed by All India Glass Manufacturers' Federation (AIGMF), and having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority through the submissions made by the interested parties or otherwise as recorded in this finding and on the basis of the analysis of the state of current and likely dumping and injury and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, the Authority concludes that:

- i. Although dumping has continued despite the anti-dumping duties in force and the dumping of subject goods from the subject countries is positive during the POI, the adverse impact of the same on the volume, prices and profitability of the domestic industry is absent during the POI as well as post POI.
- ii. Both undercutting and underselling are negative during POI as well as post POI.
- iii. The injury margin is negative during POI as well as post POI.

- iv. The likely injury margin, on the basis prices of third country exports by the subject countries during the POI are also negative.
- v. Price suppression and price depression effects are absent.
- vi. All most all volume parameters and price parameters of the domestic industry are positive during POI and post POI and there is a remarkable improvement of lasting nature in the performance of the domestic industry.
- vii. Although dumping continues, neither it has caused injury to the domestic industry, nor there any likelihood of causing injury in the event of revocation of the anti-dumping duties.

The Authority, therefore, concludes that if the anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries are removed, the injury to the domestic industry is not likely to recur.

W. Recommendation

95. Having concluded that there is a remarkable improvement in the performance of the domestic industry and there is no likelihood of recurrence of injury on account of dumped imports of the subject goods from the subject countries if the duties are revoked, the Authority holds that there is no need for continued imposition of the anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating or exported from the subject countries, and the same is required to be withdrawn.

96. The Authority had earlier recommended imposition of anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, vide Final Findings Notification No. 14/17/2010-DGAD dated 17th February, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary Part I, Section I and the definitive duties imposed by the Central Government vide Notification No., 34/2012-Customs (ADD) dated 3rd July, 2012. In view of the above position, the Authority considers it necessary and recommends revocation of the anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

X. Further Procedures

97. An appeal against the order of the Central Government arising out of this Final Finding Notification shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

A.K. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority